चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 10 अगस्त-16 अगस्त 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

भारतीय सेना की चूक

सेना में नेपाली नक्सली की भर्ती

नेपाल में माओवादी गुरिल्ला युद्ध में अग्रणी रहा यंग कम्युनिस्ट लीग का कमांडर रोम बहादुर खत्री भारतीय सेना में नेपाली माओवादियों को भर्ती कराने में सबसे अधिक सक्रिय रहा है. नेपाल में सत्ता मिलने के बाद बड़ी तादाद में हथियारबंद माओवादियों ने समर्पण किया था. उन्हें सेना की बैरकों में रखा गया था. उन माओवादियों को आत्मसमर्पण के समय आश्वासन दिया गया था कि उन्हें नेपाल की नियमित सेना में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इससे नाराज माओवादियों के फिर से हथियार उठा लेने की आशंका बनने लगी. फिर नेपाली माओवादी संगठन यंग कम्युनिस्ट लीग के नेता रोम बहादुर खत्री जैसे कट्टर माओवादी कमांडरों ने नेपाली माओवादियों को भारतीय सेना में भर्ती कराने का बीड़ा उठाया.

प्रभात रंजन दीन

जालसाजी और फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाने का देश में सिलसिला चल पड़ा है. व्यापमं घोटाले की कड़ियां केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई अन्य राज्यों से भी जुड़ी हुई हैं. नौकरियों में उत्तर प्रदेश का घोटाला दर घोटाला सुर्खियों में है. यूपी में पुलिस की भर्ती में घोटाला परम्परागत कर्मकांड की तरह हो गया है. घोटालों से अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना की नियुक्तियां भी अछूती नहीं हैं. चौथी दुनिया के 06 जुलाई से 12 जुलाई के अंक में आपने पढ़ा कि पिछड़ी जाति के लोग किस तरह अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र लेकर अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो रहे हैं. सीआरपीएफ और बीएसएफ में भर्ती हुए तकरीबन चार दर्जन लोगों की आधिकारिक तौर पर शिनाख्त हुई, जो दलित बन कर भर्ती हो गए थे. जिनकी पहचान हुई, उनमें से अधिकांश लोग यादव जाति के पाए गए. इसी तरह फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नियमित सेना में भी भर्तियां हो रही हैं. जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी संख्या नगण्य है. इसका सबसे संवेदनशील पहलू है भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में गोरखाओं के नाम पर नेपाल से भागे हुए माओवादियों की भर्ती. नेपाली माओवादियों की भारतीय सेना में भर्ती कराने में लखनऊ में रह रहे नेपाली दलाल, पूर्व सैनिक और नेपाल के कुछ माओवादी नेता सक्रिय हैं. भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ है. गोरखाओं की भर्ती का सबसे बड़ा कमांड भी यही है. लखनऊ के कुछ स्कूल नेपाल से आने वाले युवकों को अपने यहां से फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं और यहीं से उन्हें निवास का प्रमाण पत्र भी मिल जाता है और उन्हें बड़े आराम से सेना की वर्दी मिल जाती है. भर्ती महकमे के अधिकारी यह भी तस्दीक नहीं करते कि अभ्यर्थी ने अपना पता क्या लिखाया है. कुछ भर्तियां तो ऐसी भी सामने आईं, जिसमें अभ्यर्थियों ने कर्नल स्तर के अधिकारी के घर का ही पता दे डाला और उसकी छानबीन भी नहीं हुई. एक ही कर्नल के घर का पता कई अभ्यर्थियों ने लिखवाया और उसे सेना में भर्ती भी कर लिया गया. भारतीय सेना के गोरखा रेजीमेंट में भर्ती हुए कई नेपाली माओवादी सत्ता संघर्ष में हथियारबंद कैडर के रूप में सक्रिय थे. उन्होंने बाकायदा नेपाली सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और बाद में वे नेपाली सेना की बैरकों से भाग निकले थे. फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सेना में भर्ती होने के कुछ मामले लगातार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पैसे का इतना बोलबाला है कि सैन्य तंत्र भी नाकाबिल साबित होता जा रहा है.

सेना में भर्ती हो गए ये माओवादी

- संतोष थापा - 14 गोरखा रेजिमेंट
- सरजू रिमाल - गोरखा रेजिमेंट
- रमाकांत शर्मा - गोरखा रेजिमेंट
- रमेश राणा - गोरखा रेजिमेंट नंबर-एलयूजीडी-1088
- सूर्य बहादुर थापा - गोरखा रेजिमेंट
- वीरेंद्र थापा - गोरखा रेजिमेंट
- इंद्र बहादुर तमांग - 11 गोरखा रेजिमेंट
- बलराम गुरुंग - गोरखा रेजिमेंट
- रमेश छेत्री - खत -9 गोरखा रेजिमेंट
- रमेश छेत्री (2) - खखख -9 गोरखा रेजिमेंट
- सुरेश खत्री - नॉन कॉम्बैटेंट दस्ते में भर्ती
- संतोष बहादुर खत्री - खखख-9 गोरखा रेजिमेंट
- भोजराज बहादुर खत्री - 17 जैक राइफल्स

भारतीय सेना में नेपाल के माओवादियों की भर्ती के बारे में जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कई सिपाहियों के नाम और उनके असली पते तक की पुष्टि हो गई है. गोरखा रेजीमेंट की विभिन्न बटालियनों में माओवादियों की बाकायदा पोस्टिंग भी हो चुकी है. कार्रवाई के नाम पर सेना भर्ती की प्रक्रिया में थोड़ा रद्दोबदल किया गया, लेकिन जो भर्ती हो गए, उन्हें पकड़ने में सेना ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. माओवादियों की लखनऊ, वाराणसी व कुछ अन्य भर्ती केंद्रों पर बहाली हुई और उन्हें ट्रेनिंग के बाद बाकायदा सेना में शामिल कर लिया गया. यह पाया गया कि लखनऊ और आसपास के स्कूलों ने नेपाली माओवादियों को आठवीं पास के फर्जी सर्टिफिकेट प्रदान किए थे. नेपाली माओवादियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिक साबित कराया गया या उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर उन्हें सेना में भर्ती कराया गया. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हो रही भर्ती की भनक मिलने पर गोरखों की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास से दसवीं पास कर दी गई, लेकिन इस फेरबदल के पहले जिन गोरखों की नियुक्तियां फर्जी प्रमाण पत्रों पर हो गईं, वे नियमित सेना में शामिल हो गए और उनका कुछ नहीं बिगड़ा.

नेपाल में माओवादी गुरिल्ला युद्ध में अग्रणी रहा यंग कम्युनिस्ट लीग का कमांडर रोम बहादुर खत्री भारतीय सेना में नेपाली माओवादियों को भर्ती कराने में सबसे अधिक सक्रिय रहा है. नेपाल में सत्ता मिलने के बाद बड़ी तादाद में हथियारबंद माओवादियों ने समर्पण किया था. उन्हें सेना की बैरकों में रखा गया था. उन माओवादियों को आत्मसमर्पण के समय आश्वासन दिया गया था कि उन्हें नेपाल की नियमित सेना में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इससे नाराज माओवादियों के फिर से हथियार उठा लेने की आशंका बनने लगी. फिर नेपाली माओवादी संगठन यंग कम्युनिस्ट लीग के नेता रोम बहादुर खत्री जैसे कट्टर माओवादी कमांडरों ने नेपाली माओवादियों को भारतीय सेना में भर्ती कराने का बीड़ा उठाया. रोम बहादुर खत्री ने मध्य कमान मुख्यालय लखनऊ के साथ-साथ वाराणसी, बरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, गोरखपुर में अपना जाल मजबूत किया. उसने सेना के अफसरों समेत फौजी भर्ती के धंधे में लगे दलालों और

(शेष पृष्ठ 2 पर)

इस फांसी के फंदे में कई गांठ हैं | P-3

चुनावी राजनीति : जाति-धर्म के इस्तेमाल में कोई पीछे नहीं | P-4

राम नाईक ने उंगली उठाई तो राम गोपाल को गुस्सा आया | P-6

सेना में नेपाली नक्सली की भर्ती

पृष्ठ 1 का शेष

स्थानीय स्कूलों को अपने प्रभावक्षेत्र में लिया, जिनसे फर्जी प्रमाणपत्र लिए जा सकें. लखनऊ में खत्री को एक ऐसा आदमी भी मिल गया, जो भर्ती में दलाली करता था और हाईकोर्ट परिसर में टाइपिंग का काम भी करता था. अब वह वकील बन चुका है.

इस गिरोह ने सात-आठ साल तक नेपाली माओवादियों की भारतीय सेना में खूब भर्तियां कराईं. नेपाल से आने वाले माओवादियों को आठवीं क्लास पास का प्रमाणपत्र देने में लखनऊ के कई स्कूल आगे रहे और राष्ट्रद्रोह के एवज में पैसे कमाते रहे. इनमें बालागंज के कैम्पबेल रोड स्थित स्कूल, आनंद नगर स्थित एक स्कूल, उदयगंज स्थित एक स्कूल, माल में रहिमाबाद रोड स्थित एक स्कूल, इटौंजा रोड स्थित एक स्कूल अव्वल हैं. 'चौथी दुनिया' के पास इन स्कूलों के नाम भी हैं, लेकिन सेना ने छानबीन की कार्रवाई में व्यवधान न पड़े, इसके लिए उन स्कूलों का नाम प्रकाशित नहीं करने का आग्रह किया. हालांकि छानबीन में कोई उल्लेनीय प्रगति नहीं हुई है. लखनऊ और लखनऊ से बाहर के ऐसे कई स्कूल हैं, जहां नेपाली युवकों को अपने स्कूल का छात्र बताया गया और आठवीं क्लास पास का प्रमाणपत्र देकर उनकी वैधता पर मुहर लगा कर राष्ट्र के साथ द्रोह किया गया. लखनऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी जैसे कई जिलों की प्रशासनिक इकाइयां भी इस देश विरोधी हरकत में शामिल हैं, जिन्होंने नेपालियों को यहां का स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रदान किया और इस आधार पर माओवादियों ने सेना में नौकरी पा ली. डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने वाली प्रशासनिक इकाइयों ने पता का सत्यापन (ऐड्रेस वेरिफिकेशन) कराने की भी जरूरत नहीं समझी. बलराम गुरुंग नाम के निपट अनपढ़ नेपाली ने स्थानीय स्कूल से आठवीं पास का फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किया और अपना पता 28/बी, आवास विकास कॉलोनी, माल एवेन्यु, लखनऊ लिखा दिया. बलराम गुरुंग मई 2010 में सेना में भर्ती होकर गोरखा रेजीमेंट में तैनाती पर भी चला गया. उसके आधिकारिक दस्तावेजों में बाकायदा माल एवेन्यु का पता दर्ज है. जब इस ऐड्रेस की छानबीन की गई तो पता चला कि वह घर सेना के ही एक कर्नल साहब का है. कर्नल साहब अब सेना से रिटायर हो चुके हैं. उनका नाम कर्नल अजित सिंह है. जब कर्नल साहब से सम्पर्क साधा गया तो उन्होंने कहा, 'मुझे क्या पता कि किसने मेरे घर का ऐड्रेस लिखा दिया! किसी ने मुझसे पूछताछ करने की जरूरत भी नहीं समझी. मैं किसी बलराम गुरुंग को जानता भी नहीं.'

सनसनीखेज तथ्य यह है कि माओवादी गुरिल्ला कमांडर व यंग कम्युनिस्ट लीग के नेता रोम बहादुर खत्री ने भारतीय सेना में जिन माओवादियों को भर्ती कराया, वे उस तक सेना की सूचनाएं पहुंचाते हैं. रोम बहादुर खत्री ने अपने दो बेटों संतोष बहादुर खत्री और भोजराज बहादुर खत्री को भी भारतीय सेना में भर्ती करा दिया है. संतोष बहादुर खत्री खखख-9 गोरखा रेजीमेंट में भर्ती है और भोजराज बहादुर खत्री 17वीं जैक राइफल्स में भर्ती है. रोम बहादुर खत्री का एक बेटा भोजराज बहादुर खत्री पहले नेपाली सेना में था. तीन साल तक नेपाली सेना में रहते हुए वह माओवादियों के लिए मुखबिरी करता था. भोजराज की मुखबिरी पर माओवादियों ने नेपाल सेना की कई युनिटों पर हमले किए थे. ऐसे ही एक हमले में माओवादियों ने नेपाली सैनिकों को मारा, हथियार लूटे, लेकिन भोजराज को वहां से भगा दिया गया. नेपाली सेना से भागा हुआ वही माओवादी बाकायदा भारतीय सेना के गोरखा रेजीमेंट में नौकरी कर रहा है. माओवादी कमांडर खत्री ने अपने भतीजे सुरेश बहादुर खत्री को भी भारतीय सेना की नौकरी में लगवाया. वह भी एक कर्नल साहब के जरिए. वे कर्नल साहब फिलहाल पुणे में तैनात हैं. माओवादी कमांडर रोम बहादुर खत्री नेपाल के बरदिया जिले के तारातल गांव का रहने वाला है. वहां से उसके बारे में खुफिया जानकारियां मंगाई जा सकती हैं, लेकिन सेना की खुफिया इकाई भी भारत की मुख्यधारा में बह रही है. रोम बहादुर खत्री के दोनों बेटों, भतीजों और तमाम माओवादी काडरों की भारतीय सेना में हुई भर्ती का भी सेना अगर चाहे तो पता लगा कर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. माओवादी कमांडर के गांव के ही दो और युवकों के बारे में जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा. दीपक छेत्री फर्जी दस्तावेजों के जरिए सेना में भर्ती हो चुका है. वह खखख-9 गोरखा बटालियन में तैनात है. भर्ती की प्रक्रिया कितनी अंधी है कि दीपक छेत्री के दाहिने हाथ की वह उंगली कटी हुई है, जिससे राइफल का ट्रिगर दबाया जाता है. ऐसे सिपाही से सेना क्या काम लेती होगी, यह तो सेना ही बताए. दीपक का भाई रमेश छेत्री भी खत-9 गोरखा बटालियन में भर्ती है. यहां फिर से फर्जी पोस्टल ऐड्रेस का रोचक प्रसंग आता है, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं. रमेश छेत्री के सैन्य दस्तावेजों में 8/5 विक्रमादित्य मार्ग का पता दर्ज है. निश्चित तौर पर इसी ऐड्रेस के आधार पर उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल किया होगा. उस ऐड्रेस की भी 'चौथी दुनिया' ने छानबीन की. वह भी फर्जी पाया गया. यह पता भी कर्नल अजित सिंह के ही दूसरे घर का है. कर्नल ने कहा, 'मैं सेना से रिटायर हो चुका हूं. मैं विकलांग हूं, चल-फिर भी नहीं सकता. गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों को मेरा घर ही सटीक लगता होगा, जहां से उन्हें किसी सक्रिय प्रतिरोध की कोई संभावना नहीं दिखती होगी, लेकिन सेना के अधिकारियों को तो पते की छानबीन करनी चाहिए थी कि सिपाही के लिए भर्ती होने वाला नेपाली गोरखा सेना के किसी आला अफसर के घर का पता क्यों लिखवा रहा है, वह भी माल एवेन्यु जैसे पॉश इलाके का?' कर्नल ने कहा कि पूरे सिस्टम में ही भ्रष्टाचार की भंग पड़ी हुई हो तो और क्या होगा! दीपक छेत्री और रमेश छेत्री माओवादी कमांडर रोम बहादुर खत्री के गांव बरदिया तारातल के ही रहने वाले हैं. लिहाजा, उनके माओवादी कनेक्शन स्पष्ट हैं.

सेना में फर्जी लोगों की भर्ती का गोरखधंधा बार-बार सामने आने के बावजूद इस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है. सेना के सूत्र कहते हैं कि इस धंधे में सेना के अधिकारी ही लिप्त हैं, तो इस पर रोक कैसे लगे. खास तौर पर सेना के मध्य कमान में यह धंधा अधिक तेजी से पसरा है. अभी कुछ ही अर्सा पहले बरेली में सेना में भर्ती के लिए चयनित हो चुके 24 युवक पकड़े गए थे. खुफिया एजेंसी की सूचना अगर ऐन मौके पर नहीं मिलती तो वे भी भर्ती होकर सेना में शामिल हो चुके होते. फर्जी प्रमाण पत्रों पर बाकायदा चुने जा चुके सुखराम सिंह, जुगेंद्र सिंह, रामनिवास, महेश, पवन कुमार, सवेंद्रा सिंह, राजू कुमार, संदीप सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, संजीव कुमार, मुकेश, कासिम, हरीश कुमार अंकित, दीपक कुमार, योगेंद्र सिंह, अय्यूब खान, भूपेंद्र, अरुण शर्मा, सचिन कुमार, सत्यपाल सिंह, ओंकार सिंह, रामू यादव और संजीव कुमार के शैक्षणिक और आवासीय प्रमाण पत्र, सभी नकली पाए गए थे.

सेना में घुसपैठ कराने वाले धंधेबाजों का बाकायदा एक सिंडिकेट चल रहा है और उन लोगों ने अपने-अपने जोन बांट रखे हैं. बरेली जोन में आदेश गुर्जर का गैंग यह धंधा चला रहा है. उसके धंधे में कई रिटायर्ड फौजी अफसर शामिल हैं. इसी गैंग के जरिए बरेली, पीलीभीत, बदायूं, संभल, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी से फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चरित्र और आवासीय प्रमाण पत्र तैयार कराया जाता है. फर्जी भर्ती प्रकरण में पकड़े गए युवकों में से चार ने सेना को सबूत भी दिए कि कैसे उनसे रुपये लेकर आदेश गुर्जर गिरोह के सदस्य रिटायर मेजर आदित्य चौहान ने उन्हें बरेली में भर्ती कराया था। इन युवकों में विष्णु शर्मा राजस्थान के भरतपुर जिले के इकनहरा गांव का रहने वाला है, लेकिन उसे पीलीभीत बीसलपुर के देवरिया गांव का निवासी दिखाया गया. राहुल कुमार और हरेंद्र सिंह अलीगढ़ में टप्पल थाने के निगुना सुगना गांव के रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें पीलीभीत के बीसलपुर स्थित ईंचगांव का निवासी दिखाया गया. जीतू भी राहुल कुमार के ही गांव का रहने वाला है, जिसे राहुल की जगह दौड़ाया गया था. राहुल कानपुर की सेना भर्ती रैली में फेल हो गया था. इसीलिए उसकी जगह जीतू को दौड़ाया गया था. इस प्रकरण के बाद सेना बेफिक्र होकर बैठ गई और पुलिस ने भी हाथ ढीले कर दिए. फर्जी दस्तावेज पर भर्तियां धड़ल्ले से चलती रहीं. ग्यारह लड़के फिर पकड़े गए और सेना भी महज औपचारिकता निभाती रही. सेना के सूत्र बताते हैं कि फर्जी दस्तावेजों पर भर्ती होने के साथ-साथ किसी और के नाम पर किसी और के दौड़ने या लिखित परीक्षा में शामिल होने का धंधा निर्बाध गति से जारी है. बरेली, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी के युवक गाजीपुर, बलिया, देवरिया, हरदोई, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा जैसे दूरस्थ जिलों से हाईस्कूल और इंटर पास का सर्टिफिकेट लाकर सेना में भर्ती हो रहे हैं. अभी पिछले ही महीने ऐसे करीब सौ सर्टिफिकेट्स फिर संदेह के दायरे में आए, जिनकी छानबीन की जा रही है. मध्य कमान के फतेहगढ़ सैन्य ठिकाने पर भी भर्ती हो चुके 205 युवकों के फर्जी दस्तावेजों का पता चला तो उनकी ट्रेनिंग रोकी गई. कहा गया कि फतेहगढ़ भर्ती प्रकरण में फर्रुखाबाद के कई लोकवाणी केंद्रों और दलालों की पड़ताल हो रही है. पड़ताल की बात कही जा रही है, पर हो कुछ नहीं रहा है. फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजीमेंटल सेंटर के करियप्पा कॉम्प्लेक्स में बरेली सेना भर्ती बोर्ड की ओर से भर्ती की गई थी. इसमें फर्रुखाबाद के अलावा श्रावस्ती, बहराइच, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, संभल हरदोई, बलरामपुर और सीतापुर के युवक शामिल हुए थे. शारीरिक परीक्षण में चयनित अभ्यर्थियों में से कुल 640 युवकों ने लिखित परीक्षा पास की थी. उन्हें ट्रेनिंग के लिए विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में भेज भी दिया गया. बाद में खुफिया जानकारी मिलने पर छानबीन की गई तो दो सौ जवानों के प्रमाणपत्र संदिग्ध पाए गए. इनमें अनुराग यादव (कन्नौज), अनुज कुमार (बुलंदशहर), मानवीर सिंह (बुलंदशहर), अनिरुद्ध प्रताप सिंह (मैनपुरी), जयंती (मैनपुरी), गौरव सिंह राठौर (मैनपुरी), आदर्श कुमार (मैनपुरी), अखिलेश कुमार (मैनपुरी), धर्मेंद्र (आगरा), नवीन सिंह (आगरा), धर्मेंद्र सिंह (आगरा), सूरज सिंह (कानपुर देहात), नरेश सिंह (इलाहाबाद), राहुल (मथुरा) और शिवम(दिल्ली) समेत अन्य के नाम शामिल हैं.

फर्जी प्रमाण पत्र पर भर्ती हुए लोग बड़े आराम से पूरी नौकरी करके रिटायर भी हो जा रहे हैं और उसके बाद सरकार पर पेंशन का बोझ भी बढ़ा रहे हैं. जानकारी मिलने के बाद भी ऐसे फर्जी पूर्व सैनिकों की पेंशन और सुविधाएं रोकने की कोई कार्रवाई नहीं होती. सेना मुख्यालय को फैजाबाद के अजित कुमार सिंह के बारे में जानकारी भी दी गई कि फर्जी प्रमाण पत्र पर सेना में भर्ती हुआ वह शख्स रिटायर होकर पेंशन भी लेने लगा, लेकिन सेना ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसी तरह मध्य कमान क्षेत्र के अंतर्गत तीसरी बिहार बटालियन के हवलदार देवेंद्र कुमार (नंबर- 4262912 के) पर भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर सेना में नौकरी पाने और रियाटरमेंट के बाद पेंशन लेने की शिकायत है, लेकिन सेना मुख्यालय पर इस शिकायत का भी कोई असर नहीं पड़ा. ■

feedback@chauthiduniya.com

सेना में नशीली दवाएं पहुंचा रहे हैं माओवादी

नक्सलवाद से प्रभावित बिहार-झारखंड में सैन्य इकाइयों के अंदर माओवादियों की पैठ की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है. अभी कुछ ही दिनों पहले 12 जून 2015 को बिहार के गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में सेना के जवान कृष्णा राम, सेना से रिटायर्ड जवान गोपी लाल और माओवादी कमांडर इंदल भोक्ता के साथी लेखा सिंह भोक्ता को सात किलो अफीम के साथ पकड़ा गया था (चौथी दुनिया में प्रकाशित). इस वाकये से साबित हुआ कि माओवादियों की सैन्य इकाइयों तक सीधी पहुंच है. सूत्रों का कहना है कि अफीम पकड़े जाने का मामला तो एक है, जबकि इस इलाके में सेना को माओवादियों से नशीली दवाओं की खेपें लगातार मिलती रही हैं, जिसमें केवल अफीम ही नहीं, बल्कि हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं. सेना के जवानों को नशा देकर माओवादी उनसे क्या-क्या जानकारियां हासिल कर रहे हैं, इसका अनुमान लगाया जा सकता है. बिहार-झारखंड भी सेना की मध्य कमान के अंतर्गत आता है.

दिलदारी पड़ सकती है भारी

नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी आतंकवाद भारत पहुंच रहा है और नेपाल को भी अपने चंगुल में लेता जा रहा है. भारत और नेपाल की सेनाएं प्रशिक्षण में साझेदारी तो कर रही हैं, लेकिन भारतीय सेना में भर्ती के जरिए माओवादियों की जो भारी घुसपैठ हुई है, उससे निपटने की सेना के पास कोई रणनीति नहीं है. भारत में तकरीबन 50 हजार गोरखा सैनिक हैं और गोरखा रेजीमेंट की 39 बटालियनें भारत में सक्रिय हैं. नेपाल के माओवादियों की भारतीय सेना में हुई भर्तियां भविष्य में समस्याएं खड़ी कर सकती हैं. नेपाल से लगने वाली सीमा भी आफत का कारण बनने वाली है. बिहार और नेपाल की सीमा पर नक्सलियों द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर बांटे जा रहे हैं. इन पोस्टरों से भारत विरोधी भावनाएं भड़काने का काम हो रहा है. ऐसे कुछ पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं. नेपाली माओवादी भारत-नेपाल सीमा की शिनाख्त कराने वाले पुराने सीमा स्तम्भ हटा रहे हैं, जिससे सीमा की पहचान समाप्त हो जाए. माओवादियों ने ऐसे करीब साढ़े पांच सौ स्तम्भ गायब कर दिए हैं. भारत नेपाल की करीब 18 सौ किलोमीटर सीमा पर साढ़े तीन हजार से अधिक स्तम्भ लगाए गए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश का कोई अता-पता नहीं है. उत्तराखंड के नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पीलीभीत के जंगलों में माओवादी अपनी जड़ें जमा रहे हैं. भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी इन्हें काबू करने में नाकाम है. उत्तराखंड से लगी नेपाल की सीमा पर 'नो मैन्स लैंड' पर माओवादियों ने अपने घर बना लिए हैं. वहां रह रहे नेपाली नागरिक यंग कम्युनिस्ट लीग के झंडे फहराते हैं. कुछ अर्सा पहले उत्तराखंड के जगलों में माओवादियों को हथियारों की ट्रेनिंग देने वाला कमांडर पकड़ा गया था. उसका नाम प्रशांत राही है. उत्तराखंड के जंगलों में माओवादियों को प्रशिक्षण दे रहे ऐसे भारतीय कमांडरों की कोई कमी नहीं है. भारतीय सेना में नेपाली गोरखा समुदाय के जो 50 हजार से अधिक लोग भर्ती हैं, वे हर साल सात-आठ सौ करोड़ रुपए अपने परिवारों के लिए नेपाल भेजते हैं. एक लाख से अधिक गोरखा भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद नेपाल में रहते हैं. इन्हें भी 500 करोड़ से अधिक की राशि सालाना पेंशन के रूप में मिलती है. यह तादाद अगर माओवादियों के सक्रिय हितचिंतकों में तब्दील हो गई तो क्या होगा? यह अहम सवाल सामने है.

फर्जी दलित बन कर भी नौकरी पा रहे हैं नेपाली

फर्जी प्रमाण पत्र लेकर नेपाली लोग केवल सेना में ही भर्ती नहीं हो रहे हैं, बल्कि अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र लेकर वे अन्य सरकारी नौकरियों में भी घुस रहे हैं. उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में भी ऐसे दो मामले पकड़े गए. दो भाई अमित सिंह और अरुण कुमार नेपाल के खलंगा (पोस्ट : ढूलेपानी, गांव : प्यूठन) से यहां आकर अनुसूचित जाति के कोटे से सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी पा गए. शिकायत होने पर मामले की छानबीन की गई तो अरुण कुमार को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उसी फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी पाये उसके भाई अमित सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. सिंचाई विभाग में अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे अमित सिंह का आवासीय प्रमाण पत्र भी फर्जी है, क्योंकि उसमें सिंचाई विभाग की कॉलोनी का ही पता दर्ज है. सिंचाई विभाग में फर्जी नियुक्ति का यह मामला उठाने वाले व्हिसिल ब्लोअर हरपाल सिंह के उत्पीड़न का जो दौर चला, वह उनके रिटायर होने के बाद भी जारी है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 23
दिल्ली, 10 अगस्त-16 अगस्त 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अल्पसंख्य मंत्रालय अल्पसंख्यकों की आर्थिक बदहाली दूर कर रहा है

मनमोहन सिंह की पिछली यूपीए सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बड़ी-बड़ी योजनाओं का एलान किया गया था, तब भी इनका पिछड़ापन दूर नहीं हो सका. कारण था इन योजनाओं का ठीक ढंग से लागू न होना. अब केंद्र में मोदी की सरकार है, जो इन योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने का प्रयास कर रही है. चौथी दुनिया ने इन योजनाओं की ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की.

डॉ क़मर तबरेज़

भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक संस्था है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी). अल्पसंख्यक युवकों के कौशल विकास के लिए फंड जारी करने की ज़िम्मेदारी इसी संस्था की है. अपने उद्देश्यों की पूर्ति और देश में अल्पसंख्यक युवकों के कौशल विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए एनएमडीएफसी ने भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर, 2014 को मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस) की स्थापना की. मानस कार्यालय के उद्घाटन के तुरंत बाद 350 उम्मीदवारों के लिए दिल्ली के आस-पास जनरल ड्यूटी सहायक (चिकित्सा) और निहत्थे सुरक्षा गार्ड के ट्रेडों में पायलट परियोजनाओं को शुरू कर दिया गया था. ये प्रशिक्षण नागलोई, बवाना, लोनी, गुलधर (गाज़ियाबाद) क्षेत्रों में आयोजित किये गए. चौथी दुनिया ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कुछ लड़के/लड़कियों से बात करने की कोशिश की. आइए देखते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले मानस की इस परियोजना से इन युवाओं को किस तरह का लाभ मिला.

दिल्ली के लोनी क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय गज़ाला परवीन ने इसी साल मार्च-अप्रैल महीने में मानस की इस परियोजना के अंतर्गत निहत्थे सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त किया. आज वह अपने घर के पास ही एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट/कॉन्सलर की नौकरी कर रही हैं. इस काम के लिए इन्हें प्रति माह 8,000 रुपए मिलते हैं. चौथी दुनिया ने जब इनसे यह जानना चाहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले मानस की इस परियोजना की जानकारी इन्हें कैसे मिली, तो गज़ाला ने बताया कि इनके घर के पास ही टीएस स्किल एंड टेक नाम की एक ट्रेनिंग एजेंसी है, जिसे तारिक़ जमाल सिद्दीकी और सुब्रत भट्टाचार्य मिलकर चलाते हैं. इन लोगों ने गज़ाला सहित आस-पास के बहुत से अल्पसंख्यक युवाओं को अपने ऑफिस में बुलाकर सरकार की इस परियोजना के बारे में बताया. इस प्रकार गज़ाला ने वहां से सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग हासिल की. इसके बाद इसी एजेंसी ने गज़ाला को अपने यहां रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी दे दी. अब गज़ाला न केवल अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर रही हैं.

लोनी के इसी सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 21 वर्षीय मोहम्मद हारून रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड (आरबीएस) में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं. हारून ने चौथी दुनिया को बताया कि प्रशिक्षण के दौरान इन्हें सेंटर की तरफ से रोज़ 20 रुपए मिलते थे. साथ ही सभी ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों को मुफ्त में वर्दी भी दी गई थी. अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस परियोजना के अंतर्गत हर उम्मीदवार को कुल 160 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग कम्पलीट होने के बाद इन्हें नौकरी दिलवाने की ज़िम्मेदारी भी इसी ट्रेनिंग सेंटर की होती है, जहां से इन युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

मानस के द्वारा अल्पसंख्यकों को जनरल ड्यूटी सहायक (चिकित्सा) का प्रशिक्षण भी दिलवाया जाता है. चूंकि प्रशिक्षण का यह काम पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप) मॉडल के द्वारा होता है, इसलिए दिल्ली के बवाना क्षेत्र में ये ज़िम्मेदारी स्किल ट्री कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को दी गई. यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 19 वर्षीय पूजा (पुत्री सतवीर सिंह) ने चौथी दुनिया को बताया कि आजकल वह दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित पोर्टिया मेडिकल में मरीज़ों की देखभाल करती हैं. इस काम के लिए कंपनी की तरफ़ से प्रति माह इन्हें 15,000 रुपए मिलते हैं. पूजा अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले मानस की इस परियोजना से काफ़ी ख़ुश हैं और इनका कहना है कि अधिक से अधिक लड़कियों को सरकार की इस परियोजना से लाभ उठाना चाहिए.

चौथी दुनिया ने इस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम को लागू करने वाली कुछ स्टेट चैनलाइजिंग एजेन्सियों के मालिकों से बात की, तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. प्रशिक्षण एजेन्सियों के मालिक प्रशिक्षण के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के लड़के-लड़कियों का रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, लेकिन अच्छे ट्रेनर नहीं रखते, जिस कारण बहुत से बच्चे प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इसका अनिवार्य टेस्ट पास नहीं कर पाते. हेल्थ केयर की ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले बहुत से बच्चों ने चौथी दुनिया को बताया कि इन्होंने दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की सर्दी में प्रशिक्षण पूरा किया, लेकिन परीक्षा में इन्हें फेल कर दिया गया, जिसकी वजह से न तो इन्हें कोई सर्टिफिकेट मिला और न ही नौकरी, समय अलग से ख़राब हुआ. इनका यह भी कहना था कि अगर इनका दोबारा टेस्ट कराया जाये, तो वह पास होकर दिखा सकते हैं. ग़ाज़ीयाबाद की प्रशिक्षण एजेंसी स्किल ट्री कंसलटिंग प्रा.लि. में हेल्थ केयर में जनरल ड्यूटी स्टेट की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फाइनल असेसमेंट टेस्ट में कुल 190 बच्चों ने प्रवेश लिया, जिसमें से केवल 109 ही इस परीक्षा को पास कर सके, जबकि 81 बच्चे फेल कर दिये गये. इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का फेल होना तो यही बताता है कि या तो इन बच्चों का चयन सही नहीं किया गया या फिर इनकी ट्रेनिंग के लिए अच्छा ट्रेनर नहीं रखा गया.

हमने जब इस एजेंसी के मालिक पीयूष गोयल से बात की, तो इनका व्यवहार पूरी तरह से ग़ैरजिम्मेदाराना लगा. पीयूष गोयल को यह भी मालूम नहीं कि इनकी एजेंसी से कुल कितने बच्चों ने हेल्थ केयर का प्रशिक्षण लिया है और कितने बच्चों को प्रशिक्षण के बाद नौकरी मिली है, जबकि दिल्ली के बवाना क्षेत्र में उनके द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्र के बच्चों की ओर से चौथी दुनिया को यह शिकायतें मिली हैं कि इन्हें परीक्षा में जानबूझ कर फेल कर दिया गया. अपनी पड़ताल के दौरान हमें यह महसूस हुआ कि कहीं न कहीं प्राइवेट ट्रेनिंग एजेंसियों की ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की संस्था नेशनल माइनोरिटी डेवलेपमेंट एंड फाइनांस कॉर्पोरेशन (एनएमडीएफसी) ईमानदारी से अपनी ओर से प्रशिक्षण के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल अकेडमी फॉर स्किल्स (मानस) को फंड जारी कर देता है. अब यह काम 'मानस' का है कि वह इस स्कीम को लागू करने के साथ-साथ इस पर भी नज़र रखे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है. हमने जब मौलाना आज़ाद नेशनल अकेडमी फॉर स्किल्स, दिल्ली के डायरेक्टर सुभाष चन्द्रा से इस बारे में बात की तो इन्होंने चौथी दुनिया को विश्वास दिलाया कि वह इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

एनएमडीएफसी अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए काम कर रही है- शहबाज अली

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्यरत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के प्रबंध निदेशक शहबाज अली ने चौथी दुनिया को बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में एनएमडीएफसी, नई दिल्ली द्वारा ऐसी कई पहल की गई है, जिसका आने वाले समय में देश में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास पर काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा. शहबाज अली भारतीय पी एंड टी लेखा एवं वित्त सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं. हाल ही में केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति एनएमडीएफसी में प्रबंध निदेशक (एमडी) के तौर पर की है. शहबाज अली अली ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय सरकार ने एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया है, जिससे एनएमडीएफसी की इक्विटी में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई है. इससे भविष्य में अल्पसंख्यकों के हित में और अधिक प्रभावी ढंग से अपने उद्देश्यों को पूरा करने में निगम को सहूलियत होगी. शाहबाज़ अली ने कहा की एनएमडीएफसी की योजनाएं और रियायती ऋण को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जगह-जगह पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एनएमडीएफसी के उच्च अधिकारी इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे. साथ ही मौजूद लोगों को उर्दू, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में एनएमडीएफसी की विवरणिका उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें एनएमडीएफसी द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं दिए जा रहे रियायती ऋण एवं इसको प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी दर्शायी जायेगी.

एनएमडीएफसी का मुख्य काम अल्पसंख्यकों का सामाजिक और आर्थिक विकास करने में मदद करना है, जिसके लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के इस प्रमुख निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है. इसका मुख्य इद्देश्य है कि निगम द्वारा दिए जा रहे व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रियायती दरों पर ऋण का लाभ उठा कर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग खुद अपना व्यवसाय करने में सक्षम हो सकें. एनएमडीएफसी द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाओं में टर्म लोन योजना, लघु ऋण योजना, शैक्षणिक ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना शामिल है. एनएमडीएफसी की संवर्धनात्मक योजनाओं में मार्केटिंग सहायता योजना, कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना प्रमुख है. इन योजनाओं को राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है, जो अपने राज्यों में स्थानीय सरकारी/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं की सहायता से स्व-रोज़गार एवं रोज़गार परक व्यवसायों में ज़रूरत के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं. अधिकतम छः महीने तक की अवधि वाले कोर्स के लिए प्रशिक्षण लागत 2000 रुपये प्रति उम्मीदवार है. प्रशिक्षण के दौरान हर एक उम्मीदवार को हर महीने 1000 रुपये की दर से वज़ीफ़ा भी दिया जाता है. एनएमडीएफसी द्वारा प्रशिक्षण खर्च का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है तथा बाक़ी का 10 प्रतिशत राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा दिया जाता है.

इस फांसी के फंदे में कई गांठ हैं

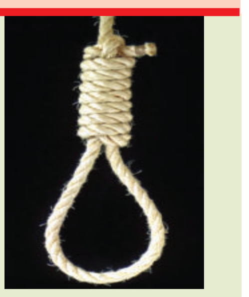

शशि शेखर

shashishekhar@gmail.com

याकूब मेमन आतंकवादी था, इसमें संदेह करने वालों की मंशा पर संदेह करना चाहिए. उसे सजा मिली और सही मिली. उसकी सजा का विरोध करने वालों की नीयत पर संदेह करने की जरूरत है. लेकिन, सवाल याकूब या उसकी फांसी का नहीं है. सवाल, इसके बहाने उठने वाले सवालों का है. उन सवालों पर चर्चा करने से पहले कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं.

राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले की एक घटना है. गढ़ी तहसील के नोखला गांव का राव जी उर्फ रामचंद्र. आपने शायद इस आदमी का नाम भी न सुना हो. 6 मई, 1993 को इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी, तीन बच्चों और एक पड़ोसी की हत्या कर दी देता है. मामला ज़िला अदालत पहुंचता है, जहां उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है. फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यह सज़ा बरक़रार रहती है. दो से ढाई सालों के बीच राव जी का मामला ज़िला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक पूरा हो जाता है. इसके बाद राव जी राजस्थान के राज्यपाल के पास दया याचिका देता है, जिसे एक जनवरी, 1996 को अस्वीकार कर दिया जाता है. तब वह राष्ट्रपति के पास फरवरी 1996 में दया याचिका भेजता है. दो से तीन महीने के भीतर वहां से भी उसकी याचिका अस्वीकृत कर दी जाती है. मई 1996 में उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है. यानी तीन साल के भीतर सारी प्रक्रिया ख़त्म.

अब इससे अलग घटनाओं पर ग़ौर कीजिए. 1999 में तमिलनाडु के मुरुगन, संथन और अरिवु को फांसी की सज़ा दी जाती है. इन पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और 18 अन्य लोगों की हत्या का दोष साबित हुआ था. इन तीनों ने 2000 में दया याचिका डाली. उनकी सजा माफ करने की अपील खुद सोनिया गांधी करती हैं. इन तीनों की दया याचिका पर जब सालों तक कोई निर्णय नहीं हुआ, तब सर्वोच्च अदालत ने इनकी प्रार्थना पर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. सवाल है, इसके लिए दोषी कौन है? बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना को माफी दिलाने के लिए शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दया याचिका लगाती है और अभी उसकी फांसी पर स्टे है. या फिर इस लिस्ट में देवेंदर पाल सिंह भुल्लर को भी जोड़ लीजिए, जिसे सजा तो फांसी की मिली है लेकिन सालों से इस सजा पर अमल नहीं हो सका है. सवाल फांसी के फंदे पर होने वाली सियासत का भी है. उस कानून का भी है, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है. सवाल यह है कि क्या सचमुच राष्ट्रपति ख़ुद अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं या इस अधिकार का इस्तेमाल भी सियासी लोग अपने फायदे के लिए करते हैं. राजीव गांधी के हत्यारों, भुल्लर एवं बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका और उन पर सरकारों का रुख़ कुछ ऐसे ही सवालों को सामने लाता है.

उपरोक्त उदाहरणों के क्या अर्थ हैं? ज़ाहिर है, ये कई सवाल पैदा करते हैं. मसलन, जब अफ़ज़ल मामले पर तत्कालीन सरकार (कांग्रेस सरकार ने) ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में (इन पंक्तियों के लेखक ने खुद यह आरटीआई डाली थी) कहा था कि सभी दया याचिकाओं को एक-एक करके और क्रम में देख रही है, तो सवाल उठता है कि 2003 में दया याचिका भेजने वाले देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की याचिका पर पहले फैसला कैसे हो गया था, जबकि राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका वर्ष 2000 से लंबित थी. दूसरा और सबसे अहम सवाल. क्या संविधान के अनुच्छेद 72, जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी सज़ायाफ्ता व्यक्ति की सज़ा को बदल सकते हैं या घटा सकते हैं, का इस्तेमाल राष्ट्रपति ख़ुद अपने विवेक से करते हैं.

दरअसल, दया याचिका की पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई गई है कि आम आदमी के लिए इसे समझना मुश्किल है. जब सज़ा पाया कोई व्यक्ति अपनी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उसे सीधे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है. फिर संबंधित राज्य सरकार अपनी राय देती है. इसके अलावा अनुच्छेद 72 में किसी भी दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए किसी समय सीमा या दिशा-निर्देश का उल्लेख नहीं है. इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि किसी की दया याचिका पर कब तक निर्णय ले लेना है, लेकिन मामला इतना सरल नहीं है. चूंकि राष्ट्रपति के पास दया याचिका से संबंधित सारे दस्तावेज़, राय एवं सुझाव इत्यादि केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार से आने होते हैं, इसलिए किसी दया याचिका पर अंतिम फैसला लेने में कितना वक्त लग सकता है, यह राष्ट्रपति पर निर्भर नहीं करता. अभी भुल्लर मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. ऐसा नहीं है कि सरकार ने ख़ुद और पूरे मन से इस मामले में फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की दया याचिका को 8 साल से लटकाने पर सवाल उठाए थे और हैरानी जताई थी. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिक्रिया दी, उसके दो दिनों बाद ही भूल्लर की दया याचिका ख़ारिज कर दी गई. ये अलग बात है कि दया याचिका खारिज होने के बाद भी अब तक भुल्लर को मिली सजा की तामील नहीं हो सकी है. अफ़ज़ल मामले में भी कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ था. पहले तो सरकार कहती रही कि मामला राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती. जबकि चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेज़ों से पता चला था कि जिस दिन अफजल की दया याचिका राष्ट्रपति सचिवालय पहुंची, उसे तत्काल गृह मंत्रालय भेज दिया गया. वहां से उसे दिल्ली सरकार को भेज दिया गया और डेढ़-दो सालों तक दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक बैठक तक नहीं की. बाद में जब यह बात सामने आई, तब आनन-फानन में दिल्ली सरकार ने फाइल आगे बढ़ाई. हालांकि इस मामले में वोट बैंक की राजनीति तो साफ-साफ दिखती है. ठीक उसी तरह, जैसे राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर भी राजनीति हुई और हो रही है. बहरहाल, फांसी पर सियासत कैसे होती है, इसका एक नमूना भुल्लर की दया याचिका ख़ारिज होते ही देखने को मिला. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह से लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल तक ने भुल्लर की फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने की वकालत की और कहा है कि वे मृत्युदंड के ख़िलाफ़ हैं. अकाली दल ने तो यहां तक कहा कि दारा सिंह पर धर्म परिवर्तन के मामले में ईसाइयों की हत्या का दोष सिद्ध हुआ था, लेकिन धार्मिकता और संवेदनशीलता के मद्देनज़र उसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था. आख़िर यही पैमाना भुल्लर के मामले में क्यों नहीं अपनाया जा सकता?

बहरहाल, अदालत मानती है कि उम्रकैद नियम है, जबकि फांसी की सज़ा एक अपवाद. ऐसी सज़ा, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में दी जाती है. अदालत तो इस उम्मीद के साथ किसी दोषी को सज़ा (मृत्युदंड) दे देती है कि इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा. लोग ग़लत काम करने से डरेंगे, लेकिन राजनीति के सियासी फंदों में ऐसे आदेश को इस तरीक़े से उलझा दिया जाता है कि सज़ा से पैदा होने वाला डर ही ख़त्म हो जाता है. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

चुनावी राजनीति : जाति-धर्म के इस्तेमाल में कोई पीछे नहीं

जगमोहन सिंह राजपूत

बिहार में चुनाव निकट है. पश्चिम बंगाल में भी चुनाव दूर नहीं है. ऐसी खबरें आने लगी हैं कि अपने आप को लगातार सेक्युलर घोषित करने वाले दल और उनके नेता वह सब कुछ अभी से आजमाने लगे हैं, जिससे वे जाति और पंथ के नाम पर वोट संग्रह कर सकें. ममता बनर्जी ने शायर इकबाल की याद का सहारा लेना प्रारम्भ कर दिया है. एक बड़ा आयोजन राज्य की उर्दू अकेडमी से करा दिया तथा मशहूर शायर इकबाल के पोते को सम्मानित भी कर दिया है. लोग इसके अर्थ निकालने लगे हैं. बिहार में लालू प्रसाद अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नीतीश के आगोश में आने के सिवाय कोई और विकल्प ढूंढ़ नहीं पा रहें हैं. वे जब देश से साम्प्रदायिक शक्तियों को तहस-नहस करने का राग छेड़ते हैं तो उन पर अब लोगों को तरस आता है. जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एकमात्र संबल बनाने में लालू जी ने कभी कोई हिचक नहीं दिखाई. वे ही तय करेंगे कि तथाकथित एमवाई अर्थात मुस्लिम-यादव समीकरण या भाईचारे के उभारने को श्रेय या अपराध में से किस खाने में रखा जाय. आगे की पीढ़ियां अवश्य याद रखेंगी कि किस प्रकार बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश को भी जातिवादी राजनीति का दूसरा बड़ा अखाड़ा बना दिया गया. भारत की राजनीति को सिद्धांतच्युत तथा मुल्यक्षरित बनाने के अथक प्रयास करनेवालों में लालू जी और नेताजी का अपना स्थान अग्रणी रहा है और इसे शायद बहनजी भी स्वीकार कर लेंगी.

आज की साठोत्तरी पीढ़ी नें जनता के आक्रोश को शब्द दिए, दिशा दी और जनता का विश्वास जीतकर मिलकर आपातकाल लगाने वालों की वह दशा की, जिसके वे हक़दार थे. सवाल है कि क्या जेपी किसी जातिवादी या साम्प्रदायिक आन्दोलन का नेतृत्व करने को कभी तैयार होते? क्या यह विडम्बना नहीं है कि गांधी के कुछ स्वघोषित उत्तराधिकारियों ने सांप्रदायिकता जमकर फैलाई और जेपी के शिष्यों ने एक कदम आगे जाकर इसमें जातिवाद को भी जोड़ दिया. उत्तर प्रदेश तथा बिहार जातिवाद तथा सांप्रदायिक मनमुटाव फैलाने के अखाड़े बना दिए गए हैं. 1976 में बिहार की युवाशक्ति के साहस और संघर्षशीलता के प्रशंसक देश भर में फैले थे. आज उस समय के नायक जातिवाद तथा सांप्रदायिकता का दलदल बिखेरकर जेपी को कैसी श्रद्धांजलि दे रहें हैं? वे लोग, जो 1950-60 के दशक में युवा थे, पूरी तरह आश्वस्त थे कि अब देश से जातिप्रथा तथा साम्प्रदायिक वैमनष्य भी सदा के लिए उसी तरह समाप्त हो जाएगा, जैसे अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया था. हर तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे नाम उभरते थे. गांधी जी की श्रेष्ठता तथा पंडित नेहरू का करिश्मा अपनी आभा हर तरफ बिखेर रहे थे. दूसरी तरफ सत्ता में पहुंचे लोगों के मन-मस्तिष्क से वे सभी मूल्य तिरोहित हो रहे थे, जिनके नैतिक बल पर देश ने आज़ादी हासिल की थी. मूल्यों का यह क्षरण लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद से हर तरफ दिखाई देने लगा था, जिसकी परिणति 25-26 जून 1976 को ऐसी हुई, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. ऐसा हुआ कैसे? यह प्रश्न अनगिनत बार उभर चुका है, मगर सामान्य जन को अपनी पैनी निगाह से यह हमेशा देखते रहना होगा की जनतंत्र का कोई पक्ष कमजोर न होने पाए. इसकी पहली जरूरत है कि लोगों की एकजुटता तथा भाईचारे को जाति और धरम के आधार पर बांटने का प्रयास करने वालों को उनका सही स्थान हर समय दिखाते रहा जाय. चुनाव- चाहे वे किसी भी स्तर पर क्यों न आयोजित हो रहें हों, इसके लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करते हैं. लोभी, लालची तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वालों को धूल चटाई जानी ही चाहिए. बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी सबसे पहले आनेवाली है. सत्ता में जो भी आये, वह जाति और धरम की राजनीति कर के न आने पाए. यह अनुभव तो सभी ने पा लिया है कि जो भी जातिवाद की राजनीति कर के आता है, उसे जातिविशेष की ओर ध्यान देना पड़ता है और इससे समानता और समता के अवसरों की जो गारंटी संविधान में दी गई है, वह चूर-चूर हो जाती है. आज राज्य सरकारों द्वारा की गई लगभग सभी नियुक्तियों पर आक्षेप लगते हैं और ये निराधार नहीं होते है, मध्य प्रदेश का व्यापम-घोटाला नई पीढ़ी के साथ किये जा रहे अन्याय का अत्यंत चिंताजनक उदाहरण है. प्रतिदिन इस प्रकार के अनुचित आचरण की खबरें आती ही रहती हैं. जातिवाद बढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाले अपने में प्रसन्न हैं, उन्हें साम्प्रदायिकता से स्वार्थ सिद्ध करने में कोई हिचक क्यों होगी?

> **आज की साठोत्तरी पीढ़ी नें जनता के आक्रोश को शब्द दिए, दिशा दी और जनता का विश्वास जीतकर मिलकर आपातकाल लगाने वालों की वह दशा की, जिसके वे हक़दार थे. सवाल है कि क्या जेपी किसी जातिवादी या साम्प्रदायिक आन्दोलन का नेतृत्व करने को कभी तैयार होते? क्या यह विडम्बना नहीं है कि गांधी के कुछ स्वघोषित उत्तराधिकारियों ने सांप्रदायिकता जमकर फैलाई और जेपी के शिष्यों ने एक कदम आगे जाकर इसमें जातिवाद को भी जोड़ दिया.**

साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद पर निर्भर बड़े राजनीतिक दल अपने चिन्हित विरोधियों को लगातार कम्युनल घोषित करते रहे हैं और लोग इसे सुन-सुन कर तंग आ चुके हैं. सच तो यह है कि वे बिना हिचक सेक्युलरिज्म का सहारा लेते रहे हैं. व्यवहारिकता में यह अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम मतदाता गोलबंद करने की कोशिश में बदल जाता है. परिपक्व मुस्लिम समुदाय इस खेल को कई बार नकार चुका है. आज भारत की आवश्यकता तो यही है कि सभी राजनीतिक दल धार्मिक तथा पंथिक सदभाव बढ़ाने के लिए गांधी का रास्ता अपनायें, लोगों को भी याद दिलाते रहें कि उन्होंने कहा था कि मैं वेदों की एकछत्रता में विश्वास नहीं करता. मैं मानता हूं कि बाइबिल, कुरान, जेन-अवेस्ता सभी उतने ही ईश्वर-प्रेरित हैं, जितने कि वेद.

क्या यह संभव नहीं है कि एक सर्वदलीय बैठक यह तय करे कि आनेवाले चुनाव में स्वेच्छा से सभी दल, जाति और मजहब की राजनीति से दूर रहेंगे और देश के सामने एक आवश्यक तथा अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे. इस प्रकार के अभियान में सबसे सशक्त तथा उत्साहपूर्ण सहयोग युवाओं से प्राप्त होगा. उनका सोच संकुचित नहीं होता है. उनके सामने विश्व-पटल खुला है. समय के साथ अस्वीकार हो चुकी प्रवृत्तियों तथा उन पर आश्रित लोगों से वे ऊब चुके हैं. वे जानते हैं कि कुछ थोड़े से लोग चुनावों को साधन-सम्पन्न वर्ग-विशेष के असामाजिक खेल में परिवर्तित कर देते हैं. वे कितने ही बड़े क्यों न हों, देश से बड़े नहीं हैं और न हो सकते हैं. भारत की आत्मा में सर्वधर्म समभाव तथा समादर बसा हुआ है. गांधी जी ने इसे आत्मसात कर लिया था. इसीलिए वे बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने हिन्दू धार्मिकता को स्वीकार कर सकते थे और सारे विश्व से कह सकते थे और सभी से अपेक्षा कर सकते थे कि वे अपने मजहब और आस्था के अनुसार अपनी पूजा पद्धति का निर्वहन करें. 1920 में यह पूछे जाने पर कि किस पुस्तक ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया, वे यह उत्तर दे सके : न्यू टेस्टामेंट! आज, भारत में विविधताओं को लेकर कोई विवाद क्यों हो और ऐसे प्रयास क्यों किये जायें, जो देश में मनमुटाव बढ़ाने का सबब बनें? विविधता की स्वीकार्यता की संस्कृति को न केवल देशव्यापी बनाना है, वरन इसे तो विश्वव्यापी बनाने में भारत को पहल करनी है. लोग यह समझते हैं, मगर नेता इसे भूल जाते हैं. लोग ही उन्हें याद दिला सकते हैं. ■

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं.)

उत्तराखंड

स्टिंग ऑपरेशन : शाहिद के बहाने हरीश पर निशाना

राजकुमार शर्मा

स्टिंग आपरेशन में फंसे मुख्यमंत्री के सचिव मोहम्मद शाहिद को भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने अफरातफरी में कागज पर वापस बुला लिया हो, लेकिन प्रदेश की हरीश सरकार अपनी सुरक्षा के लिहाज से इन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है. केंद्र की इस एकतरफा कार्रवाई से बचने के लिए प्रदेश की हरीश सरकार रास्ता तलाश रही है. आबकारी घोटाले के स्टिंग मामले में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की जिद्द का सलीके से जवाब देते हुए इनके नहले पर दहला दे मारा. हरीश जिद्द पकड़े थे कि फोरेंसिक जांच से पहले अफसर पर कार्रवाई नहीं होगी, उधर केंद्र ने शाहिद की प्रतिनियुक्ति रद्द कर इन्हें वापस बुला लिया. शाहिद को दिल्ली वापस बुलाने से हरीश सरकार में चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है, क्योंकि अभी तक तो केंद्र सरकार शाहिद के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी, अब शाहिद के बहाने हरीश पर कई निशाने साधे जा सकते हैं. मोदी सरकार की इस कार्रवाई ने इशारे-इशारे में संकेत दे दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं. यही वजह है कि स्टिंग के एक सप्ताह बाद प्रदेश सरकार ने मामले की प्रशासनिक जांच बैठा दी है. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री ओम प्रकाश को जांच अधिकारी नामित किया गया है. इसी जांच को ढाल बनाकर मोहम्मद शाहिद को प्रदेश सरकार कुछ दिन रोक सकती है. इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को पत्र भेजा जा रहा है.

जारी स्टिंग ऑपरेशन में सचिव मुख्यमंत्री को निजी शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए डील करते हुए दिखाया गया था. इसके बाद से ही केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है. इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की घेराबंदी की हुई है. प्रदेश कांग्रेस की ओर से बार-बार मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए इस्तीफे का दबाव बनाया जा रह है, जबकि मुख्यमंत्री हरीश रावत बार-बार सीडी की वास्तविकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं. चारों ओर से बढ़ते दबाव और मोहम्मद शाहिद के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने इन्हें सचिव मुख्यमंत्री, आबकारी व सुराज एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग से हटा दिया था. इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को सीडी की फॉरेंसिक जांच कराए जाने की घोषणा की थी, जिस पर भाजपा का साफ आरोप है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत एक दागी पुलिस अफसर से अपनी दाग धुलवाना चाहते हैं. इससे पहले की प्रदेश सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, केंद्र ने कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिनियुक्ति पर तैनात सचिव मोहम्मद शाहिद को वापस बुला लिया. केंद्र के कार्मिक मंत्रालय ने इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि को समाप्त कर तत्काल मोहम्मद शाहिद को केंद्र में अपनी तैनाती देने के निर्देश दिए. केंद्र की इस कार्रवाई से प्रदेश सरकार सहित नौकरशाही सकते में आ गई. केंद्र की मोदी सरकार की इस कार्रवाई से बचने के लिए प्रदेश सरकार सहित शासन के वरिष्ठ नौकरशाह इस उधेड़बुन में लगे हैं कि केंद्र के इस पैंतरे से कैसे निजात पायी जाए. वर्तमान हालत में मोहम्मद शाहिद के केंद्र में वापस लौटने को प्रदेश सरकार के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है. सूत्रों की मानें तो शाहिद की वापसी पर अड़ंगे के लिए प्रदेश सरकार जांच को आधार बना सकती है. इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सीडी प्रकरण की प्रशासनिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. प्रमुख सचिव ओम प्रकाश को जांच अधिकारी नामित किया गया है. जांच दो चरणों में होगी. पहले चरण में डीजीपी बीएस सिद्धू सीडी की वास्तविकता की जांच करेंगे. इसके बाद प्रमुख सचिव ओम प्रकाश सीडी में दिखाए गए तथ्यों की जांच करेंगे. सूत्रों की मानें तो जांच के नाम पर प्रदेश सरकार सचिव मोहम्मद शाहिद को रोके जाने के लिए केंद्र से अनुरोध कर सकती है.

> कथित आपदा राहत घोटाले और आबकारी स्टिंग ऑपरेशन से तिलमिलाई कांग्रेस को भाजपा के समय के 410 कथित घोटालों की याद आ गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 50 कांग्रेस नेताओं के दलबल के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और इन्हें ज्ञापन सौंप कर भाजपा के समय के कथित 419 घोटालों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत के नेतृत्व में तत्कालीन प्रदेश भाजपा सरकार पर 419 घोटालों का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा घोटाले भाजपा के राज में हुए थे. इन्होंने कहा कि इन घोटालों में मुख्य रूप से जमीन घोटाला था. 2010 कुम्भ मेले में तत्कालीन यूपीए सरकार से मिले 750 करोड़ रुपये का भी गोलमाल हुआ, जिसके सभी दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ वसूली की कार्रवाई होनी चाहिए. 2010 की प्राकृतिक आपदा में 600 करोड़ रुपये के गोलमाल की भी जांच होनी चाहिए. ऋषिकेष स्थित स्टुर्जिया घोटाले की भी फिर से जांच होनी चाहिए. 2007 में भाजपा की सरकार के गठन के साथ ही सरकार के मुखिया ने शराब माफियाओं के साथ सांठगांठ करके शराब के थोक व्यापार (एफएल-2) को जीएमवीएन व केएमवीएन से हटाकर निजी हाथों में सौंपकर करोड़ों रुपयों का घोटाला किया था.

देखना यह है कि प्रदेश सरकार अपनी इस रणनीति में कितनी सफल होती है. सीडी प्रकरण की प्रशासनिक जांच प्रमुख सचिव ओम प्रकाश को दी गई है. जहां तक सचिव मोहम्मद शाहिद को केंद्र वापस भेजने का सवाल है. इस संबंध में पत्रावली मुख्यमंत्री को भेज दी गई है. एन. रविशंकर, मुख्य सचिव सीडी की वास्तविकता की जांच डीजीपी को दी गई है. इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीडी में पाए जाने वाले मैटर की जांच की जाएगी. इस संबंध में मोहम्म शाहिद से भी पूछताछ होगी. साथ ही सीडी बनाने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाएगी. ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ओम प्रकाश की ओर से स्टिंग ऑपरेशन की सीडी की प्रमाणिकता की जांच के निर्देश मुझे प्राप्त हुए हैं. इस संबंध में अब वास्तविक सीडी, कैमरा आदि जरूरी चीजों को प्राप्त किया जाएगा. इसके बाद इसे फॉरेंसिक जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा. इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार कर शासन को उपलब्ध करायी जाएगी.

24 जुलाई को गुजरात सरकार ने एक पत्र केंद्र को भेजा और कहा कि इनके कैडर के 1998 बैच के आईएएस मोहम्मद शाहिद उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसके लिए केंद्र को गुजरात द्वारा दी गई एनओसी वापस ली जाती है. 25 जुलाई को केंद्र सरकार ने पीएमओ व डीओपीटी को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की बैठक बुलाकर शाहिद का उत्तराखंड प्रतिनियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया. शनिवार को केंद्रीय कार्यालयों में अवकाश होता है, इसी दिन बैठक हुई और इसी दिन शाम को डीओपीटी ने उत्तराखंड सरकार को आदेश भेज दिया. अब शाहिद डीओपीटी में जाकर ज्वॉइनिंग देंगे और इसके बाद केंद्र सरकार ही तय करेगी कि इन्हें क्या करना है. मोदी सरकार की फौरी कार्रवाई दागी आईएएस अफसर के गले की फांस बन गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार चुनाव विशेष

बिहार में चुनावी शंखनाद हाने के साथ ही सूबे की राजनीति गरमा गई है. चुनावी बिगुल बजने के साथ ही छोटी-बड़ी सभी राजनीतिक पार्टियां जनता का नब्ज टटोलने का कार्य कर रही हैं. साथ ही अपना अगामी विधानसभा चुनाव का विजन भी जनता के समक्ष रख रही हैं. छोटी से लेकर बड़ी पार्टियां चुनावी समर में कूद गई हैं. सत्ताधारी दल जदयू जहां राजद, कांग्रेस और एनसीपी के साथ महागठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम को सामने रखकर जनता के सामने जा रहे हैं. कभी लालू के चहेते सांसद पप्पू यादव इस विधानसभा चुनाव में राजद का दामन छोड़कर चुनावी समर में उतर गए हैं. जिस प्रकार वह बिहार के सभी जिलों का तूफानी दौरा कर रहे हैं, उससे यह साफ प्रतीत हो रहा है कि वे बिहार विधानसभा में अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं. इन्होंने राजद से अलग होकर अपनी नई जन अधिकार पार्टी बना ली है. इनमें से कुछ दलों के प्रमुख नेताओं ने बिहार को लेकर अपने विजन पर बात की. प्रस्तुत है इस बातचीत के अंश.

दिव्या त्रिपाठी

भ्रष्ट नेताओं की खैर नहीं : पप्पू यादव

पप्पू यादव ने बिहार विजन पर कहा कि अगर मेरी या मेरे समर्थन से सरकार बनी तो 72 घंटे के अन्दर आम आदमी मालिक बनेगा. कलेक्टर और बीडीओ राज खत्म होगा. भ्रष्ट नेता और अधिकारी को बिहार छोड़ने पर मजबूर होना होगा. तीन महीने के अन्दर बिचौलियों और दलालों को बिहार छोड़ना होगा. इस काम में अगर तीन महीने से एक दिन भी ज्यादा लग गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा. छह महीने के अन्दर हर परिस्थिति में शिक्षा का सारा सिस्टम बदल जाएगा. डोनेशन, रिएडमिशन, कोचिंग सब बंद होगा. एक साल के भीतर गांव का मेडिकल सिस्टम बदल जाएगा. जिन चीजों से आम आदमी परेशान हुआ है, वह दूर-दूर तक बिहार में नजर नहीं आएगा. गांव तय करेगा पटना की किस्मत, पटना तय नहीं करेगा गांव की किस्मत. गरीब जनता और आम आदमी के लिए हर दिन नया सवेरा होगा. बेरोजगार, नौजवान और जो बिहार के बाहर हैं, उनको एक साल के अन्दर बिहार लाने की कोशिश रहेगी. अच्छा कॉलेज, अच्छा विद्यालय एक वर्ष के अन्दर खुलेगा और गांव का सरकारी स्कूल किसी भी प्राइवेट विद्यालय से अच्छा होगा. देश की जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो आम आदमी के लिए सुलभ किया जाएगा. एक वर्ष के अन्दर सिस्टम को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा. एक वर्ष के भीतर आम लोगों को भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और न्याय का अधिकार मिलेगा. खास और आम में काई फर्क नहीं होगा. सब एक समान होंगे. तीन महीने के अन्दर भूमि विवाद को ऑनलाइन कर देंगे. बटाइदारों के लिए तीन महीनों के अन्दर कानून, बाजार से किसानों को मुक्त कर देगें और उन्हें कॉपरेटिव से जोड़ेंगे. खाद और बिज कॉपरेटिव देगा और फसल भी कॉपरेटिव ही खरीदेगा. 1990 के बाद जो भी नेता, विधायक, मंत्री, बालू माफिया, गांजा माफिया पदाधिकारी बने हैं और जिसने अकूत संपत्ति जमा की है, उसकी जांच ईडी से करवाई जाएगी. साथ ही साथ मेरी भी संपत्ति की जांच भी करवाई जाएगी. अकूत संपत्ति जमा करने वालों की संपत्ति जब्त कर अस्पताल और स्कूल में लगाया जाएगा. अमीरदास आयोग कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा. ■

गरीबों और गांवों का विकास : शकुनी

हम के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी ने अपने विजन में कहा कि जो आज गरीब है, वह और गरीब बनता जा रहा है और जो अमीर है और अमीर बनता जा रहा है. गरीबों और अमीरों के बीच एक खाई बनती जा रही है, इसको समय रहते नहीं पाटा गया तो यह बहुत बड़ा जनाक्रोश का रूप ले लेगा. हमारी सरकार बनी तो इसे हम पहली प्राथमिकताओं में रखेंगे. गरीबों के लिए अच्छे स्कूल, अस्पताल और रहने के लिए घर बनाने होंगे. बिहार से गरीबी को मिटाना, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, शिक्षकों को समान वेतन देना, सिस्टम से भ्रष्टाचार को समाप्त करना, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को सख्ती से लागू करना और बिहार से अपराध को समाप्त करना हमारा विजन है. किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना होगा. महिलाओं के लिए एमए तक की पढ़ाई को फ्री करना, कोई ट्यूशन फी नहीं, रोजगार में 35 प्रतिशत आरक्षण जरूरी है. यानी आगामी विधानसभा चुनाव में हम पार्टी गांव एवं गरीबों के विकास, राज्य के कानून व्यवस्था में सुधार एवं महिलाओं के हित को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरेगी. शकुनी चौधरी मानते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के गलत नेतृत्व के कारण बिहार काफी पीछे चला गया है. जीतनराम मांझी ने जब ताबड़तोड़ फैसले किए तो इन नेताओं से बर्दाश्त नहीं हुआ और श्री मांझी को अपमानित करके हटा दिया गया. बिहार की जनता आगामी चुनाव में महादलित के इस अपमान का बदला जरूर लेगी और नीतीश और लालू जैसे कायर नेताओं से बिहार को मुक्त करेगी. ■

युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता : चंदन

कांग्रेस के तेजतर्रार युवा नेता चंदन यादव मानते हैं कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम है. बिहार के विकास के लिए वह यहां के युवाओं और महिलाओं का पूर्ण विकास पहले हो, इसे जरूरी मानते हैं. चंदन कहते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता देने का काम किया है, इसलिए बिहार के विकास में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा. बकौल चंदन यादव कांग्रेस के खोये हुए जनाधार को वापस लाने के लिए युवाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा. वैसे युवा, जिसके अन्दर कुछ करने का जज्बा है, जो समाज, राज्य देश के हित में कार्य करना चाहते हैं, उन्हें पार्टी से जोड़ा जाएगा. महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा. उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा. चंदन यादव का मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने दो लक्ष्य हैं. पहला लक्ष्य है अपने खोये हुए जनाधार को प्राप्त करना और राज्य की राजनीति में अपने आप को मजबूत करना. दूसरा लक्ष्य है वैचारिक संकल्प और वैचारिक संघर्ष, जिसके तहत समाज को बांटने वाले को सत्ता पर काबिज होने से रोकना. बिहार में संगठन को मजबूत करने का कार्य इस विधानसभा चुनाव में किया जाएगा. इन्होंने कहा कि बिहार में जितना भी विकास का कार्य हुआ है, वह सबसे अधिक कांग्रेस के राज में हुआ है. अब बिहार की जनता को भी यह भरोसा होने लगा है कि आगे भी कांग्रेस ही इनका सहारा बनेगी और राज्य में विकास की गंगा बहाएगी, जिससे हर एक इंसान को लाभ मिलेगा. चंदन का दावा है कि इस बार बिहार में कांग्रेस चुनावी महासमर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. सभी पार्टी के नेताओं का अपना-अपना विजन है कि वो जनता के पास किस मुद्दे को रखेंगे कि जनता इनको जनाधार दे और बिहार में इनकी सरकार बने. खैर, देखना दिलचस्प होगा की इस बार बिहार की जनता किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाती है और किसको नकारती है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जनता ने अपना रुख साफ नहीं किया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मगध में विधानसभा चुनाव

एनडीए नेताओं के सामने बड़ी चुनौती

सुनील सौरभ

मगध में एनडीए के नेताओं को अपने प्रत्याशियों को जिताने की बड़ी चुनौती होगी. कहा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मगध में कोई भी दल फिसल गया तो सत्ता उसके हाथ से गई. झारखंड के अलग होने के बाद तो मगध की महत्ता बिहार विधानसभा चुनाव में और बढ़ गयी है. पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में मगध के सभी पांच सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया था, लेकिन इस समय बिहार का राजनीतिक समीकरण कुछ दूसरा था. आज बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल गया है. एनडीए के सामने राजद-जदयू-कांग्रेस का महागठबंधन खड़ा है. इसलिए एनडीए के नेताओं को मगध के पांच जिले के 26 विधानसभा क्षेत्रों में खड़े होने वाले गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की चुनौती है. मगध में दर्जन भर ऐसे नेता हैं, जो एनडीए के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें दो केन्द्रीय मंत्री तथा एक पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. राजद-जदयू-कांग्रेस के महागठबंधन के बाद मगध में एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है. 2010 के विधानसभा चुनाव में मगध के 26 सीटों में से 14 पर जदयू, 10 पर भाजपा, एक पर राजद तथा एक पर निर्दलीय का कब्जा हुआ था. तब बिहार का राजनीतिक समीकरण कुछ और था. भाजपा-जदयू का गठबंधन था तो लोजपा-राजद के साथ था. आज लोजपा भाजपा के साथ हो गई है तो जदयू राजद-कांग्रेस के साथ हो गई है. भाजपा के साथ जदयू से अलग हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) तथा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है. मगध का राजनीतिक जमीन कहा जाये तो राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन के लिए मजबूत मानी जा सकती है. जातीय वोट

मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने के बाद बाद मांझी जदयू से अलग हो अपनी पार्टी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) बना लिया और एनडीए का हिस्सा बन गये हैं. जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा हम के साथ हैं. उनके पुत्र राहुल कुमार घोशी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के बागी विधायक हैं. एक तरह से यह भी हम से जुड़े हैं. गया शहर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉ प्रेम कुमार भी एनडीए के बड़े नेता माने जाते हैं.

बैंक का समीकरण भी इस गठबंधन के लिए मगध में अच्छा माना जा रहा है. ऐसे में मगध के एनडीए नेताओं को अपने गठबंधन से खड़े होने वाले प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए कड़े प्रयास करने होंगे. नवादा के भाजपा सांसद गिरिराज सिंह तथा कराकाट के सांसद और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा केन्द्र में मंत्री हैं. जहानाबाद जिले के सुरक्षित मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी विधायक हैं. मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने के बाद बाद मांझी जदयू से अलग हो अपनी पार्टी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) बना लिया और एनडीए का हिस्सा बन गये हैं. जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा हम के साथ हैं. उनके पुत्र राहुल कुमार घोशी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के बागी विधायक हैं. एक तरह से यह भी हम से जुड़े हैं. गया शहर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉ प्रेम कुमार भी एनडीए के बड़े नेता माने जाते हैं. इन सब के अलावा आधा दर्जन के करीब अन्य ऐसे नेता हैं, जो अपने को एनडीए के अहम नेता के रूप में मानते हैं. औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, गया के सासंद हरि मांझी, रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष और जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार मगध में एनडीए के मजबूत स्तंभ माने जा रहे हैं. ऐसे में मगध के 26 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी तो हार का ठीकरा भी एनडीए के इन्हीं नेताओं पर फुटेगा. एनडीए में शामिल दल के नेता टिकट के लिए अपने-अपने समीकरण को लेकर सक्रिय हैं और संभावित क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं. यदि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिला तो एनडीए के प्रत्याशियों को भीतरघात का भी सामना करना पाड़ेगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी नेता को राजनीति में पांच साल का इंतजार करना बहुत ही कठिन होता है. ऐसे में हम नहीं तो तुम भी नहीं की राजनीति से एनडीए के प्रत्याशियों को परेशानी हो सकती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर अनिल यादव की नियुक्ति का मसला तो घोर विवादों में है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यहां तक पूछा है कि अनिल यादव में ऐसी क्या योग्यता थी कि उन्हें लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया? जातिवाद की योग्यता से ग्रसित अनिल यादव के कार्यकाल में प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की सारी मर्यादा समाप्त हो गई. पीसीएस परीक्षा तक में जबरदस्त जातिवाद हुआ, धांधलियां हुईं और हाईकोर्ट को हस्तक्षेप कर परीक्षाएं स्थगित करने तक की कार्रवाई करनी पड़ी. प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य थे, तभी सरकार ने उन्हें आयोग का सदस्य और फिर आयोग का अध्यक्ष बना दिया.

सरकारी नियुक्ति में यादवों की संख्या पर

राम नाईक ने उंगली उठाई तो रामगोपाल को गुस्सा आया

प्रभात रंजन दीन

समाजवादी पार्टी ने अब यह आधिकारिक तौर पर ज्ञापित कर दिया है कि वह यादवों की पार्टी है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण पदों पर यादव जाति के लोगों को भरे जाने के सार्वजनिक आरोपों पर बिफर उठे हैं. अब उन्होंने सीधा हथियार उठा लिया है और यादव-वाद की शिकायत करने वाले लोगों और खास तौर पर नौकरशाहों और यहां तक कि प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक पर भी असंवैधानिक हमला बोल दिया है. राम गोपाल के हाथ में यादव अधिकारियों की लिस्ट है और वे उस लिस्ट को घुमा-घुमा कर कह रहे हैं कि यादव उतने नहीं हैं, जितना कहा जा रहा है, लेकिन प्रो. राम गोपाल यादव की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के संवेदनशील विभागों के शीर्ष पदों पर स्थापित यादव जाति के विवादास्पद और अयोग्य लोगों का जिक्र नहीं है. राम गोपाल की लिस्ट में दारोगा और सिपाहियों की भर्ती में भरे गए यादवों का भी कोई जिक्र नहीं है और पीसीएस परीक्षा में यादव-मेधा अचानक उभर कर प्रदेश पर हावी हो जाने की वजहों पर भी राम गोपाल ने चुप्पी साध रखी है.

प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण पदों पर जिस तरह एक ही जाति के लोगों की तैनाती, नियुक्ति और भर्तियां की जा रही हैं, उससे प्रदेश भर में एक नकारात्मक माहौल बनता जा रहा है. आम लोगों के साथ-साथ अब कानूनविद्, नौकरशाह और राज्यपाल भी ऐसी सत्ताजनित-धांधली पर सार्वजनिक चिंता व्यक्त करने लगे हैं. तभी समाजवादी पार्टी ने खुद को सुधारने के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है. इसका बीड़ा सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने उठाया है. इसकी एक वजह यह भी है कि पीसीएस परीक्षा विवाद में राम गोपाल की बहू का नाम भी शुमार हो चुका है. यादव-वाद की शिकायतों पर भड़के राम गोपाल ने अपनी तल्खी जाहिर करने के पहले यह भी नहीं सोचा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की विवादास्पद नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने उंगली उठा दी है और सरकार से जवाब देने को कहा है.

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने पिछले दिनों बाकायदा पत्रकारों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने प्रदेश में फैली अराजकता का जिक्र किया और महत्वपूर्ण थानों में जाति विशेष (यादव) के लोगों की तैनाती पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा. राज्यपाल ने यह भी कहा कि नौकरियों में भी जाति विशेष के लोगों का ही चयन किया जा रहा है. इस पर राज्यपाल ने राज्य सरकार से जवाब-तलब करने की बात कही. इसके पूर्व प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की गैरवाजिब नियुक्ति के साथ-साथ यादवों की हो रही अंधाधुंध भर्तियों पर सार्वजनिक तौर पर उंगली उठा चुके हैं. अभी हाल ही में समूह-ग की भर्ती में भी यादव-वाद को एसपी सिंह ने उजागर किया था. सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव के पद पर तैनात एसपी सिंह ने यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को अपराधी तक करार दिया और कहा कि अनिल यादव पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसे जेल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति प्रदेश में महत्वपूर्ण पद पर बैठा है और पीसीएस और पीपीएस अफसरों की नियुक्ति कर रहा है. सिंह ने लोक सेवा आयोग के रिजल्ट पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ओबीसी को कुल 27 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन एक ही जाति विशेष (यादव) के लोगों को 21 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया. वरिष्ठ नौकरशाह ने अखिलेश सरकार को सीख भी दी कि जाति का राजनीतिकरण गैरवाजिब और अलोकतांत्रिक है.

जातिवाद के सार्वजनिक आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने अपना आपा खो दिया है. सपा के शीर्षस्थ नेता राम गोपाल यादव ने वरिष्ठ आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के बारे में कह दिया कि उनके दिमाग का स्क्रू ढीला है और राज्यपाल राम नाईक के बारे में कह डाला कि राज्यपाल को महामहिम कहने में उन्हें लज्जा आती है. हास्यास्पद स्थिति यह है कि प्रदेश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को महामहिम कहने में जिस नेता को शर्म आती है, उन्हें अपने और अपने सरकार के कृत्यों पर शर्म नहीं आती और वे यह भी कहते फिरते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं.

सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राज्य सरकार के खिलाफ जिस तरह के अमर्यादित बयान दे रहे हैं, इससे राज्यपाल पद की गरिमा खत्म हो गई है और इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को महामहिम कहकर संबोधित करना भी अब लज्जाजनक लगने लगा है. राम नाईक को राज्यपाल पद से हटाकर, 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया जाना चाहिए, ताकि वे और बेशर्मी के साथ सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर सकें. राज्यपाल का यह कहना कि उत्तर प्रदेश प्रशासन में एक जाति विशेष के वर्चस्व से वे चिंतित हैं, राज्यपाल के मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है. तो यह थी संवैधानिक, लोकतांत्रिक और मर्यादित भाषा प्रोफेसर राम गोपाल यादव की.

बिफरे राम गोपाल ने मीडिया के लिए एक लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें यादव अधिकारियों की तैनातियों का ब्यौरा है, लेकिन उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर अनिल यादव की तैनाती का जिक्र नहीं है. प्रदेश भर के थानों पर यादव प्रभारियों का जिक्र नहीं है. पीसीएस परीक्षा परिणाम में अचानक छाए यादव-वर्चस्व का जिक्र नहीं है. समूह-ग की भर्तियों में हुए भीषण जातिवाद का जिक्र नहीं है. दारोगा और सिपाहियों की भर्ती में हुए यादव-वाद का उस लिस्ट में कोई जिक्र नहीं है.

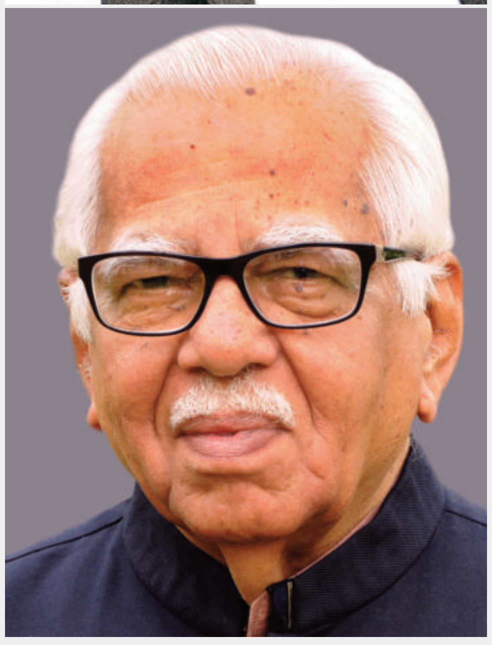

राज्यपाल को महामहिम कहने पर शर्माने वाले राम गोपाल को ऐसी लिस्ट पर झेंप नहीं आई. राम गोपाल यादव द्वारा पेश की गई लिस्ट के मुताबिक प्रमुख सचिव स्तर के 53 पदों में से केवल एक पर यादव, सचिव स्तर के 21 में से दो पदों पर यादव, विशेष सचिव के 68 पदों में से एक पर यादव, 17 मंडलायुक्तों में एक यादव, निदेशक-प्रबंध निदेशक के 28 पदों में दो यादव, 75 जिलाधिकारियों में आठ यादव, मुख्य विकास अधिकारी के 25 पदों में से छह पर यादव अधिकारी तैनात हैं. राम गोपाल की लिस्ट बताती है कि पीसीएस अधिकारियों में विशेष सचिव स्तर के 21 अफसरों में से एक यादव, 30 मुख्य विकास अधिकारियों में से तीन यादव, 127 अपर जिलाधिकारियों में नौ यादव और 32 नगर मजिस्ट्रेटों में केवल एक यादव हैं. यूपी पुलिस में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) यादव हैं. इसके अलावा राम गोपाल कहते हैं कि 75 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों में 10 यादव हैं और 79 पुलिस अधीक्षकों में तीन यादव हैं. 149 अपर पुलिस अधीक्षकों (एएसपी) में 33 यादव और 459 पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी) में 51 यादव हैं. राम गोपाल की लिस्ट में यादव थाना प्रभारियों, यादव दारोगाओं और यादव सिपाहियों की संख्या का जिक्र नहीं है, लेकिन यादव-वाद पर की गई राज्यपाल की टिप्पणियों पर राम गोपाल गुस्सा और धमकी दोनों उछालते हैं. कहते हैं कि सपा के कार्यकर्ता राज्यपाल को सड़क पर देख लेंगे.

अब समाजवादी सरकार के यादव-वाद पर आम लोगों की रिपोर्ट देखें. सपा सरकार के कार्यकाल में यश भारती सम्मान से सम्मानित 59 लोगों में 16 लोग यादव जाति के हैं. इनमें हीरालाल यादव, बंशगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, लालबचन यादव, योगेंद्र सिंह यादव, विजयपाल यादव, राजेश कुमार यादव, भगत सिंह यादव, अभिषेक यादव, दर्शन सिंह यादव, विष्णु यादव, डॉ. सीएस यादव, डॉ. राकेश यादव, अवनीश कुमार यादव, पूनम यादव, खुशवीर यादव शामिल हैं. अब पार्टी के फोरम पर आएं और यादव-वाद का विहंगम दृश्य देखें. समाजवादी पार्टी के 75 जिलाध्यक्षों में से 63 जिलाध्यक्ष यादव हैं. शिक्षा के क्षेत्र में यादव-वाद देखें. प्रदेश के 75 बेसिक शिक्षा अधिकारियों में 62 यादव हैं. प्रदेश के 67 प्रतिशत थानों में यादव थाना प्रभारी हैं. जो बीडीओ यादव जाति के हैं, उन्हें तीन-तीन, चार-चार ब्लॉकों का अतिरिक्त प्रभार मिला है. विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों में 69 प्रतिशत यादव हैं. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव हैं. अधिनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव हैं. माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अध्यक्ष रामपाल यादव हैं. उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष रामवीर यादव हैं. यूपी पुलिस के डीजीपी जगमोहन यादव हैं. हाल ही में सरकार ने जिन चार लोगों को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया है, उनमें तीन एसआरएस यादव, रामवृक्ष यादव और जीतेंद्र यादव सपा के यादव-वाद के ही उत्पाद हैं.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर अनिल यादव की नियुक्ति का मसला तो घोर विवादों में है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यहां तक पूछा है कि अनिल यादव में ऐसी क्या योग्यता थी कि उन्हें लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया? जातिवाद की योग्यता से ग्रसित अनिल यादव के कार्यकाल में प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की सारी मर्यादा समाप्त हो गई. पीसीएस परीक्षा तक में जबरदस्त जातिवाद हुआ, धांधलियां हुईं और हाईकोर्ट को हस्तक्षेप कर परीक्षाएं स्थगित करने तक की कार्रवाई करनी पड़ी. प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य थे, तभी सरकार ने उन्हें आयोग का सदस्य और फिर आयोग का अध्यक्ष बना दिया. हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या चयन में वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया था? क्या अनिल यादव के अलावा अन्य अभ्यर्थियों पर भी नियुक्ति के समय विचार किया गया था और क्या अनिल यादव की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति में योग्यता का आंकलन किया गया था? हाईकोर्ट ने खुद ही यह सवाल उठाया कि अनिल यादव के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का ठीक से सत्यापन कराए बिना नियुक्ति कैसे कर ली गई? उनमें सरकार को ऐसी क्या खूबी दिखी, जो दूसरे अभ्यर्थियों में नहीं थी? अनिल यादव की नियुक्ति की ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि एक दिन में ही, वो भी रविवार को अनिल यादव का पुलिस सत्यापन करा कर अगले ही दिन नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी कर दी गई? आयोग के अध्यक्ष के लिए कुल 83 अभ्यर्थियों का आवेदन आया था. उनमें 29 लोग ऐसे थे, जिनके पास पीएचडी तक की डिग्री है. वह रीडर या प्रोफेसर हैं, लेकिन सरकार ने सभी 83 आवेदनों पर एक ही दिन में विचार कर अनिल यादव की नियुक्ति का फैसला कर लिया. सरकार ने इस नियुक्ति के लिए किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनते ही अनिल यादव ने यादवोन्मुखी नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी, जिसके चलते इलाहाबाद समेत प्रदेश भर में काफी उपद्रव हुए और सरकार की बदनामी हुई. अनिल यादव ने आयोग की परीक्षाओं में त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू की थी, जबकि इसके पहले परिणाम आने के बाद ही आरक्षण लागू किया जाता था. नए अध्यक्ष का नया फरमान था कि प्रिलिमिनरी, मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में अलग-अलग आरक्षण लागू होगा. प्रस्तावित नई व्यवस्था से सामान्य वर्ग की अनारक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग को हिस्सा मिल गया. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की एक जाति विशेष (यादव) को आरक्षण की आड़ में नाजायज फायदा पहुंचाने का षड़यंत्र किया जा रहा है. हाईकोर्ट से 1994 की आरक्षण नियमावली के तहत पद के सापेक्ष नियुक्ति में आरक्षण दिए जाने की मांग की गई थी.

पीसीएस-2011 में इंटरव्यू में यादव अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में काफी ऊपर स्थान दिया गया. पिछड़े वर्ग के जिन 86 अभ्यर्थियों को चुना गया, उसमें 54 सिर्फ यादव जाति के अभ्यर्थी हैं. हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अवनीश पांडेय का कहना है कि पिछले तीन साल में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच हो जाए तो इसके आगे व्यापमं घोटाला फेल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुईं, उन सबमें पिछड़ी जाति में से सिर्फ यादवों का ही वर्चस्व रहा. याचिका में पीसीएस-2013 की प्रारंभिक परीक्षा में सपा महासचिव राम गोपाल यादव की बहू ऋचा अहलूवालिया का परीक्षा-केंद्र गाजियाबाद से अन्यत्र बदलने का भी जिक्र किया गया है. मैनपुरी और इटावा को परीक्षा केंद्र बनाकर सामूहिक नकल कराने का याचिका में आरोप लगाया गया है. 54 यादव अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने वाले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ओबीसी की अन्य 230 जातियों के बारे में कुछ नहीं सोचा. इसी तरह जेई सिविल के 542 पदों पर सीधी भर्ती में भी हुआ. इस भर्ती में जनरल के 415 और एससी/एसटी के 127 पद पर आरक्षण था. जब परिणाम आया तो लोग उसे देख कर हक्के-बक्के रह गए. ओबीसी का एक भी पद न होने के बावजूद 313 ओबीसी अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जबकि सामान्य वर्ग के 102 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए.

कृषि विभाग में की जाने वाली नियुक्तियों पर भी हाईकोर्ट ने इन्हीं धांधलियों के कारण रोक लगा दी थी. कृषि विभाग में 6628 भर्तियां होने वाली थीं. सामान्य और एससी-एसटी कोटे को ओबीसी अभ्यर्थियों से भरे जाने की शिकायतों के कारण अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा था. यूपी लोकसेवा आयोग को कृषि विभाग में 6628 पदों पर नियुक्ति करनी थी. इसमें सामान्य वर्ग के लिए 3616 पद, एससी उम्मीदवारों के लिए 2211, एसटी के लिए 235 और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 566 पद शामिल थे. लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को पूरा परिदृश्य ही बदला हुआ मिला. आयोग ने पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या बढ़ाकर 2030 कर दी थी, जबकि सामान्य वर्ग के पदों की संख्या 3616 से घटाकर 2515 कर दी गई. एससी वर्ग के पदों की संख्या 2211 से घटाकर 1882 और एसटी वर्ग के पदों की संख्या 235 से घटाकर 201 कर दी गई थी, लेकिन विडंबना यह है कि अनिल यादव के नेतृत्व में चलने वाले आयोग ने ओबीसी का पद 566 से बढ़ाकर 2030 कर दिया थ. ■

feedback@chauthiduniya.com

राम गोपाल के बयान पर कुछ बोलना गरिमा के अनुकूल नही : नाईक

राम गोपाल के आपत्तिजनक बयान पर प्रतिक्रिया देने से मना करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि राम गोपाल के बयान पर प्रतिक्रिया देना राज्यपाल की गरिमा के अनुकूल नहीं होगा, लेकिन प्रदेश भाजपा ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकान्त वाजपेयी ने कहा कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं और यदि वे किसी मामले में सवाल उठाते हैं तो सरकार को अनर्गल आरोप लगाने के बजाय उसे गंभीरता से लेना चाहिए. उन्होंने राम गोपाल द्वारा यादव अधिकारियों की तैनाती की सूची जारी करने को हास्यास्पद बताया और पूछा कि लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा चयन बोर्ड, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थान सेवा मंडल के अध्यक्ष कौन हैं? बाजपेयी ने कहा कि लोकसेवा आयोग में पिछले 40 माह में हुई दारोगा-सिपाही भर्ती समेत तमाम भर्तियों की सूची नाम व जिला सहित घोषित कर दे तो सरकार की कलई अपने आप खुल जाएगी. उल्लेखनीय है कि सपा सरकार की राज्यपाल राम नाईक से नाराजगी मंत्रियों के आचरण को लेकर सरकार से जवाब-तलब किए जाने से भी बढ़ी है. उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने मंत्रियों की जांच के संबंध में राज्यपाल को 24 विशेष प्रत्यावेदन सौंपे थे. इन पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा. लोकायुक्त के 24 प्रत्यावेदनों में से मात्र चार पर सरकार जवाब दे पाई. 20 प्रत्यावेदनों पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है. ■

नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया

अनंत कुमार की एंट्री और नीरा का अनोखा

शरद यादव नए उड्डयन मंत्री बने. लेकिन शरद यादव और नीरा के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं बन पाई. शायद नीरा की पिछली गतिविधियों से उन्हें पहले से ही आगाह कर दिया गया था. शरद यादव को मालूम था कि उड्डयन के हर मामले में उसकी दखल है. वह नीरा को नापसंद करते थे. इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अनंत कुमार जिन सौदों को अंतिम रूप देने वाले थे, उसे शरद यादव ने रोक दिया. इनमें एयरबस और फ्लाइंग स्कूल प्रोजेक्ट के साथ-साथ सिंगापुर एयरलाइंस का भारतीय निजी क्षेत्र के एयरलाइंस में प्रवेश शामिल था, जिससे एयर इंडिया को नुकसान उठाना पड़ता.

नीरा बड़ी सोच रखती थी. वह छोटे-मोटे असाइनमेंट से संतुष्ट नहीं थी. उसकी महत्वाकांक्षा खुद का एयरलाइंस शुरू करने की थी. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे कर्नाटक से चुन कर आये नए नागरिक उड्डयन मंत्री अनंत कुमार की सहायता की ज़रूरत थी. अनंत कुमार मार्च 1998 में मंत्री बने थे. अप्रैल 1999 में भाजपा की सरकार गिर गई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद होने वाले चुनाव में फिर से भाजपा सत्ता पर काबिज़ हो गई थी.

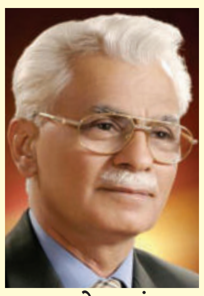

आर के आनंद

वर्ष 1996 में नीरा को एक और बिज़नेस प्रस्ताव प्राप्त हुआ. केएलएम (यूके) ने उससे कहा कि कंपनी द्वारा मोदी लुफ्त (एक विमानन कंपनी) को लीज पर दिए गए तीन विमानों को वापस हासिल करने के लिए वह केएलएम की तरफ से बातचीत करें. यह वही मौक़ा था, जब मैं पहली बार नीरा राडिया के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क में आया. बतौर वकील मैंने पूरे मामले को कामयाबी के साथ निपटाने में मदद की. नतीजा यह हुआ कि विमानन क्षेत्र में नीरा राडिया के नाम के साथ एक और उपलब्धि जुड़ गई. इस दौरान मैं नीरा के परिवार से परिचित हुआ. अब तक बाहरी लोगों को इस परिवार की अधिक जानकारी नहीं थी और इसी वजह से मैं परेशानी में भी फंसा. मैं अब तक परदे में छुपी इस कहानी को यहां और आने वाले किस्तों में बेनकाब करूंगा. ऐसा मैं बदले की नीयत से या किसी पश्चाताप के कारण नहीं करूंगा, बल्कि एक वकील और एक लेखक की नज़र से यह जानने की कोशिश करूंगा कि नीरा राडिया जैसी औरत कैसे पैदा होती है और प्राइवेट बिज़नेस में चोटी पर बने रहने के लिए किस तरह की कठोरता की आवश्यकता होती है. इस मामले का मैं अकेला शिकार नहीं था. इस पर आगे बात करेंगे. फ़िलहाल, 1999 की ओर क़दम बढ़ाते हैं. इस वर्ष केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था और भाजपा सत्ता में आई थी. अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे.

नीरा बड़ी सोच रखती थी. वह छोटे-मोटे असाइनमेंट से संतुष्ट नहीं थी. उसकी महत्वाकांक्षा खुद का एयरलाइंस शुरू करने की थी. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे कर्नाटक से चुन कर आये नए नागरिक उड्डयन मंत्री अनंत कुमार की सहायता की ज़रूरत थी. अनंत कुमार मार्च 1998 में मंत्री बने थे. अप्रैल 1999 में भाजपा की सरकार गिर गई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद होने वाले चुनाव में फिर से भाजपा सत्ता पर काबिज़ हो गई थी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय अनंत कुमार के पास ही रहा. यह मंत्रालय अक्टूबर 1999 तक उनके पास रहा. इस दौरान पर्यटन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहा.

दिल्ली के सत्ता के गलियारों से भलीभांति वाकिफ, अपने कॉन्टैक्ट के सहारे प्रबुद्ध लोगों से दोस्ती गांठने की कला में माहिर, पार्टियों में आने-जाने और बड़े लोगों से अपनी दोस्ती की नुमाइश की अहमियत समझने वाली नीरा राडिया ने अनंत कुमार के कार्यकाल के पहले ही चरण में उनके नज़दीक पहुंचने में ज़रा भी समय नष्ट नहीं किया. नीरा के लिए एक और अनुकूल परिस्थिति यह थी कि विमानन क्षेत्र में उसकी जानकारी अनंत कुमार के बड़े-बड़े नौकरशाहों से भी अधिक थी. अनंत कुमार खुद एनडीए सरकार के एक नौसिखिये मंत्री थे. उन्हें नीरा में ऐसा गुरु नज़र आया, जो उन्हें शक्तिशाली विमानन क्षेत्र के बारिकियों को समझा सकता था. यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह एक सुन्दर, लेकिन खतरनाक महिला के जाल में फंस गए थे और वह यह भी जान चुके थे कि लोगों पर उसका जादू कैसे चलता है. नीरा ने अनंत कुमार से अपनी जान-पहचान को कभी छुपाया नहीं. उसके दोस्त उन्हें असोला (दिल्ली) स्थित सुदेश फॉर्म में अक्सर एक साथ देखा करते थे. यह वह जगह थी, जहां नीरा, राव धीरज सिंह के साथ रहती थी. नीरा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साध लिया था. वह किसी भी कीमत पर

महाराष्ट्र और अनंत कुमार के घरेलू राज्य कर्नाटक की सरकारों को हेलीकॉप्टर बेचना चाहती थी. अनंत कुमार की सहायता से इन दोनों सरकारों के साथ एक सौदा तय हो गया. कमीशन के रूप में जो भारी-भरकम रक़म मिली, वह नीरा के लन्दन और चैनल आइलैंड खातों में चली गई. यह बात उसके पार्टनर धीरज सिंह ने बताई.

नीरा को एयरलाइंस मैगनेट बनने के सपने को पूरा करने का दूसरा मौक़ा बंगलौर एयर शो के दौरान मिला. ऐसे एयर शो केवल सैन्य उत्सव मनाने या करतब दिखाने के लिए नहीं होते. एरो इंडिया प्रदर्शनी अक्सर हुआ करती है, जिसमें विदेशी कम्पनियां भारतीय बाज़ार में अपने लिए जगह तलाश करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं. इस खेल में पैसा कभी रुकावट नहीं बनता. इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस शो में सोफेमा, एटीआर, यूरोकॉप्टर और एयरबस जैसी चोटी की कंपनियां हिस्सा लेती हैं. नीरा ने पहले से ही अपना पंख फैलाना शुरू कर दिया था. उसने निश्चय कर लिया था कि वह भारत सरकार को एयरबस से जहाज खरीदने पर राज़ी करेगी. विमानन के क्षेत्र में सरकारी निर्णय प्रक्रिया की जानकारी के कारण उसे मालूम था कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के फ्लीट में विस्तार के लिए विमान की खरीद होने वाली है. अनंत कुमार से उसे पता चला की दोनों एयरलाइंस के लिए फास्टट्रैक प्रक्रिया अपनाई जायेगी.

एयरबस का मामला

किसी भी दौड़ (खास तौर पर विमानन के क्षेत्र, जिसमें वह पहले से ही दूसरों पर बढ़त हासिल कर चुकी थी) में हार नहीं मानने वाली नीरा एयरबस सौदे में कूद पड़ी. उसे मालूम था कि अगर एयरलाइन्स की फ्लीट के लिए वह सरकार को बोइंग से विमान खरीदने की नीति को बदलवा कर एयरबस से विमान खरीदने पर राज़ी कर लेगी तो इसके बदले में उसे कमीशन के रूप में एक भारी रक़म मिलेगी. इस बीच विदेशी विमान निर्माता कम्पनी और नीरा की लन्दन स्थित क्राउनमार्ट इंटरनेशनल ग्रुप लिमिटेड और नेस गोल्ड लिमिटेड के बीच अस्थाई समझौते के लिए धीरज सिंह और नीरा पेरिस पहुंचे. धीरज सिंह के मुताबिक, डील पूरी होने की सूरत में मिलने वाली कमीशन की रकम को जमा करने के लिए बैंक खाता खुलवाने के उदेश्य से दोनों कई बार ज्यूरिच (स्विट्ज़रलैंड) गए. नीरा उत्साह, जोश और तेज़ गति से काम करती थी. अपने निजी कॉर्पोरेट मामलों को साफ-सुथरा रखने के लिए उसने यह सुनिश्चित किया कि लन्दन में रहने वाली उसकी बड़ी बहन करुणा, उसके और धीरज सिंह के साथ बिज़नेस ट्रिप पर जाए. वह हर कीमत पर परिवार को लूप में रखना चाहती थी.

इस दौरान सौदे की प्रक्रिया को सरकार द्वारा जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने के लिए नीरा ने घरेलू मोर्चे पर लॉबिंग तेज़ कर दी थी. सौदे का कमीशन नीरा के विदेशी खातों में भेजवाने के लिए एयर बस कंपनी की कई शर्तों में से यह भी एक शर्त थी. नीरा असावधानी से काम करने के लिए नहीं जानी जाती थी. वह अपने दो स्रोतों में से एक का राज़ दूसरे तक नहीं पहुंचने देती थी, लेकिन एयरबस सौदे के दौरान उससे चूक हो गई. इंडियन एयरलाइंस के मामले में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि एयरलाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर पीसी सेन ने उस पर अपनी आपत्ति जताई. नीरा के संरक्षक अनंत कुमार ने इसका जवाब सेन को उनके उस पद से हटा कर दिया.

जब विमान अर्जन (एक्वीजीशन) की नीति बदली जा रही थी. उस समय नीरा, अनंत कुमार के सरकारी निवास 10 पृथ्वीराज रोड अक्सर आया-जाया करती थी. खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक नीरा और अनंत कुमार अक्सर एक साथ विदेश भ्रमण पर भी गए. दरअसल, अनंत कुमार एक साधारण व्यक्तित्व के इंसान थे. वह (हाई सोसाइटी के) बातचीत और तौर-तरीके नीरा से सीखते थे.

नीरा से उनकी नजदीकी का यह नतीजा निकला कि उन्होंने विमान अर्जन की नीति बदल दी. इस नीति में तब्दीली की बुनियाद संदिग्ध थे. कहा गया कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को अधिक क्षमता और अधिक दूरी तय करने वाले विमानों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कम क्षमता वाले अधिक दूरी के विमानों की आवश्यकता है, जो बोइंग कंपनी नहीं बनाती. यह एक ऐसा समाधान था, जिसके अपनाते ही एयरबस के सारे प्रतिस्पर्धी खेल से बाहर हो गए. नीरा के लिए एक ज़बरदस्त कामयाबी थी. अब वह कह सकती थी कि वह एयरबस इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व करती है. उसने एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश, जिसकी शासन व्यवस्था एक बहुदलीय प्रणाली और स्टील-फ्रेम कहे जाने वाली नौकरशाही द्वारा चलाई जाती है, की नीतियों को अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के मुताबिक बदलने पर विवश कर दिया. यह डील लगभग 22000 करोड़ रुपयों का था, जिसमें से 10 प्रतिशत यानी 220 करोड़ रुपये नीरा के हिस्से में कमीशन के रूप में आये.

...और सपना टूट गया

अंग्रेजी में एक कहावत है कि कोई भी काम कितनी भी सावधानी से क्यों न की जाए, कोई न कोई कमी ज़रूर रह जाती है. अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार संसद में विश्वासमत हासिल करने में नाकाम रही. फलत: सरकार गिर गई. नए चुनावों की घोषणा हुई. नीरा और उसके सहयोगियों ने भाजपा को सत्ता में लाने के लिए दिन-रात एक कर दिए, ताकि सरकार बने तो फिर से अनंत कुमार नागरिक उड्डयन मंत्री बन सकें. नीरा और अनंत कुमार के बीच सौदा तय हो गया था. बतौर मंत्री अनंत कुमार की भूमिका इतनी थी कि वह एयरपोर्ट प्राधिकरण से सम्पूर्ण मैसूर एयरफील्ड कम से कम लीज पर उपलब्ध करा दें और कर्नाटक सरकार से सभी आवश्यक अनुमति दिलवा दें. नीरा की भूमिका एयरफील्ड को डेवलप करने के लिए संबंधित एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना था. बाकी बची कमियों को दूर करने के लिए धीरज सिंह ने अच्छा-खासा समय बंगलौर में बिताया. वहीं अनंत कुमार ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी कृष्ण कुमार को स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करने के लिए वहां भेजा.

इस दौरान चुनाव अभियान अपने चरम सीमा पर थे. धीरज सिंह के मुताबिक नीरा ने अनंत कुमार के चुनाव के लिए और दोबारा उड्डयन मंत्रालय में लेने के लिए मुंबई, बंगलौर और दिल्ली में बोरियां भर-भर कर पैसे दिए. ये पैसे अनंत कुमार के राजदार दिवाकर नाम के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ने वसूल किये थे.

अनंत कुमार दोबारा मंत्री बनने के बाद भी नीरा से किये गए वादे को पूरा नहीं कर सके. परेशानी यह भी थी कि नीरा से उनकी नजदीकियों ने स्कैंडल का रूप ले लिया था. उनकी पत्नी तेजस्वीनी व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत करने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी के पास गईं. वाजपेयी ने अनंत कुमार को अक्टूबर 1999 में संस्कृति एवं युवा और खेल मामलों का मंत्री बना दिया.

शरद यादव नए उड्डयन मंत्री बने. लेकिन शरद यादव और नीरा के बीच कोई केमिस्ट्री नहीं बन पाई. शायद नीरा की पिछली गतिविधियों से उन्हें पहले से ही आगाह कर दिया गया था. शरद यादव को मालूम था कि उड्डयन के हर मामले में उसकी दखल है. वह नीरा को नापसंद करते थे. इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अनंत कुमार जिन सौदों को अंतिम रूप देने वाले थे, उसे शरद यादव ने रोक दिया. इनमें एयरबस और फ्लाइंग स्कूल प्रोजेक्ट के साथ-साथ सिंगापुर एयरलाइंस का भारतीय निजी क्षेत्र के एयरलाइंस में प्रवेश शामिल था, जिससे एयर इंडिया को नुकसान उठाना पड़ता. इस सौदे को भारत के प्रतिख़ित व्यवसायी जे आर डी टाटा के वंशज रतन टाटा का समर्थन भी हासिल था. यह वही टाटा थे, जिन्होंने एयर इंडिया की नींव डाली थी. अगर अनंत कुमार उड्डयन मंत्री बने रह जाते तो बहुत संभव था कि एयर इंडिया धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती और उसकी जगह सिंगापुर एयरलाइन्स द्वारा संचालित और टाटा एम्पायर की सहायता से चलने वाली एक नई एयरलाइंस ले लेती, जिसमें नीरा की किसी न किसी तरह की मालिकाना भूमिका अवश्य होती.

एनडीए के कार्यकाल में शरद यादव एक सख्त मंत्री थे. लिहाज़ा, वह किसी तरह के राजनीतिक दबाव में नहीं आये. नीरा के एक क़रीबी सहयोगी के मुताबिक उन्हें नीरा से चिढ़ थी. अपनी खुद की एयरलाइंस के सपने को नीरा ने कभी मिटने नहीं दिया था. राडिया ने एयरलाइंस शुरू करने के लिए क्राउन एक्सप्रेस के नाम पर उसने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए एफआईपीबी की क्लियरेंस हासिल कर ली थी, लेकिन नए उड्डयन मंत्री शरद यादव ने आखिरकार नीरा के इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया.■

जारी...

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

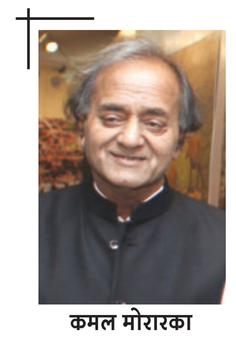
कमल मोरारका

मेरी चिंता थोड़ी अलग है. अगर ऐसे ही सबकुछ चलता रहा तो संसद को बदनाम करके तीन साल बाद यह न कहा जाने लगे कि सिस्टम नाकाम रही है और अधिनायकवादी शासन आ जाए. आखिरकार, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपने साथ बहस के लिए बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता है. वह कौन हैं? वह एक आईपीएस अधिकारी हैं और एक छोटी अवधि के लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं. उनको इस सब से क्या मतलब है? वास्तव में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वह सचमुच लेफ्टिनेंट गवर्नर या गृहमंत्री या भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के इशारे पर यह सब कर रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत बात है.

एक अलग तरह की सांप्रदायिकता फैलाने का काम हो रहा है

पिछले दिनों याकूब मेमन की फांसी की खबरें लगातार सुर्खियों में थीं. इस पर कई सवाल उठाए गए. दो पक्षों के बीच स्पष्ट विभाजन था. एक पक्ष चाहता था कि फांसी हो और दूसरा पक्ष चाहता था कि मौत की सजा माफ कर दी जानी चाहिए. लेकिन मैं इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता हूं. मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर जाना चाहता हूं. जनता यह जानना चाहती है कि क्या याकूब ने किसी वादे के बाद आत्मसमर्पण किया था. लोग इस तथ्य को जानना चाहते हैं. एक स्टोरी यह भी है कि उसके साथ नेपाल में एक डील हुई थी और यह जताने के लिए कि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया था, उसे दिल्ली से गिरफ्तार होना दिखा दिया गया. यह महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण यहां यह है कि यदि कोई वादा किया गया था तो उसे पूरा किया जाना चाहिए था.

खुफिया एजेंसी के शीर्ष अधिकारी बी रमण, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, के बारे में लोग कहते हैं कि वे कोई अथॉरिटी नहीं थे, जो कोई डील कर सकते थे. यह एक पर्याप्त जवाब नहीं है. अगर आपने कोई डील किया है और उससे पीछे हटते हैं तो वह सही नहीं है. एक व्यक्ति का जीवन या मौत शायद ही किसी देश के इतिहास में मायने रखती है, लेकिन संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं और सभी संस्थाएं दबाव में हैं. आईबी, रॉ, ये सब दबाव में हैं. मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई बेहतर सन्देश नहीं दिया. आधी रात को सुनवाई करने की इतनी क्या जल्दबाजी थी. मानो सुबह 7 बजे का कोई मुहुर्त निकला था. मानो, याकूब को 30 जुलाई की सुबह 7 बजे फांसी पर नहीं लटकाया तो फिर कभी उसे फांसी नहीं दी जा सकेगी. यह शर्म की बात है. मुझे लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा दे दी गई थी. सैद्धांतिक तौर पर सभी यूरोपीय देशों में फांसी की सजा समाप्त कर दी गई है. वक्त आ गया है कि हम भी इस दिशा में सोचें.

इसके पीछे तर्क यह है कि अगर आप जीवन नहीं दे सकते हैं तो जान लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है. मैं जानता हूं कि कट्टरपंथी इसके लिए कभी हां नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल है कि फांसी से हासिल क्या हुआ है? क्या आपको लगता है कि याकूब मेनन की फांसी अन्य आतंकवादियों को आतंकवाद फैलाने से रोक देगा, उन्हें डरा देगा. गंभीर विचार का वक्त है. यह सोचना चाहिए कि क्या मौत की सजा को खत्म कर दिया जाए?

दूसरी बात, यदि आपने एक व्यक्ति को प्रलोभन दिया है, उससे कोई सौदा किया है तो उसे पूरा किया जाए. सरकार ऐसी डील से पीछे नहीं हट सकती और न ही हटना चाहिए. बेशक, इस सरकार के आने से हमारे जैसे लोग यह मान रहे थे कि देशभर में हिन्दू-मुस्लिम दंगे होंगे, समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लेकिन पिछले 6 महीनों से मैं देख रहा हूं कि एक नई तरह की सांप्रदायिकता सामने आ रही है. मुझे लगता है कि वे स्थायी सांप्रदायिकता लाने के लिए काम कर रहे हैं. यदि वे तेजी से सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं तो प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वे धीरे-धीरे जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, जो अंत में इस प्रणाली में अवशोषित हो जाएगा. उदाहरण के लिए, उन्होंने फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में एक बहुत ही जूनियर टीवी अभिनेता को नियुक्त किया है. इसी तरह, आईसीएचआर, आईसीएसएसआर, सभी संस्थानों में अपने लोग भर रहे हैं. मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि मौजूदा सरकार अपने पसन्द के लोगों को ला रही है, लेकिन सक्षम लोग लाए जाने चाहिए. बिना अयोग्य व्यक्ति के संस्थानों का क्या हाल होगा, समझा जा सकता है. किसी ने सही सुझाव दिया है कि उनके साथ फिल्म बिरादरी के बहुत सारे लोग है. किरण खेर एक सांसद हैं, उन्हें नामित किया जाता तो लोग उसका स्वागत करते. अनुपम खेर बन सकते थे. लेकिन एक जूनियर आदमी को नियुक्त किया जाना, जिसका अनुभव इनलोगों के सामने कुछ भी नहीं है. इसका अर्थ है कि आप ऐसी संस्था का महत्व घटा रहे हैं और आप पूरे राजनीतिक परिदृश्य का अपमान कर रहे हैं. मैं नहीं जानता कि सरकार में निर्णय लेने वाला कौन है. एक फिल्म निर्माता की अध्यक्षता में सेंसर बोर्ड चल रहा है, जो जिम्मेदार तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है. यदि ये सब उनके संज्ञान में नहीं आया है तो खुद प्रधानमंत्री को इस मामले पर गौर करना चाहिए. अपनी साख खोने से सरकार को फायदा नहीं होने वाला है. आप अपना हिन्दुत्व, अपना दक्षिणपंथ दिखाएं, लेकिन तरीके से.

संसद में गतिरोध जारी है. अरुण जेटली बोल रहे हैं कि कांग्रेस बहुत बचकाना व्यवहार कर रही है. कांग्रेस बहुत चतुराई से अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के हवाले से दिए गए बयान को कोट कर रही है. जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये क्या कर रहे थे? तब जेटली और स्वराज कहते थे कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और जब उनसे संसद में अवरोध पैदा करने पर सवाल पूछा जाता था, तब कहते थे कि संसद में बाधा पैदा करने से भी देश को मदद मिलती है. अब क्या हो गया है? सिर्फ पाला बदला है. अब कांग्रेस विपक्ष में है और भाजपा सत्ता में है. अब वही काम कांग्रेस कर रही है, जो पहले भाजपा कर रही थी. दोनों तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं हैं. दोनों को अब साथ बैठना चाहिए. आखिरकार, अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में बड़ा अंतर है. लेकिन वे साथ बैठते हैं और मसले को सुलझाते हैं. इसी से लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है. अभी संसद में जो हो रहा है, वो सही नहीं है.

मेरी चिंता थोड़ी अलग है. अगर ऐसे ही सबकुछ चलता रहा तो संसद को बदनाम करके तीन साल बाद यह न कहा जाने लगे कि सिस्टम नाकाम रही है और अधिनायकवादी शासन आ जाए. आखिरकार, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपने साथ बहस के लिए बोलने का दुस्साहस नहीं कर सकता है. वह कौन हैं? वह एक आईपीएस अधिकारी हैं और एक छोटी अवधि के लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं. उनको इस सब से क्या मतलब? वास्तव में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए, लेकिन अगर वह सचमुच लेफ्टिनेंट गवर्नर या गृहमंत्री या भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के इशारे पर यह सब कर रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत बात है. अब सोचिए, क्या होगा अगर एक सेना का अधिकारी प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करना शुरू कर दे? क्या हम पाकिस्तान के रास्ते पर जा रहे हैं?

पाकिस्तान में वास्तव में यही सब तो हुआ. सबसे पहले आप निर्वाचित लोगों के नाम लेते हैं और फिर यह कह कर कि आप अनफिट हैं, सेना सत्ता संभाल लेती है. भारत में एक मजबूत चुनाव प्रणाली है. मतदाताओं ने अपनी बुद्धिमता से अरविंद केजरीवाल का चयन किया है. आप इसे नापसंद कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? कांग्रेस भी पसन्द नहीं करती तो क्या बीजेपी और कांग्रेस की सर्वसम्मति से उसे बाहर फेंक दिया जाना चाहिए.

मैं केवल उपचारात्मक कार्रवाई को ही आशा के रूप में देखता हूं. वह भी समय सीमा के भीतर. नहीं तो, यह सरकार अगले 4 साल तक सत्ता में है और इसकी कीमत हमें चुकानी होगी. मुझे लगता है कि नागरिक समाज को खड़ा हो कर आपत्ति करनी चाहिए. कोई भी केजरीवाल का समर्थन नहीं कर रहा है. सबसे बड़ा मुद्दा है कि वे एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं. उन्हें संवैधानिक दायरे के भीतर काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए. दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं. ठीक है, लेकिन अपने-अपने दायरे में एलजी और मुख्यमंत्री को आपस में सहयोग करना चाहिए. सार्वजनिक रूप से उन्हें विवाद नहीं करना चाहिए और हर छोटी बात के लिए अदालत नहीं जाना चाहिए. निश्चित रूप से पुलिस आयुक्त को तत्काल हटाया जाना चाहिए. ऐसे आदमी को नियुक्त किया जाना चाहिए, जो अपना मुंह कम खोले और अपने डंडे का इस्तेमाल दुष्कर्मियों और अपराधियों के खिलाफ करे. वे जिस भी पार्टी को चाहें, ज्वॉइन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से सिस्टम को चलाने की अनुमति नहीं मिल सकती. चलिए, बेहतर की उम्मीद करते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

अंततः छविराम मारा गया-4

जनता बागियों का समर्पण चाहती थी

मैं चार मार्च को दोपहर बारह बजे मैनपुरी पहुंचा, तब तक लाशें पुलिस लाइन में लाई जा चुकी थीं. भीड़ की वजह से उन्हें वहां से हटाना पड़ा था. हज़ारों की भीड़, जिसमें बच्चे व औरतें भी शामिल थीं, छविराम की लाश को देखने के लिए बेचैन थी. पुलिस के लोग बार-बार डंडे मारकर उसे पीछे धकेल रहे थे. छविराम की लाश को देखने की यह बेचैनी घृणा की वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरा विषाद था. मैनपुरी में छविराम की मौत का हर्ष नहीं मनाया गया, यह छविराम की लोकप्रियता का एक अद्‌भुत नमूना था. सभी की ज़ुबान पर यही था कि वह अच्छा आदमी था. जब मैं मुठभेड़-स्थल देखने गया, तो मेरे साथ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के डीआईजी बीपी सिंघल भी थे. जब मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सारा घटनाक्रम बताया, तो उन्होंने भी यही कहा कि छविराम निश्चित ही बहुत बहादुर था और बहादुरी जहां कहीं भी हो, उसकी तारीफ़ होनी ही चाहिए.

छविराम की मौत का राजनीतिक प्रभाव जल्दी ही ग्राम प्रधानों के चुनाव में दिखाई देगा. उसकी मौत का सबसे ज़्यादा खामियाजा इंका ही भुगतेगी, जिसे उसका राजनीतिक समर्थन मिलता रहा है. और जहां तक जन-साधारण में व्याप्त आतंक का सवाल है, तो गिरोह तो टूटा नहीं. जो डाकू बच गए हैं, उनमें क्रूरता ज़्यादा है, इसलिए वे नियंत्रण के अभाव में अब और ज़्यादा खूंखार हो जाएंगे. छविराम गिरोह के मथुरा सिंह, कैलाश, अजंट व कमांडर भगवान के बच जाने के कारण स्थिति में कोई खास तब्दीली नहीं आ सकती. मैनपुरी के वकीलों का कहना था कि यदि समर्पण होता, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि तब पोथी, महाबीरा व अनार सिंह भी सरकार के कब्जे में आ जाते. डाकुओं की तथाकथित तलाश में निर्दोष लोगों की हत्या का जो सिलसिला चल रहा है, उसके बंद होने की आशा भी क्षीण हो गई है. मैनपुरी पुलिस ने छविराम को समाप्त करने की बहादुरी दिखाई, इसके कारण नरेश वर्मा को पुलिस विभाग का महानिदेशक बना दिया गया है.

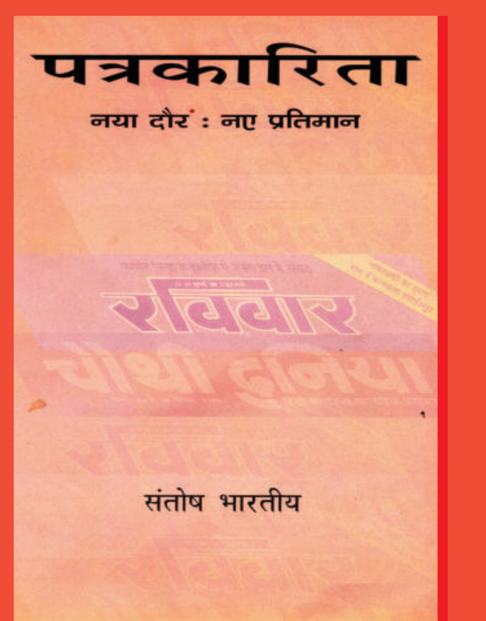

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

शाम को लगभग पांच बजे मृत सिपाही किशन चंद पांडे को अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक तुषार दत्त ने आख़िरी सलामी दी, यद्यपि उस समय लोग बेचैनी से मुख्यमंत्री व गृह राज्यमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे थे. किशन चंद पैंतीस वर्ष के थे तथा अपने पीछे एकमात्र पुत्र धर्मेंद्र को छोड़ गए हैं, जो सातवीं कक्षा का छात्र है. कहना चाहिए कि छविराम की मौत का वास्तविक श्रेय किशन चंद को ही है, जिनकी मौत ने बाकी सिपाहियों को जान की बाजी लगाने के लिए उत्तेजित किया. लगभग उसी समय नथुआपुर में शहीद इंस्पेक्टर राजपाल सिंह के माता-पिता अपने गांव गुलावटी से छविराम की लाश देखने आए. उनका कहना था कि आज उनकी आत्मा को शांति मिली है. वे लोग अपने बेटे के उन हथियारों को देखकर रो पड़े, जिन्हें छविराम मारकर छीन ले गया था. अगले दिन छविराम की पत्नी व उसके बेटे अपने नाना के साथ आए. उन्होंने दस्यु सरदार के पैरों के पास फूल चढ़ाए तथा लौट गए. पुलिस ने उन्हें लाश देने से इंकार कर दिया था. पांच मार्च को भी छविराम को देखने वालों का तांता लगा रहा. चीर-फाड़ घर का आहाता खचाखच भरा हुआ था.

चार मार्च की रात कुछ शरारती तत्वों ने मैनपुरी में एक ख़तरनाक अफवाह फैला दी. इसके अनुसार पुलिस ने छविराम के बचपन के साथी मथुरा सिंह, जो ठाकुर हैं, को फोड़कर ठाकुरों के ही एक गांव नवाटेढ़ा में खाने के साथ ज़हर खिलवा दिया तथा बाद में पकड़ कर मार दिया. दिल्ली में लोकदल के अध्यक्ष मुलायम सिंह ने भी इसी तरह की बात कही. अपने इस दावे के समर्थन में इन लोगों ने तर्क दिया कि लाशों का रंग काला था, जबकि मरने के बाद वह पीला हो जाता है. कहना न होगा कि यह सब सिर्फ़ अफवाह थी. यह सच है कि छविराम नवाटेढ़ा पहुंचना तो चाहता था, लेकिन वह वहां पहुंच ही नहीं पाया. आया वह हरैना की तरफ़ से सेंगर नदी के ऊपर था. यदि वह नवाटेढ़ा पहुंच जाता, तो निश्चित रूप से बचकर निकल जाता. जहां तक लाशों के रंग का सवाल है, तो लाशों का रंग कीचड़-धूल से सनकर काला हुआ था. सारी लाशें ग्रेनेडो व गोलियों से भरी थीं. गोली चलने की आवाज़ आसपास के सभी गांव वालों ने सुनी थी. चूंकि इस क्षेत्र में ठाकुरों व यादवों में दुश्मनी चलती है और छविराम यादव था, इसलिए इस अफवाह ने परंपरागत वैमनस्य को थोड़ा और गाढ़ा किया.

छविराम की मौत का राजनीतिक प्रभाव जल्दी ही ग्राम प्रधानों के चुनाव में दिखाई देगा. उसकी मौत का सबसे ज़्यादा खामियाजा इंका ही भुगतेगी, जिसे उसका राजनीतिक समर्थन मिलता रहा है. और जहां तक जन-साधारण में व्याप्त आतंक का सवाल है, तो गिरोह तो टूटा नहीं. जो डाकू बच गए हैं, उनमें क्रूरता ज़्यादा है, इसलिए वे नियंत्रण के अभाव में अब और ज़्यादा खूंखार हो जाएंगे. छविराम गिरोह के मथुरा सिंह, कैलाश, अजंट व कमांडर भगवान के बच जाने के कारण स्थिति में कोई खास तब्दीली नहीं आ सकती. मैनपुरी के वकीलों का कहना था कि यदि समर्पण होता, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि तब पोथी, महाबीरा व अनार सिंह भी सरकार के कब्जे में आ जाते. डाकुओं की तथाकथित तलाश में निर्दोष लोगों की हत्या का जो सिलसिला चल रहा है, उसके बंद होने की आशा भी क्षीण हो गई है. मैनपुरी पुलिस ने छविराम को समाप्त करने की बहादुरी दिखाई, इसके कारण नरेश वर्मा को पुलिस विभाग का महानिदेशक बना दिया गया है. मुख्यमंत्री को भी सिर ऊंचा कर बोलने का मौक़ा मिला है, लेकिन भविष्य में क्या छिपा है, इसका कुछ संकेत इस बात से मिलता है कि जब मैं वापस आने लगा, तो एक व्यक्ति फुसफुसा कर बोला, जाओ साब, लेकिन फिर जल्दी ही मैनपुरी आना होगा.■

क्रमशः

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सर्वोच्च न्यायालय को अंतर्विरोधों का जवाब देना चाहिए

“लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों का विद्रोह नहीं चलता और बहुसंख्यक का अधिनायकवाद नहीं चलता. लोकतंत्र में अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, संविधान के तहत एक ही तरह के अधिकार मिलते हैं और उन अधिकारों के तहत उनकी समस्याओं के निदान तलाशे जाते हैं. बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, दोनों वर्गों में लोकतंत्र को न मानने वाले दिमाग हैं और ये दिमाग यह बतलाते हैं कि उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं है, उन्हें बहुसंख्यक समाज का अधिनायकवाद पसंद है और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों में अलोकतांत्रिक दिमाग अल्पसंख्यकों को विद्रोह के लिए उकसाना अपना फर्ज समझता है, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की यह खूबी है कि दोनों तरह के दिमाग अपनी बात संपूर्ण जनता के सामने रखते रहते हैं...”

हर व्यवस्था के अपने बंधन होते हैं, अपने सवाल होते हैं. अधिनायकवादी व्यवस्था में न्याय के ऊपर सवाल नहीं उठता. अधिनायकवादी व्यवस्था में अन्याय के ऊपर सवाल नहीं उठता, क्योंकि वहां अधिनायक अगर किसी को न्याय कहता है, तो सब उसे न्याय मानते हैं और किसी को अन्याय कहता है, तो सब अन्याय मानते हैं. लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता. लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय की एक प्रक्रिया होती है और न्याय तथा अन्याय की स्पष्ट परिभाषा भी होती है. लोकतंत्र में हर समुदाय को संविधान का संरक्षण मिलता है. संविधान लोकतंत्र की गीता और कुरान है. जहां पर संविधान की व्याख्या करनी हो और जहां पर जरा भी शंका हो, वहां पर उसकी व्याख्या करने का काम सर्वोच्च न्यायालय करता है. ये सारी बातें दुनिया के हर लोकतांत्रिक देश में लागू होती हैं. हमारा देश भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है.

लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों का विद्रोह नहीं चलता और बहुसंख्यक का अधिनायकवाद नहीं चलता. लोकतंत्र में अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, संविधान के तहत एक ही तरह के अधिकार मिलते हैं और उन अधिकारों के तहत उनकी समस्याओं के निदान तलाशे जाते हैं. बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, दोनों वर्गों में लोकतंत्र को न मानने वाले दिमाग हैं और ये दिमाग यह बतलाते हैं कि उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं है, उन्हें बहुसंख्यक समाज का अधिनायकवाद पसंद है और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों में अलोकतांत्रिक दिमाग अल्पसंख्यकों को विद्रोह के लिए उकसाना अपना फर्ज समझता है, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की यह खूबी है कि दोनों तरह के दिमाग अपनी बात संपूर्ण जनता के सामने रखते रहते हैं, पर जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं, वहां पर आम जनता इन दिमागों से प्रभावित नहीं होती और चुनावों में हमेशा ऐसा फैसला देती है, जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, कमजोर नहीं.

इसके बावजूद सवाल तो खड़े होते हैं. प्रशासन के तरीके पर सवाल खड़े होते हैं, कानून बनाने के तरीके पर सवाल खड़े होते हैं, अवसरों के सामान वितरण की जगह अवसरों की असमान उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, किसी घटना की जिम्मेदारी तय करने के तरीके के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और देश में व्यवस्था चलाने के तरीके को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं. इन सवालों का उत्तर लोकतांत्रिक व्यवस्था जब तक सक्षम रूप से देती रहती है, तब तक वह व्यवस्था देश के हित में मानी जाती है. जहां व्यवस्था के सारे अंग सवालों का जवाब देना बंद कर दें या सवालों से भटकाने की कोशिश करें, वहां लोकतांत्रिक देशों में सर्वोच्च न्यायालय या न्याय व्यवस्था के ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है. न्याय व्यवस्था के ऊपर इस जिम्मेदारी का मतलब ये भी निकालना चाहिए कि देश में लोकतंत्र को बचाए रखने का आखिरी हथियार या तो जनता है या फिर न्याय व्यवस्था है.

लोकतंत्र को चलाने की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की है और दूसरी तरफ सरकार और विधायिका की है. अगर हम स्पष्ट रूप से देखने लगें कि कुछ लोगों को न्याय मिलने में जबरदस्ती अड़ंगे लगते हैं और दूसरी तरफ जानबूझकर कुछ फैसलों को इतने लंबे समय तक लटकाया जाता है. जब यह कहा जाए, चूंकि फैसला होने में देरी हुई इसलिए अब इन्हें न्याय के अनुसार दिए गए फैसले पर होने वाले अमल से बरी कर दिया जाए.

पर जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिखने लगे कि न्याय पैसे के आधार पर, राजनीतिक प्रभाव के आधार पर या धर्म के आधार पर मतभेद करने लगे, तो मानना चाहिए कि लोकतंत्र में कहीं कुछ सड़ने लगा है. और ये सड़न अगर तत्काल दूर नहीं की गई, तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने आप में निष्प्रभावी होने के रास्ते पर निकल पड़ेगी.

लोकतंत्र को चलाने की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की है और दूसरी तरफ सरकार और विधायिका की है. अगर हम स्पष्ट रूप से देखने लगें कि कुछ लोगों को न्याय मिलने में जबरदस्ती अड़ंगे लगते हैं और दूसरी तरफ जानबूझकर कुछ फैसलों को इतने लंबे समय तक लटकाया जाता है. जब यह कहा जाए, चूंकि फैसला होने में देरी हुई इसलिए अब इन्हें न्याय के अनुसार दिए गए फैसले पर होने वाले अमल से बरी कर दिया जाए. हमारे देश में पिछले दिनों ऐसे ही उदाहरण देखने को मिले, जहां पर यह शंका पैदा हुई कि राजनीति के आधार पर राजनीतिक प्रभावशीलता के आधार पर और धार्मिक असहनशीलता के आधार पर होने वाले फैसलों ने देश के एक बड़े वर्ग के अंदर असहजता पैदा करनी शुरू कर दी है. हो सकता है यह ट्रेंड स्थाई न हो, पर यह ट्रेंड अस्थाई भी नहीं है.

अफसोस की बात यह है कि इन सारे सवालों पर जहां बहुसंख्यक समाज का एक प्रभावशाली हिस्सा चुप नहीं है, बल्कि इन विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है. वहीं अल्पसंख्यक समाज में आवाजें बंद हैं और जब एक आवाज उन विसंगतियों का विरोध करती है, तो वो अल्पसंख्यकों के बाकी नेताओं को अप्रासंगिक साबित करती है और एकछत्र नेतृत्व की तरफ अल्पसंख्यकों को ले जाती है. किसी भी समाज में अकेला नेतृत्व बहुत स्वस्थ नहीं माना जा सकता, लेकिन जब बाकी लोग खामोश हों और सिर्फ एक आवाज उठे, तो अल्पसंख्यक जनता के मन में उस आवाज के लिए आदर पैदा होना आश्चर्यजनक चीज नहीं मानी जा सकती.

लोकतंत्र के भीतर उठे हुए सवाल और जिन अंतर्विरोधों का जिक्र हम कर रहे हैं, अगर इन अंतर्विरोधों के सवाल पर लोकतांत्रिक व्यवस्था या संविधान की व्याख्या करने वाला सर्वोच्च न्यायालय खामोश रहता है और इनका उत्तर नहीं देता, तब हमें मानना चाहिए कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए स्थापित व्यवस्था से बाहर भी कुछ करने की जरूरत है और ये कुछ करने का जिम्मा जहां एक तरफ बुद्धिजीवियों के ऊपर है, वहीं इसका दूसरा दायित्व पत्रकारों के ऊपर भी है. पर हमारे देश में बुद्धिजीवियों की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन पत्रकारों के बारे में मेरे मन में एक संदेह है कि उनमें कितने ऐसे हैं, जिनके मन में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सम्मान है या जो यह मानते हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चलनी चाहिए. ये शंका पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, जिस नजरिये से सवालों को देखा जा रहा है, उसे देख कर खड़ी हुई है. पर चिंताएं एक तरफ और चिंताओं से लड़ाई दूसरी तरफ. वक्त आ गया है कि हम सब सर्वोच्च न्यायालय से कहें कि वो अंतर्विरोधों के जवाब दे और अगर सर्वोच्च न्यायालय भी खामोश रहता है तो फिर व्यवस्था से इतर जनता को लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए कुछ सोचने की और करने की आवश्यकता दिखाई देती है.■

editor@chauthiduniya.com

जनता काम करने के लिए सांसद चुनती है

भारत में संसद की कार्रवाई में व्यवधान कोई नई बात नहीं है. यहां विपक्ष विरले ही मत विभाजन में विजयी होता है. भारत में सरकारें किसी विधेयक को पारित करवाने के लिए सदन के पटल पर मत विभाजन या संशोधन जैसी प्रक्रियाएं हमेशा पूरी नहीं करतीं. दरअसल, संसद के बाहर विधेयक पर बहस होती है, सुलह-सफाई होती है और बहुत जल्दबाजी में उसे पारित करा दिया जाता है. उदाहरण के लिए तेलंगाना विधेयक जो कई वर्षों तक लंबित रहा, लेकिन उसे कुछ घंटों में ही पारित करवा लिया गया. यूपीए-2 के पास बहुमत नहीं थी, लेकिन वह भूमि अधिग्रहण और लोकायुक्त जैसे प्रमुख विधेयक पारित करवा लेने में सफल रही थी.

मेघनाद देसाई

जब लेबर पार्टी ने ब्रिटेन में 1945 में पहली बार बहुमत हासिल किया था तो संसद में उसे एक मुश्किल का सामना करना पड़ा था. हालांकि हाउस ऑफ़ कॉमन्स में 150 सदस्यों के साथ उसे ठोस बहुमत हासिल थी, लेकिन हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के 750 में पार्टी के केवल 20 ही सदस्य थे. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत के बाद वहां सालिसबरी परम्परा की बुनियाद पड़ी, जिसके तहत विपक्ष ऐसे किसी विधयक को बाधित नहीं करेगा, जिसका वादा सत्ताधारी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में किया होगा. इस तरह नई आवश्यकताओं के मद्देनज़र एक पुराने अलिखित संविधान को पूरी तरह से बदल दिया गया.

भारत का पहला लिखित संविधान गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट-1935 था. यह ऐसा एक्ट था, जिस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में वर्ष 1999 तक सबसे अधिक चर्चा हुई थी. केवल हाउस ऑफ़ कॉमन्स में ही इस पर 40 लाख से अधिक शब्द बोले गए थे. इस कानून में मज़बूत राज्यों और कमज़ोर केंद्र की परिकल्पना पेश की गई थी. अगर 1942 का क्रिप्स मिशन या 1946 का कैबिनेट मिशन इस मसले को सुलझा लिया होता तो अविभाजित भारत एक मज़बूत केंद्र के संघ के बजाय एक कमज़ोर कंफेडेरशन होता. इस एक्ट में व्यापक बदलाव विभाजन के दो साल बाद किये गए, जिसके नतीजे के रूप में भारत एक मज़बूत केंद्र का संघ बना.

जब केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का एकक्षत्र राज था, तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता की भागीदारी अर्थहीन था, लेकिन 1967 के बाद जब कांग्रेस की केंद्र सरकार को राज्य स्तर पर दूसरी पार्टियों के साथ सत्ता में भागीदारी करनी पड़ी तो टकराव पैदा होने लगा. राष्ट्रपति शासन का बेजा इस्तेमाल किया गया. गैर-कांग्रेसी सरकारों ने केंद्र पर आर्थिक भेदभाव का आरोप लगया. इस दौरान एक गैर-निर्वाचित संस्था, योजना आयोग, फंड वितरित करने का काम करती थी.

फ़िलहाल जो बहस चल रही है, वह भी एक फ़ेडरल ढांचे की ओर संवैधानिक विकास का एक चरण है. सख्त संवैधानिक मायनों में केंद्र सरकार के पास किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार नहीं है. कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने इस तरह की कार्रवाई को नियमित कार्रवाई बना दिया था. नई सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच बराबरी और बेहतर संवैधानिक बर्ताव के प्रथा की नींव डाली है. नीति आयोग योजना आयोग से अलग है. इसके ज़रिये फंड का हस्तांतरण अधिक उदार तरीके से हो रहा है. केंद्र की तरफ से राज्यों को श्रम कानून, सुशासन या भूमि अधिग्रहण, जैसे खुद के कानून पारित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है.

भारत में संसद की कार्रवाई में व्यवधान कोई नई बात नहीं है. यहां विपक्ष विरले ही मत विभाजन में विजयी होता है. भारत में सरकारें किसी विधेयक को पारित करवाने के लिए सदन के पटल पर मत विभाजन या संसोधन जैसी प्रक्रियाएं हमेशा पूरी नहीं करतीं. दरअसल, संसद के बाहर विधेयक पर बहस होती है, सुलह-सफाई होती है और बहुत जल्दबाजी में उसे पारित करा दिया जाता है. उदाहरण के लिए तेलंगाना विधयक जो कई वर्षों तक लंबित रहा, लेकिन उसे कुछ घंटों में ही पारित करवा लिया गया. यूपीए-2 के पास बहुमत नहीं थी, लेकिन वह भूमि अधिग्रहण और लोकायुक्त जैसे प्रमुख विधयक पारित करवा लेने में सफल रही थी. विपक्ष केवल संसद की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करने में ही अपनी शक्ति प्रदर्शन करता है. जहां तक संसदीय प्रक्रिया का सवाल है तो इस तरह की कार्रवाई सरकारी संसाधनों का बड़ा दुरुपयोग है. ब्रिटिश संसद में बहस के दौरान विधेयक में संसोधन करके सुधार लाया जाता है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया के दौरान पुनःअध्यन, समिति, और रिपोर्ट का चक्र चलता रहता है. सत्ता और विपक्ष दोनों के ही पिछली बेंचों पर बैठने वाले सदस्यों को भी अपनी बात रखने का मौक़ा मिलता है और सरकार को अक्सर संशोधन भी करने पड़ते हैं. भारतीय संसद के पिछली बेंचों पर बैठने वाले संसद या तो पार्टी आदेश का पालन करते हैं या स्पीकर वेल में घुस जाते हैं या नारे लगते हैं. जनता उन्हें इस काम के लिए नहीं चुनती है. जनता उनसे बेहतर काम की उम्मीद रखती है.

ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गैर-कांग्रेस पार्टी केंद्र में बहुमत में आई है. इसलिए देश की संसदीय प्रक्रिया पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है. भारत को एक बेहतर संसदीय संस्कृति की आवश्यकता है. दरअसल, भूमि अधिग्रहण विधेयक हंगामे का कारण बनी हुई है. बेहतर यह होता कि इस विधयक पर सदन के पटल पर बहस का मौक़ा दिया जाता और संशोधन के सुझावों पर वोटिंग के बाद सरकार उसे स्वीकार करती. वर्तमान में चलन यह है कि चूंकि किसी विधेयक पर विपक्ष असहमत है और वह विधयक में किसी तरह का बदलाव करवाने की स्थित में नहीं है, तो उसके पास एकमात्र उपाय है कि विधेयक को पेश करने और उस पर बहस करने से ही रोक दो. 60 साल से अधिक पुराने संसद से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है. संसद को सुचारू रूप से चलने के लिए एक नए संहिता की आवश्यकता है, ऐसा करना इस पार्टी या उस पार्टी के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए ज़रूरी है.■

feedback@chauthiduniya.com

> जब एंटोनिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थीं उसी दौरान अमेरिकी संघ की सेनाओं द्वारा फेयरफॉक्स पर कब्जा किया गया तो एंटोनिया ने अपने संबंधों को इस्तेमाल करना शुरू किया. चूंकि उनके पिता पहले से वर्जिनिया और विद्रोही राज्यों में गहरी पैठ रखते थे इस वजह से एंटोनिया को विद्रोही राज्यों की तरफ से मदद मिलने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा. उन्होंने संघ की सेना में भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी.

क्या है चर्म रोग?

चर्म रोग आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. बारिश और गर्मी के मौसम में इस तरह की समस्याएं अधिक होती हैं. ऐसे में त्वचा का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो चर्म रोग होने की संभावना ज्यादा होती है. आइए हम आपको चर्म रोग से बचने के कुछ घरेलू उपाय के बारे में जानाकरी दे रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

चर्म यानि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अंग है जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है और इसकी शरीर में संरचना बेहद जटिल होती है और यह एक तरह से हमारे शरीर के लिए रक्षाकवच का काम करती है क्योंकि इसके नीचे ही हमारे शरीर के तमाम अंग, रक्तवाहिकाएं, ग्रंथियां, कोशिकाएं छिपी रहती हैं. त्वचा हमारे शरीर को धूप और बाहरी कारकों से बचाती है और एक तरह से यह हमारे लिए वाटरप्रूफ और गैसप्रूफ परत होती है जो सूरज की गर्मी और उसकी तेज रोशनी से होने वाले दुष्प्रभावों से भी शरीर की रक्षा करती है और साथ ही हमारे शरीर में लिए आवश्यक विटामिन डी का निर्माण भी हमारी त्वचा के द्वारा सूर्य की गर्मी से होता है.

लक्षण

चर्म रोग से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव चर्म रोग शरीर में काफी जलन पैदा करता है. इस जलन का मेडिकल विज्ञान में अलग नाम है. चर्म रोग होने का मुख्य कारण है हमारे शरीर में हमारी लापरवाही की वजह से कुछ अनचाहे विषैले पदार्थो का जमा होना और कई बार जब हम बीमार होते है और कुछ गलत दवाई ले लेते है जिसके प्रति हमारा शरीर संवेदनशीलता जाहिर करता है तो उसके बाद भी चर्म पर इसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते है. कुछ चर्म रोग के कारण हैं-पारा, आयोडीन , पोटाशियम जैसे तत्वों की अधिकता हो जाना.

ध्यान रखें ये बातें

कुछ खास बातें ऐसे में आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है. उनमे से एक है साबुन से नहीं नहाना और लोग यही गलती करते हैं. लोग अच्छे से अच्छे साबुन से नहाते हैं. जबकि ऐसे में साबुन से नहाने पर आपकी तकलीफ और भी बढ़ जाती है जबकि ऐसे में साधारण गर्म और गुनगुने पानी से स्नान करने पर आपकी परेशानी दूर हो सकती है इसलिए आप अगर ठीक विधि से नहाते है तो आपकी परेशानी में आपको काफी आराम मिल सकता है.

अधिक खाना नहीं खाएं

चर्म रोग में अक्सर लोग कई तरह की लापरवाही भी करते है जिनमें से एक है खाने के प्रति लापरवाह होना और खाने की अच्छी आदतें नहीं होना ऐसे में आप खराब पाचन क्रिया के शिकार हो सकते है. अगर आप की पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी तो तो आपको चर्म रोगों में खाना सही से पचने के कारण ज्यादा आराम मिलेगा.साथ ही ध्यान रखें कि स्टार्च और शुगर आपके चर्म रोग की परेशानी को बढ़ा सकते है इसलिए भोजन करते समय अपने भोजन के संतुलित होने का ख्याल रखें और एक साथ स्टार्च या प्रोटीन का अधिक मात्रा में लेने से बचे.

चर्म रोग में आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. बारिश और गर्मी के मौसम में इस तरह की समस्याएं अधिक होती हैं. ऐसे में त्वचा का बचाव करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो चर्म रोग होने की आशंका ज्यादा होती है. आइए हम आपको चर्म रोग से बचने के कुछ घरेलू उपाय के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

घरेलू उपचार

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, त्वचा की प्राकृतिक नमी कम होने लगती है. इसलिए त्वचा के रखरखाव में सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है. हल्दी, लाल चंदन, नीम की छाल, चिरायता, बहेड़ा, आंवला, हरेड़ा और अड़ूसे के पत्ते को एक समान मात्रा में लीजिए. इन सभी सामानों को पानी में पूरी तरह से फूलने के लिए भिगो दीजिए. जब ये सारे सामान पूरी तरह से फूल जाएं तो पीसकर हल्का गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए. अब इस पेस्ट से चार गुना अधिक मात्रा में तिल का तेल लीजिए. तिल के तेल से चार गुनी मात्रा में पानी लेकर सारे सामानों को एक बर्तन में मिला लीजिए. उसके बाद मिश्रण को मंद आंच पर तब तक गर्म करते रहिए जब तक कि सारा पानी भाप बनकर उड़ ना जाए. इस पेस्ट को पूरे शरीर में जहां-जहां खुजली हो रही हो वहां पर या फिर पूरे शरीर में लगाइए. इसके लगाते रहने से आपके त्वचा से चर्म रोग ठीक हो जाएगा. इस पेस्ट का इस्तेमाल नहाने से पहले और रात में सोने से कुछ समय पहले आप कर सकते हैं. चर्म रोग होने पर पुदीना और लौंग का लेप लगाने पर भी फायदा होता है.

एग्जिमा, सोरियासिस, मस्सा, ल्यूकोर्डमा, स्केबीज या खुजली चर्म रोग के प्रकार हैं. किसी भी प्रकार का चर्म रोग जब तक ठीक नहीं हो जाता है, बहुत कष्टदायक होता है. जिसके कारण से आदमी मानसिक रूप से बीमार हो जाता है. चर्म रोग की समस्या होने पर आप चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

अमेरिकी संघ को नाकाम किया था एंटोनिया ने

अरुण तिवारी

एंटोनिया फोर्ड विलियम ने अमेरिकी सिविल वार के दौरान विद्रोही राज्यों की तरफ से जासूसी का काम किया था. एंटोनिया का जन्म अमेरिका के वर्जिनिया प्रांत में हुआ था. वर्जिनिया भी उन प्रांतों में शामिल था जिन्होंने अमेरिकी संघ के खिलाफ मोर्चा खोला था. एंटोनिया के पिता आर फोर्ड एक स्थानीय व्यापारी थे और उनका प्रांत की सरकार में अच्छा खासा रसूख था. एक व्यापारी होने के अलावा वे उन प्रमुख लोगों में शामिल थे जो वर्जिनिया को अमेरिकी संघ से अलग करने की मंशा रखते थे. एक तरह से वे अलगाववादी धड़े के नेता भी थे जो यह मानते थे कि अमेरिका से आजाद होने के बाद वर्जिनिया और दूसरे छह विद्रोही राज्यों का भविष्य और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है. एंटोनिया ने अपनी शुरुआती शिक्षा कुंबे कॉटेज स्कूल से प्राप्त की थी. इसके बाद उच्च शिक्षा लेने के लिए वे बकिंघम फीमेल कॉलिजियेट इंस्टीट्यूट चली गईं.

विश्वविद्यालय में शिक्षा के दौरान एंटोनिया फोर्ड न सिर्फ शिक्षा ग्रहण करती थीं बल्कि खेलों में भी रुचि लिया करती थीं. एंटोनिया भी अपने पिता के विचारों से काफी प्रभावित थीं. दरअसल अमेरिकी सिविल वार की शुरुआत भले ही साल 1861 में हुई हो लेकिन इसके बीज विद्रोही राज्यों में बहुत पहले से ही पड़ चुके थे. इन राज्यों में एक बड़ा तबका यह मानने लगा था कि हमारा विकास तभी हो सकता है जब हम अमेरिकी संघ से अलग हो जाएंगे. इसके लिए इन राज्यों में विद्वान लोगों और संभ्रात लोगों का एक बड़ा तबका दशकों से लॉबिंग कर रहा था और ऐसा माहौल तैयार कर रहा था कि अमेरिकी संघ के विरुद्ध जंग छेड़ कर न सिर्फ उससे अलग हुआ जाए बल्कि उसे युद्ध में हराया भी जाए. लेकिन यह लड़ाई इस वजह से आसान नहीं थी, क्योंकि एक तो इन राज्यों के पास संघ के मुकाबले संसाधनों की कमी थी और दूसरा समस्त विश्व से अमेरिका को सपोर्ट भी मिल रहा था. हालांकि विद्रोही राज्यों की तरफ से भी काफी माहौल वैश्विक स्तर पर बनाया जा रहा था, लेकिन संघ की पैठ की वजह से उसे ऐसा कर पाने में मुश्किल हो रही थी.

जब एंटोनिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थीं उसी दौरान अमेरिकी संघ की सेनाओं द्वारा फेयरफॉक्स पर कब्जा किया गया तो उस दौरान एंटोनिया ने अपने संबंधों को इस्तेमाल करना शुरू किया. चूंकि उनके पिता पहले से वर्जिनिया और विद्रोही राज्यों में गहरी पैठ रखते थे इस वजह से एंटोनिया को विद्रोही राज्यों की तरफ से मदद मिलने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा. उन्होंने संघ की सेना में भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी. संघ की सेना के कई अधिकारियों से उन्होंने संपर्क बनाए. एंटोनिया इसके लिए अपनी खूबसूरती का भी इस्तेमाल किया करती थीं. एंटोनिया संभ्रांत परिवार की थीं और इस बात का लाभ उन्हें संघ की सेना के अधिकारियों से संपर्क बनाने के दौरान मिला. उनकी कई ऐसी मित्र थीं जिनके पति संघ की सेना में अधिकारी थे. अपनी दोस्तों से मिलने के बहाने वे उनके पतियों से भी मिला करती थीं. बातों ही बातों में कई खुफिया जानकारियां हासिल किया करती थीं और उन जानकारियों को विद्रोही राज्यों तक पहुंचा दिया करती थीं. उन पर कोई शक भी नहीं करता था, क्योंकि उनके बारे में यह बात किसी को पता नहीं थी कि वे विद्रोही राज्यों के लिए काम किया करती हैं. एंटोनिया का भाई व्रिदोही सेना में था. जब संघ की सेनाओं का हमला होना तय था उस दौरान कई ऐसी खुफिया जानकारियां एंटोनिया ने विद्रोही सेना के ब्रिगेडियर को उपलब्ध करवाईं जिनके जरिये संघ के हमले को कई जगह नाकाम किया गया. इसके बाद विद्रोही राज्यों में एंटोनिया की कद्र बहुत ज्यादा बढ़ गई. साल 1861 में ही उन्हें इन राज्यों की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया. जब उन्हें पुरस्कार मिला तो इस बात की खबर कई अखबारों में प्रकाशित हुई. अब वे धीरे-धीरे इस बात के लिए प्रसिद्ध होने लगीं कि वे एक विद्रोही जासूस हैं.

साल 1863 में एक ऐसा काला दिन भी आया जब एंटोनिया को संघ के एक जासूस फ्रैंकी एबेल ने अपने जाल में फंसा लिया. एंटोनिया मानती थीं कि वह उनका मित्र है, लेकिन एक जासूस होने के बावजूद भी उनकी आंखें इस बात में धोखा खा गईं कि वे एक जासूस को पहचान सकें. इसके बाद एंटोनिया को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अमेरिकी जनरल एडविन की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. लेकिन जब इस बात की पड़ताल की गई तो विद्रोही सेना के वे अधिकारी बिल्कुल अपनी बात से पलट गए जिन्हें एंटोनिया ने जानकारी दी थी. एंटोनिया के खिलाफ इसके बाद कोई भी सबूत संघ की सेना के पास नहीं था. लिहाजा उन्हें छोड़ दिया गया. वे वापस लौटकर वर्जिनिया आ गईं. उन्होंने साल 1864 में शादी की. साल 2007 में एंटोनिया पर बॉलीवुड में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई थी. जिसमें उनके जीवन के बारे में बताया गया. एंटोनिया के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि आगे का जीवन वाशिंगटन में गुजारने के लिए उन्होंने संघ के साथ रहने की कसम भी खाई थी. उन्होंने यहां भी अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और एक बार संघ से जुड़ने के बाद उन्होंने कभी विद्रोही गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश नहीं की. एंटोनिया की मौत 1871 में हुई.■

feedback@chauthiduniya.com

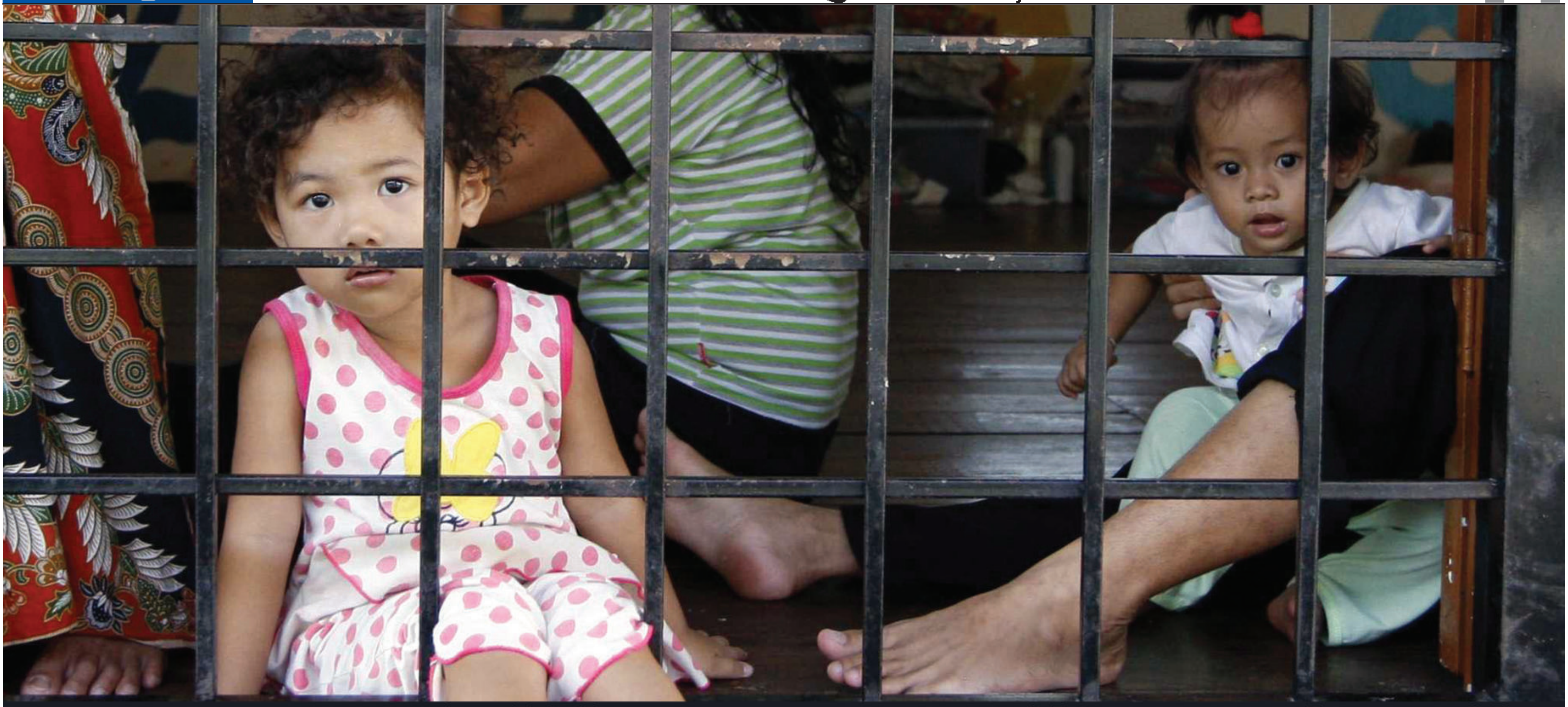

चीन मानव अंगों के व्यापार का वैश्विक केन्द्र है

चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चीन में करीब 15 लाख लोगों को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है, जबकि अंग दानकर्ताओं की कमी के कारण हर वर्ष केवल 10 हजार लोगों का ही अंग प्रत्यारोपण हो पाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि जरूरतमंद लोगों को अंगों का प्रत्यारोपण कैसे किया जाता है? चीन में मानव अंगों की तस्करी के खिलाफ कड़े कानून हैं, फिर भी दलालों द्वारा ऊंचे दामों पर प्रत्यारोपण के लिए जरूरी अंग चोरी और तस्करी के रास्ते उपलब्ध कराई जाती है. अभी हाल ही में चीन में मानव अंगों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने इससे जुड़े 137 लोगों को गिरफ्तार किया है. चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह अभियान संयुक्त रूप से देश के 18 प्रांतों की पुलिस द्वारा चलाया गया था. ये आंकड़े और अभियान इस ओर इशारा करते हैं कि चीन विश्व में मानव अंगों के तस्करी का प्रमुख केंद्र बन चुका है.

वसीम अहमद

मुर्दे शिकायत नहीं करते. यही कारण है कि पूरे विश्व में मानव अंगों की तस्करी का एक बड़ा जाल बिछ चुका है. रूस, भारत, कुछ दक्षिण एशियाई देश और कुछ बेहद गरीब अफ्रीकी देशों में यह धंधा जोरों पर है. इन देशों में मानव अंगों, किडनी, आंखों के कॉर्निया, लीवर, चमड़ी आदि निकालकर बिचौलियों के जरिये बेचे जाते हैं. मानव अंगों की तस्करी और व्यापार में चीन इन देशों को भी पीछे छोड़ चुका है. चीन दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश है. वह दुनिया के उन पांच शक्तिशाली देशों में शामिल है, जिसे सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त है. चीन की राष्ट्रीय विचारधारा वामपंथ पर आधारित है, जिसमें हिंसा और कट्टरता का तत्व शामिल है. यही कारण है कि चीनी सरकार अपने प्रभुत्व को बरक़रार रखने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है. वह अपना दबदबा दिखाने के लिए न केवल पड़ोसी देशों के साथ, बल्कि अपनी जनता के साथ भी प्राय: हिंसात्मक हो जाती है. अभी हाल ही में चीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ज़कीउर्रहमान लखवी को रिहा करने को लेकर सुरक्षा परिषद में बहिष्कार करके इस बात का सबूत दे चुका है. लखवी मुम्बई धमाकों का प्रमुख दोषी है और इसको रिहा करने पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग पर चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो कर दिया था, जिसके बाद लखवी को संरक्षण मिल गया और वह गिरफ्तारी से बच गया. जहां तक चीनी सरकार का अपने नागरिकों पर हिंसा की बात है तो इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंसा के कारण ही चीन में 1950 से अब तक लगभग 6 से 8 करोड़ नागरिक मारे जा चुके हैं.

चीन दुनिया का पहला देश है, जहां मानव अंगों का व्यापार उच्च स्तर पर होता है और यह सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है. हालांकि चीनी क़ानून में मानव अंगों का व्यापार करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इस क़ानून का क्रियान्वयन नहीं है. इस अमानवीय व्यापार में चीन के बड़े-बड़े नेताओं का हाथ शामिल रहा है. 2009 में स्पेन की एक अदालत चीनी सरकार के कई वरिख़नेताओं को इस व्यापार में संलिप्त होने का दोष लगा चुकी है. 2010 में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने चीन में इस व्यापार को रोकने के लिए प्रावधान संख्या 605 प्रस्तुत किया था. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी प्रयासों के बावजूद चीन में यह व्यापार जारी है. 2006 में एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन में क़ैदी बनाये गये लोगों के अंग निकाल कर दूसरे देशों में बेच दिये जाते हैं. कनाडा के एक पत्रकार लियोन ली ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की. इस रिपोर्ट में उन्होंने चीन के अन्दर मानव अंगों के व्यापार से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य पेश किये हैं, जिनको जानने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया. उन्होंने चीन के कई अस्पतालों का दौरा करने और डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद यह ख़ुलासा किया कि यहां प्रत्येक वर्ष हज़ारों की संख्या में मानव अंग बेचे जाते हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है. कनाडा मूल के संगठन फालून दाफ़ा की ओर से जारी एक वीडिया फिल्म में बताया गया है कि चीन में फेफड़े, कॉर्निया, हार्ट, किडनी आदि का व्यापार उच्च स्तर पर हो रहा है. 2000 से लेकर 2005 तक चीन में विभिन्न अंगों के लगभग 41,500 मानव अंग अवैध रूप से प्रत्यारोपित किये गये थे. आम तौर पर एक फेफड़े का मूल्य 150,000 डॉलर, कॉर्निया 30,000 डॉलर, हार्ट 130,000 से लेकर 160,000 डॉलर, किडनी 62,000 डॉलर और किडनी पैनक्रियाज का मूल्य 150,000 डॉलर में एक्सपोर्ट किया जाता था.

अब सवाल यह पैदा होता है कि आख़िर एक्सपोर्ट करने के लिए मानव अंग इतने बड़े स्तर पर कहां से उपलब्ध कराए जाते थे? इसका जवाब एक वीडियो फिल्म में है कि किस तरह से चीन की विभिन्न जेलों में बंद ऐसे क़ैदी या सैनिक जिनको मौत की सज़ा दी गई हो, के अंग सज़ा देने के बाद निकाल लिये जाते थे और फिर इन्हें भारी क़ीमत लेकर बेच दिया जाता था. चीन से प्रकाशित होने वाला अख़बार 'डेली चायना' ने लिखा है कि चीन में प्रत्यारोपण के लिए मानव अंग का जो दान किया जाता है, इनमें 65 प्रतिशत अंग इन कैदियों के होते हैं, जिन्हें मौत की सज़ा दी जाती है. ये अंग उनकी इच्छा के विरुद्ध निकाले जाते हैं. इस अख़बार ने चीन के उप स्वास्थ मंत्री हुनांग जीफू का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार प्रत्यारोपण के लिए, मृत्युदंड पाने वाले कैदियों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में कई ऐसी अवैध एजेंसियां काम कर रही हैं, जो कागज़ों में हेरफेर करके मरीज़ों को आवश्यक अंग उपलब्ध कर देती हैं. चीन में ऐसे अस्पताल भी मौजूद हैं, जहां भारी मुनाफे के बदले में अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है.

प्रत्यारोपण करने वाली जर्मनी फाउंडेशन के चेयरमैन गुंटर क्रिस्टे कहते हैं कि प्रत्यारोपण की अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी ने हमेशा इस बात पर कड़ा विरोध जताया है, इसलिए बार-बार विश्वास दिलाये जाने के बावजूद यह समस्या हल नहीं हो सकी है. इस अवैध काम के ख़िलाफ़ मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों की ओर से आवाज़ उठाई गई और किसी के अंगों को उसकी इच्छा के बिना जिंदगी या इसकी मौत के बाद निकालने के खिलाफ़ विरोध जताया गया, तो चीन की ओर से यह सफ़ाई दी गई कि जो अंग ज़रूरतमंदों को उपलब्ध किये जाते हैं, वह दान के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में अपनी इच्छा से वार्षिक अंग दान करने वालों की कुल संख्या 100 से 150 तक होती है, जबकि दुनिया भर से अंगों के ज़रूरतमंदों की संख्या 1.5 मिलियन है. इनमें से वार्षिक 10 हज़ार लोगों की आवश्यकताएं पूरी कर दी जाती हैं और शेष पाइपलाइन में होते हैं और जैसे ही अंग उपलब्ध होता है, उन्हें जरूरतमंद व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है. चीन में यह उपलब्धता इन कैदियों से की जाती है, जिनको फांसी की सज़ा हो चुकी है या अन्य रूप से मौत की सज़ा दी जाती है. ऐसे कैदियों के अंग सज़ा दिये जाने के तुरंत बाद निकाल लिये जाते हैं. चीन में मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों की संख्या लगभग 8 हज़ार वार्षिक है. इस प्रकार देखा जाये तो इंटरनेशनल डिमांड की अधिकतर ज़रूरतें चीन से ही पूरी की जाती हैं. फिल्म में दिखाया गया है कि इन अंगों की भारी क़ीमत वसूल करने के लिए कई बार जिंदा कैदियों के अंग बेहोशी की हालत में भी निकाले जाते हैं. उस वीडियो एक डॉक्टर को यह बताते हुए दिखाया गया है कि मौत की सज़ा पाने वाले एक कैदी को इसके सीने की दाईं ओर गोली मारी गई. गोली दाईं ओर लगने के कारण वह जिंदा बच गया, लेकिन बेहोशी की हालत में था. अस्पताल ने इसके जीवित रहते हुए ही इसका लीवर और किडनी बाहर निकाल लिया.

चीन में इस अमानवीय व्यापार की परंपरा बहुत पुरानी है और इस कारोबार के द्वारा सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी मुनाफ़ा कमा रही है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अवैध रूप से मानव अंगों का प्रत्यारोपण फंड की कमी के शिकार चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी एक मुनाफे और तेज़ी से फलता-फूलता कारोबार बनता जा रहा है. यह काम सरकार और वहां की सेना की मिलीभगत से हो रहा है. पुलिस और सुरक्षाकर्मी इस काम में मदद पहुंचाते हैं और निर्दोष लोगों को झूठे आरोपों में फंसा कर जेलों में डाल देते हैं और फिर इनके अंग निकाल लिये जाते हैं. पुलिस विरोधी समूह के लोगों को जबरन गिरफ्तार करती है और इन्हें बंद कर देती है और फिर इन पर तरह-तरह के आरोप लगाकर मुक़दमा चलाया जाता है. जैसा कि 20 जुलाई, 1999 में बीजिंग के जिला हुयेरो में एक अफसोसनाक घटना हुई. आधी रात के अंधेरे में कुछ पुलिसकर्मियों ने दबिश देकर आधी रात को सैंकड़ों निर्दोष लोगों को इनके घरों से उठा लिया और उन्हें जबरन जेलों में कैद कर दिया. फिर इन पर कड़े आरोप लगाये गये. अब अगर फालून दाफ़ा की दिखाई गई फिल्म पर भरोसा किया जाये तो यह साफ़ हो जाता है कि मौत की सज़ा पाने वाले लोग कौन होते हैं? ज़ाहिर है यह सरकार के राजनीतिक विरोधी होते हैं, जिनको पुलिस दबिश देकर पकड़ती है और फिर इन पर तरह-तरह के मुक़दमे लगाकर अदालत में पेश करती है और जब इनके लिए सज़ाए मौत तय हो जाती है, तो इनके अंग निकाल कर बेच दिये जाते हैं. यहां तक कि चीन, जिसको दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार किया जाता है, वह अपनी शक्ति के अहंकार में न केवल पड़ोसी देशों पर अत्याचार करता है, बल्कि अपने नागरिकों पर हिंसा और जेलों में बंद कैदियों के अंगों को बेचने का गंभीर अपराध भी कर रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत में भी मानव तस्करी

भारत में भी मानव अंगों की चोरी, तस्करी, विक्रय का एक विशाल रैकेट काम कर रहा है. छिटपुट मामले कभी-कभार पकड़ में आते हैं, लेकिन निठारी या डॉ अमित जैसे बड़े केस इक्का-दुक्का ही हैं. निठारी कांड में बच्चों की किडनियां निकालने की बात सबके सामने आई थी, किडनी किंग डॉक्टर अमित को कौन भूला होगा, जिसका नेटवर्क नेपाल तक फैला हुआ है और जिसके ग्राहकों में कई वीआईपी शामिल हैं. सभी को याद होगा कि इंग्लैंड निवासी स्कारलेट के शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग गायब थे. अकेले उत्तरप्रदेश से गत पांच वर्षों में 12,000 से अधिक गुमशुदगी के मामले सामने आये हैं, जिसमें से अधिकतर बच्चे हैं. अपराधी तत्व कब्रिस्तानों और श्मशानों से मानव कंकाल, खोपड़ी और अन्य मानव अंग खोदकर ले जाते हैं और उन अंगों को बाजार में ऊंची कीमतों पर बेच देते हैं. जाहिर है कि यह धंधा बेहद मुनाफे वाला है. कई मामलों में जांचकर्ताओं ने पाया है कि इस प्रकार के मानव अंगों के मुख्य खरीदार अरब देशों के अमीर शेख, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका के बेहद धनी लोग होते हैं. ऐसे में अपराधियों, दलालों, गंदे दिमाग वाले डॉक्टरों और किडनी, आंखें, लीवर आदि अंगों के विदेशी ग्राहकों का एक खतरनाक गैंग चुपचाप अपना काम जारी रखे हुए है. एक मोटे अनुमान के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष एक लाख किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, जबकि आधिकारिक और कानूनी रूप से सिर्फ 5000 किडनियां बदली जा रही हैं. जाहिर है कि मांग और पूर्ति में भारी अंतर है और इसका फायदा स्मगलर उठाते हैं. हाइवे पर अकेले चलने वाले ड्रायवर, नशे में हुए एक्सीडेंट, जिनमें लाश लावारिस घोषित हो जाती है, अकेले रहने वाले बूढ़े, जिनकी असामयिक मौत हो जाती है, गरीब, मजबूर और कर्ज से दबे हुए लोग आदि इस माफिया के आसान शिकार होते हैं. (मुंबई, गुड़गांव, चेन्नई चारों तरफ इस प्रकार के अपराध पकड़ में आ रहे हैं. उज्जैन में एक किडनी रैकेट पकड़ाया था, जो डॉक्टरों की मिलीभगत से गरीबों और मजदूरों को किडनी बेचने के लिये फुसलाता था. ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में कई बार ये अपराधी अपहरण करने से भी नहीं हिचकते.

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

मां ने बालक का मन रखने के लिए सच में ही सोने का अपना वह कंगन कलाई से उतारा और कहा कि लो, दे दो. बालक ख़ुशी-ख़ुशी वह कंगन उस भिखारिन को दे आया. भिखारिन को तो मानो एक ख़ज़ाना ही मिल गया. कंगन बेचकर उसने परिवार के बच्चों के लिए अनाज, कपड़े आदि जुटा लिए. उसका पति अंधा था. उधर वह बालक पढ़-लिखकर बड़ा विद्वान हुआ, काफ़ी नाम कमाया.एक दिन वह मां से बोला कि मां! तुम अपने हाथ का नाप दे दो, मैं कंगन बनवा दूं कि उसे बचपन का अपना वचन याद था.

बाबा के प्रति बढ़ता आकर्षण

चौथी दुनिया ब्यूरो

बाबा की ओर लोग किस लिए आकर्षित होते हैं?

सद्गुरु ईश्वरीय स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात देह-धारण करके, सगुण रूप से आए हैं. उनके पास विभिन्न मन-वृत्ति के लोग आते हैं. शिरडी में जब वे देह-रूप में थे, तब भी आते थे. आज जबकि वे सूक्ष्म रूप में हैं. फिर भी लोग उनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और आगे भी उनका आकर्षण रहेगा. इस संदर्भ में यह बताना उचित होगा कि बाबा के विभिन्न प्रकार के भक्त हैं.

बाबा के प्रति प्रथम बार आकर्षित होने वाले ज्यादातर लोग अपनी उद्देश्य-पूर्ति जैसे संतति प्राप्त करना एवं उनके सौभाग्य की कामना, नौकरी या उच्चपद प्राप्त करने की लालसा, धन या यश प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण आते थे. दामू अण्णा कासार, नांदेड़ के रतन जी, श्रीमती औरंगाबादकर आदि संतान प्राप्ति की कामना से बाबा के पास आए थे. हरिश्चन्द्र पितले संतति की कल्याण कामना से चिंतित थे. अत: उनका शिरडी-गमन हुआ. गोपाल नारायण आंबेडकर नौकरी की समस्या से ग्रस्त थे. रघुनाथ राव पेंशन में वृद्धि के लिए बाबा के कृपाकांक्षी थे. कुछ लोग परीक्षा में सफलता की कामना से बाबा की भक्ति की दिशा में अग्रसर हुए- जैसे चोलकर, शेवड़े, तेंदुलकर आदि. संक्षेप में उपर्युक्त प्रकार के भक्त सद्गुरु के पास अपनी वस्तुवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आते थे.

दूसरे प्रकार के लोग आधि-व्याधि, कचहरी, ऋण, झगड़ा, फसाद आदि कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए आते थे. साठे को मानसिक शांति की तलाश थी. इसलिए वे शिरडी गए. काकासाहेब दीक्षित मन की पंगुता दूर करने के लिए बाबा के पास पहुंचे. बाबा ने ऋण से मुक्त होने के लिए भक्तों की सहायता की. रोग-निवृत्ति के उद्देश्य से शिरडी आने वाले अनेक लोगों का उल्लेख श्री साई सच्चरित्र में हुआ है. जैसे भीमा जी पाटिल दत्तोपंत, माधवराव देशपांडे, अमीर शक्कर आदि बाबा का कहना था-कोई कितना भी दुखित पीड़ित क्यों न हो. जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है. वह सुखी हो जाता है.

बाबा की दिव्य शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए या कौतूहलवश भी कुछ लोग उनके पास जाते थे. जैसे श्रीमान ठक्कर हरी कानोबा आदि ऐसे लोगों के प्रति बाबा का कहना था आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर लें. इस प्रकार भटकने से कोई लाभ नहीं है. कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनमें थोड़ा बहुत भक्तिभाव तो रहता था, लेकिन वह भी परंपरागत रूप में जैसे डॉक्टर के इष्ट राम थे, लेकिन मित्र के साथ शिरडी जाने पर जब उन्होंने श्री साई को राम रूप में देखा तो वे साई भक्त हो गए. कुछ ऐसे भी लोग थे जो विद्या या उपदेश प्राप्ति के लिए बाबा के पास गए. जैसे कि धार्मिक लोग विद्वान पंडितों के पास जाया करते हैं. नाना साहेब निमोणकर जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था और भागवत् पढ़ना चाहते थे. बाबा की कृपा से उसे पूरा पढ़कर अर्थ समझ गए.

कुछ भक्त ऐसे थे, जो बाबा के प्रति विशुद्ध सेवा की भाव से उनके पास जाते थे, जैसे बाइजाबाई, मेघा आदि. वस्तुत: अपनी जिस उद्देश्य सिद्धि के लिए लोग जैसे पहले बाबा के पास जाते थे, आज भी बाबा की भक्ति की पृष्ठभूमि में लगभग वैसी ही मानसिकता है-हां स्थिति पहले से विकट हो गई है. जैसा पहले था, वैसे ही आज भी ऐसे भक्त बहुत ही विरले हैं, जो कुछ मांगने या किसी भय से मुक्त होने के विचार से उठकर मात्र आध्यात्मिक प्रगति के लिए श्री साई महाराज की पूजा करते हैं.

बाबा से सांसारिक जगत की सुविधा उपलब्ध करके एवं मानसिक सहायता प्राप्त करने के उपरांत भी कुछ लोग क्यों नहीं प्रगति कर पाते, यद्यपि वे कहते हैं कि वे बाबा के शरणागत हैं और आत्म-समर्पण कर चुके हैं?

वास्तव में आत्म समर्पण कह देने से ही आत्म-समर्पण नहीं होता. ज्यादातर लोग समर्पण शब्द का आसानी से प्रयोग करके समझते हैं कि समर्पण हो गया है. वे अर्पण बहुत कम करते हैं और पाना बहुत अधिक चाहते हैं. कुछ लोग भक्ति की बात करते हैं, मंदिर में खूब पूजा करते हैं और बाबा के प्रति आकर्षित होने की बात करते हैं, पर वास्तव में उनके भीतर कुछ अन्य भावना जैसे कि धन, तरक्की, संतान आदि प्राप्त करने की तीव्र इच्छा छाई रहती है. अगर उनकी यह इच्छा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी नहीं होती है, तो वे विमुख होने लगते हैं. जैसे कई स्वार्थी व्यक्ति बाबा की पूजा कम करते हैं या किसी अन्य गुरु, तांत्रिक, साधु आदि की तलाश में रहते हैं-जो उनकी मूल मनोकामना पूरी करे. कहने का तात्पर्य यह है कि वे बाबा के पास अहंकार शून्य होकर नहीं आते अपितु वे तो अपना अंहकार पूर्ण करने आते हैं, जिनका पूरा होना संभव नहीं हो पाता है. इनकी कुछ पाने की लालसा इतनी तीव्र होती है कि अगर कुछ पूजा पाठ करते हुए वह पूरी नहीं होती तो वे व्याकुल रहते हैं और बाबा को छोड़ देते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

प्रधानमंत्री सबका होता है

जब तोप मुकाबिल हो-आप देश के प्रधानमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं(27 जुलाई -02 अगस्त 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने बिल्कुल सही कहा है कि नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति द्वारा दी गई ईफ्तार पार्टी में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक उसी दिन और उसी समय बुलाई थी. नरेन्द्र मोदी देश के सभी जाति व धर्म के लोगों के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्हें सभी धर्मों के त्यौहार का सम्मान करना चाहिए. प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति भवन के इफ्तार पार्टी में न जाने का कारण मीटिंग रही हो, लेकिन देश के मुसलमानों में एक संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री उनके धर्म और त्यौहारों का सम्मान नहीं करते. इसलिए प्रधानमंत्री को सभी धर्मों के लोगों के त्यौहारों में शामिल होना चाहिए और उन्हें यह संदेश देना चाहिए कि उनके लिए सभी बराबर हैं, वो चाहे किसी धर्म और जाति के लोग हों.

-फिरोज़ आलम, *पटना, बिहार.*

डिजिटल भारत चाहिए

हमारे समाज का अंतिम आदमी अपने हिस्से की बुनियादी तरक्की का आज भी इंतजार कर रहा है. समाज व्यवस्था और आदमी के चरित्र में आई दरारों को देखने-सुनने व महसूस करने की आवश्यकता है. हमारे प्रधान सेवक मोदी ने पिछले दिनों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की घोषणा बड़े धूमधाम से की. पिछले साल प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि यूपीए सरकार ने बाजारीकरण नीति को ठीक से लागू नहीं किया, मैं उसे ठीक से लागू करूंगा. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम उसी घोषणा का एक हिस्सा है, जिसमें पूंजीपतियों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आम जनता के लिए क्या है वह अभी स्पष्ट नहीं है. देखा जाए तो हमारे भारत में एक ऐसा बहुसंख्यक समाज है, जिसके पास सूचना का कोई साधन नहीं है. भारत में गरीबी और अशिक्षा है. गरीबों तक सूचना पहुंचाने के लिए पहला उपाय उन्हें शिक्षित करना है, लेकिन केन्द्र सरकार ने शिक्षा का बजट 16.5% घटा दिया है और शिक्षा पर कोई उल्लेखनीय पहल नहीं की. शिक्षा के बिना ई-गवर्नेंस की आम जनता के लिए क्या उपयोगिता होगी. डिजिटल इंडिया से पहले एजूकेट इंडिया की बात हो. लगभग चालीस करोड़ किसानों का यह देश हमारे प्रधानसेवक की ओर देख रहा है. उन्हें डिजिटल भारत चाहिए डिजिटल नहीं. सत्ता की आपाधापी में उलझी केन्द्र सरकार को भारत की जनता की परवाह होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरी समझ है भारत की, वो जानते पहचानते हैं भारत को. इसलिए उन्हें परवाह भी भारत की होनी चाहिए .

-गौरव निर्मोही, *दरभंगा, बिहार.*

देश में अकूत कालाधन है

लोकसभा चुनावों के समय भाजपा को कालेधन की वापसी के लिए जनता ने अभूतपूर्व समर्थन दिया था, लेकिन सरकारें भूल जाती हैं कि यदि 10 रूपये विदेशी बैंकों में जमा है, तो 1000 रुपये कालाधन देश में ही है. सरकार उस धन की बात क्यों नहीं करती? जो अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व जन प्रतिनिधियों ने रिश्वत व कमीशन से कमाए हैं. चौथी दुनिया ने प्रकाशित किया था कि सोनभद्र में खनन माफिया अवैध खनन कर प्रतिमास 13 करोड़ रुपये वी.आई.पी के रूप में ऊपर भेजते हैं. यादव सिंह के घर से जो दस्तावेज मिले थे उससे प्रमाणित हुआ था कि उनके पास एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति है. अब्दुल करीम तेलगी ने जाली स्टाम्प पेपर बेचकर तीस हजार करोड़ कमाए. अवैध कमाई करने वाले लाखों रुपये प्रतिमास उच्चाधिकारियों तक पहुंचाते हैं. अगर सरकार वाकई कालाधन निकालना चाहती है, तो प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी विधायक सांसद से केह कि वे शपथ पत्र देकर घोषित करें कि उनके परिवार जनों के नाम अमुक-अमुक सम्पत्ति है. जांच कर गलत ढंग से कमाई गई व छुपाई गई सम्पत्ति को सरकार जब्त करे.

-राजकिशोर पाण्डेय
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

धूम्रपान न करने के लिए प्रेरित करें

केंद्र सरकार की सिफारिश पर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी, सिगरेट पीने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे. इस आदेश से कुछ प्रबुद्ध लोग बहुत प्रसन्न हुए तथा कुछ बीड़ी, सिगरेट बनाने वाली कम्पनियों एवं धूम्रपान करने वाले नागरिक नाराज़ एवं परेशान हुए. आदेश जारी होने के कुछ दिनों तक तो स्थिति बहुत अच्छी रही. लोगों ने सज़ा एवं जुर्माने के डर से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना बंद कर दिया, लेकिन अब स्थिति धीरे-धीरे पहले जैसी हो गयी है. आज रेलवे स्टेशनों, औषधालयों, बस अड्डों, न्यायालयों यहां तक कि विद्यालयों में भी निर्भय होकर धूम्रपान करके न्यायालय के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इसका प्रमुख कारण है, इस बुराई के प्रति सरकार का कड़ा रुख़ न होना तथा लोगों में सामाजिक चेतना का अभाव. अतः आप अपने समाचार-पत्र के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने के लिए प्रेरित करें.

-अदित्य नारायण, *नोएडा, उत्तर प्रदेश.*

जातिगत आंकड़ों का खुलासा हो

सामाजिक-आर्थिक व जाति आधारित जनगणना(एसईसीसी) 2011 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश के कई करोड़ परिवार गांवों में रहते हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताों को पूरा करने में असमर्थ हैं, इससे देश की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का पता चलता है, लेकिन जातिगत आंकड़ों के सार्वजनिक न होने से अभावों से ग्रस्त एक बड़ी आबादी की स्पष्ट तस्वीर सामने आने से रह गई है, क्योंकि भारतीय समाज में जाति एक सच्चाई है, जिससे मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं जब कि जनगणना सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित की गई है, अत: सरकार को चाहिए कि देश के समग्र विकास के लिए जातिगत आंकड़ों का भी खुलासा करे.■

-सत्य प्रकाश शिक्ष, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

महानता के लक्षण

एक बालक नित्य विद्यालय पढ़ने जाता था. घर में उसकी माता थी. मां अपने बेटे पर प्राण न्योछावर किए रहती थी, उसकी हर मांग पूरी करने में आनंद का अनुभव करती. पुत्र भी पढ़ने-लिखने में बड़ा तेज़ और परिश्रमी था. खेल के समय खेलता, लेकिन पढ़ने के समय का ध्यान रखता.

एक दिन दरवाज़े पर किसी ने-माई! ओ माई!' पुकारते हुए आवाज़ लगाई तो बालक हाथ में पुस्तक पकड़े हुए द्वार पर गया, देखा कि एक फटेहाल बुढ़िया कांपते हाथ फैलाए खड़ी थी.

उसने कहा, बेटा! कुछ भीख दे दे. बुढ़िया के मुंह से बेटा सुनकर वह भावुक हो गया और मां से आकर कहने लगा कि मां! एक बेचारी गरीब मां मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है. उस समय घर में कुछ खाने की चीज़ थी नहीं, इसलिए मां ने कहा कि बेटा! रोटी-भात तो कुछ बचा नहीं है, चाहे तो चावल दे दो. पर बालक ने हठ करते हुए कहा-मां! चावल से क्या होगा? तुम जो अपने हाथ में सोने का कंगन पहने हो, वही दे दो न उस बेचारी को. मैं जब बड़ा होकर कमाऊंगा तो तुम्हें दो कंगन बनवा दूंगा.

मां ने बालक का मन रखने के लिए सच में ही सोने का अपना वह कंगन कलाई से उतारा और कहा कि लो, दे दो. बालक खुशी-खुशी वह कंगन उस भिखारिन को दे आया. भिखारिन को तो मानो एक ख़ज़ाना ही मिल गया. कंगन बेचकर उसने परिवार के बच्चों के लिए अनाज, कपड़े आदि जुटा लिए. उसका पति अंधा था. उधर वह बालक पढ़-लिखकर बड़ा विद्वान हुआ, काफ़ी नाम कमाया. एक दिन वह मां से बोला कि मां! तुम अपने हाथ का नाप दे दो, मैं कंगन बनवा दूं कि उसे बचपन का अपना वचन याद था. पर माता ने कहा कि उसकी चिंता छोड़. मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं कि अब मुझे कंगन शोभा नहीं देंगे. हां, कलकत्ते के तमाम ग़रीब बालक विद्यालय और चिकित्सा के लिए मारे-मारे फिरते हैं, उनके लिए तू एक विद्यालय और एक चिकित्सालय खुलवा दे जहां निशुल्क पढ़ाई और चिकित्सा की व्यवस्था हो. मां के उस पुत्र का नाम ईश्वररचंद्र विद्यासागर था.■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

लिटरेचर फेस्टिवल का बढ़ता दायरा

अनंत विजय

हमारे देश में पिछले दो-तीन वर्षों में लिटरेचर फेस्टिवल की संख्या में खासा इज़ाफ़ा हुआ है. अब तो देशभर के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग लिटरेचर फेस्टिवल या साहित्य उत्सव मनाया जाता है. कई अखबारों ने भी साहित्य को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने लिट फेस्ट शुरू कर दिए हैं. परंतु ज्यादातर लिटरेचर फेस्टिवल में अंग्रेजी हावी रहती है, अंग्रेजी के लेखकों को प्राथमिकता दी जाती है. अच्छी बात यह हुई है कि अब हिंदी समेत कुछ अन्य भारतीय भाषाओं ने अपनी भाषा में साहित्योत्सव शुरू कर दिया है. साहित्य महोत्सव पाठकों को ध्यान में रखकर आयोजित किए जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इनका उद्देश्य और मंशा साहित्य और समाज के सवालों से टकराने का है. वरिष्ठ लेखक आपस में साहित्य की समकालीन समस्याओं से लेकर नई लेखकीय प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं. माना यह जाता है कि इससे उस भाषा के पाठक संस्कारित होंगे. होते ही हैं. परंतु हाल के दिनों में इन लिटरेचर महोत्सवों में सितारों और गंभीर लेखकों के बीच का फर्क मिट सा गया है. जिस तरह से प्रकाशकों को यह लगता है कि फिल्मी सितारों, राजनेताओं, सेलिब्रिटी पत्रकारों की किताबें छापने से उनको लाभ होगा उसी तरह से अब इन साहित्यक मेला आयोजकों को भी अपने बीच सितारों से लेकर पूर्व और वर्तमान राजनेताओं को लाने की होड़ लगी रहती है. देशभर के कई लिटरेचर फेस्टिवल में गुलज़ार साहब स्थायी भाव की तरह मौजूद रहते हैं. हिंदी के कवि के तौर पर. भले ही उन साहित्यक मेलों में केदारनाथ सिंह, लीलाधर जगूड़ी या विनोद कुमार शुक्ल हों या ना हों. गुलज़ार को बुलाने के पीछे की मंशा उनकी बेहतरीन कविताएं सुनने की अवश्य रहती होंगी, लेकिन भीड़ जुटाना और पाठकों को आकर्षित करना भी एक मकसद रहता है. इसके अलावा अब तो फिल्मी सितारों को भी लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाने का चलन शुरू हो गया है. अमिताभ बच्चन से लेकर शर्मिला टैगोर तक को इन साहित्यिक महोत्सवों में बुलाया जाने लगा है. लिटरेचर फेस्टिवल से जुड़े लोगों का कहना है कि सितारों के आने से भीड़ अवश्य जुट जाती है लेकिन इन मेलों के मूल उद्देश्य, साहित्य पर गंभीर चिंतन की पूर्ति नहीं हो पाती है. कई बार तो इन सितारों की खातिरदारी या लेटलतीफी की वजह से सत्रों को छोटा भी करना पड़ता है या अन्य सत्रों को रद्द भी करना पड़ता है. मेले के आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि साहित्योत्सवों में आने वाले सितारों पर जितना पैसा खर्च होता है. उसका असर लेखकों पर पड़ता है और यह सिर्फ भारत में होता है ऐसा नहीं है. पूरी दुनिया में लिटरेचर फेस्टिवल में सितारों की चमक महसूस की जा सकती है. बेस्टसेलर उपन्यास चॉकलेट की लेखक जॉन हैरिस ने भी एक बार कहा था कि कई लिटरेचर फेस्टिवल इन सितारों के चक्कर में लेखकों पर होने वाले खर्चे में भारी कटौती करते हैं. आयोजकों को लगता है कि सितारों के आने से ही उनको हेडलाइन मिलेगी. उन्होंने कहा था कि हाल के दिनों में लिटरेचर फेस्टिवल की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है लेकिन लेखकों को इससे बहुत फायदा नहीं हुआ है.

जब हमारे देश में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी तब शायद ही किसी को अंदाज़ा रहा हो कि ये फेस्टिवल अंतराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाने के बाद अंतराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के अलग-अलग देशों में आयोजित होगा. जयपुर में आयोजित ये लिटरेचर फेस्टिवल साल दर साल मजबूती से साहित्य की दुनिया में अपने को स्थापित कर रहा है. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी सितारों और विवादों की खासी भूमिका रही है. सितारों की चमक से जयपुर लिटरेटर फेस्टिवल चमकता रहता है. आपको वहां फिल्मों से जुड़े जावेद अख्तर, शबाना आज़मी, शर्मिला टैगोर, गुलज़ार आदि किसी न किसी स्टॉल पर किसी न किसी सेशन में अवश्य मिल जाएंगे. प्रसून जोशी भी. यहां तक कि अमेरिका की मशहूर एंकर ओपरा विनफ्रे भी यहां आ चुकी हैं. इन सेलिब्रिटी की मौजूदगी में बड़े लेखकों की उपस्थिति दब जाती है. इन लिटरेचर फेस्टिवल में प्रसिद्धि की एक वर्ण-व्यवस्था दिखाई देती है. इसको साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है. यह सिर्फ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ही नहीं बल्कि दुबई के लिट फेस्ट से लेकर एडिनबर्ग इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में भी देखा जा सकता है. लेखकों में भी सेलिब्रिटी की हैसियत या फिर मशहूर शख्सियतों की किताबों या फिर उनके लेखन को गंभीर साहित्यकारों या कवियों पर तरजीह दी जाती है. यह सब किया जाता है पाठकों के नाम पर. लंदन में तो इन साहित्यक आयोजनों में मशहूर शख्सियतों को लेखकों की बनिस्पत ज्यादा तवज्जो देने पर पिछले साल खासा विवाद हुआ था. यह आवश्यक है कि इस तरह के साहित्यक आयोजनों की निरंतरता के लिए मशहूर शख्सियतों का उससे जुड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि विज्ञापनदाता उनके ही नाम पर राशि खर्च करते हैं. विज्ञापनदाताओं को यह लगता है कि जितना बड़ा नाम कार्यक्रम में शिरकत करेगा उतनी भीड़ वहां जमा होगी और उसके उत्पाद के विज्ञापन को देखेगी, लिहाज़ा आयोजकों पर उनका भी दबाव होता है. परंतु सवाल यही है कि क्या इस तरह के आयोजनों में साहित्य या साहित्यकारों पर पैसे को तरजीह दी जानी चाहिए. कतई नहीं. अगर उद्देश्य साहित्य पर गंभीर विमर्श है, अगर उद्देश्य पाठकों को साहित्य के प्रति संस्कारित करने का है तब तो हरगिज़ नहीं. हां, अगर उद्देश्य साहित्य के मार्फत कारोबार करना है तो फिर इस तरह से लटके-झटके तो करने ही होंगे.

अब अगर हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को ही लें तो यह साफ हो गया है कि आठ नौ साल के अंदर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने विश्व के साहित्यक पटल पर अपना एक स्थान बना लिया है. इसको विश्व में लोकप्रिय बनाने में इसके आयोजकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और वी एस नायपाल से लेकर जोनाथन फ्रेंजन तक की भागीदारी इस लिटरेचर फेस्टिवल में सुनिश्चित की गई. अब इस लिटरेचर फेस्टिवल को आयोजकों ने विश्व के अन्य देशों में ले जाने का फैसला किया. इस क्रम में पहले लंदन में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया. इस साल मई में लंदन के साउथबैंक सेंटर में दो दिनों तक लेखकों ने साहित्य और राजनीति के सवालों से मुठभेड़ की. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को आयोजित करनेवाले लेखक द्वय नमिता गोखले और विलियम डेलरिम्पल ने लंदन में भी सफलतापूर्व इसका आयोजन किया जिसमें कई भारतीय लेखकों ने भी शिरकत की. जयपुर की तरह लंदन के दो दिनों के फेस्टिवल में मुफ्त में प्रवेश नहीं था बल्कि एक निर्धारित शुल्क लेकर श्रोताओं को प्रवेश दिया गया. लंदन में सफलतापूर्वक आयोजन के बाद अब जयपुर लिटरेचर फेस्विवल अमेरिका जा रहा है. अठारह से लेकर बीस सितंबर तक अमेरिका में अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा. आयोजकों का दावा है कि अमेरिका में होने वाले इस लिटरेचर फेस्टिवल में करीब सौ से ज्यादा लेखक शामिल होंगे. कोलोराडो में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में लेखकों के साथ विमर्श के अलावा राजनीति और पर्यावरण की चिंताओं पर भी बात होगी. इसका मतलब यह है कि ये लिटरेचर फेस्टिवल लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक खास बात यह है कि इसमें विमर्श पर भी तवज्जो दी जाती है. लेकिन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजकों ने यह साबित कर दिया कि हमारे देश में साहित्य का बहुत बड़ा बाज़ार है. उसने यह भी साबित कर दिया कि साहित्य और बाज़ार साथ-साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं. साबित तो यह भी हुआ कि बाज़ार का विरोध करने वाले नए वैश्विक परिवेश में कहीं न कहीं पिछड़ते जा रहे हैं. पिछड़ते तो वो पाठकों तक पहुंचने में भी जा रहे हैं. इसके विरोध में तर्क देने वाले यह कह सकते हैं कि यह अंग्रेजी का मेला है लिहाज़ा इसको प्रायोजक भी मिलते हैं और धन आने से आयोजन सफल होता जाता है. सवाल फिर वही कि हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में हमने कोई कोशिश की? बगैर किसी कोशिश के अपने ठस सिद्धातों पर यह मान लेना कि हिंदी में इस तरह का भव्य आयोजन संभव नहीं है, गलत है. आसमान में सूराख हो सकता है जरूरत इस बात की है कि पत्थर जरा तबीयत से उछाला जाए.

विवादों ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को खासा चर्चित किया. आयोजकों की मंशा विवाद में रही है या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन इतना तय है कि विवाद ने इस आयोजन को लोकप्रिय बनाया. चाहे वो सलमान रश्दी के कार्यक्रम में आने को लेकर उठा विवाद हो या फिर आशुतोष और आशीष नंदी के बीच का विवाद हो, सबने मिलकर इस फेस्टिवल को साहित्य की चौहद्दी से बाहर निकालकर आम जनता तक पहुंचा दिया. नतीजा यह हुआ कि साहित्य का ये फेस्टिवल धीरे-धीरे मीना बाज़ार, यह शब्द इस स्तंभ में कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है, बन गया. आयोजकों को स्पांसरशिप से फायदा हुआ तो इस फेस्टिवल का दायरा और इसका प्रोडक्शन बेहतर होता चला गया.■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

साहित्य की भाषा पर घमासान

नीलोत्पल मृणाल

आज के नये दौर में जब समाज और साहित्य दोनों तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब आपको हिंदी के साहित्यिक गलियारों में अक्सर एक विमर्श सुनने को मिल जायेगा कि आख़िर वर्तमान साहित्य की भाषा कैसी है और कैसी होनी चाहिए? ख़ासकर युवा लेखकों के संदर्भ में तो यह और भी ज़रूरी जिरह का मुद्दा बना रहता है. ये मुद्दा तब और विमर्शकारी होता जा रहा है जब एकाएक सोशल मीडिया और अन्य आधुनिक संचार माध्यमों के रास्ते हिंदी साहित्य के मंच पर लगातार नये लेखकों का आगमन हो रहा है. ये लेखक अपनी लेखनशैली और भाषा के स्तर पर एक खास शास्त्रीय मान्यताओं से मुक्त हैं. अब इनकी भाषा स्तरीय है या नहीं यह मामला इतर है. एक नए लेखक के रूप में जब मैं अपना पहला उपन्यास लिखने बैठा तो मेरे सामने भी ये एक कठिन चुनौती थी कि आख़िर मेरी भाषा कैसी हो? शब्दों का चयन कैसा हो? ये चुनौती तब और भी गंभीर लगी, क्योंकि मैंने मन ही मन अपनी भूमिका गढ़ रखी थी कि मुझे यथार्थ लिखना है. हिंदी के एक नए लेखक के सामने एक तरफ यशपाल जी की 'दिव्या' की अलंकारिक भाषा का उदाहरण खड़ा है तो दूसरी तरफ काशीनाथ सिंह का 'काशी का अस्सी' जैसा झन्नाटेदार आइटम भी प्रयोग के लिए उपलब्ध है. फिर मैंने सोचा कि क्या आप अपने पात्रों की भाषा किसी से सीखकर या किसी भाषाई पंडित से पूछ कर, ठोक-बजा कर प्रमाण पत्र लेकर लिखेंगे? क्या कोई लेखक अपने किरदार पहले गूंगा पैदा करता है और उसमें फिर अपनी मर्ज़ी की बोली डालता है? ये तो किसी मुर्दे में किसी और की आत्मा डालने वाली बात हो गई. आपके गढ़े किरदार की भी अपनी एक स्वाभाविक भाषा या बोली होती है और आप जब कोई किरदार गढ़ते हैं, तो केवल उस किरदार और उसके हालात का ही यथार्थ नहीं लिखते बल्कि उस किरदार की स्वाभाविक भाषा में ही इसे बयान भी किया जाना चाहिए. तब ही किरदार आपको जिंदा नज़र आएंगे. भाषा में शूचिता हो या लत्तम-जूता हो, देशीपन हो कि शास्त्रीय अलंकार हो, ये लेखक नहीं बल्कि उसके गढ़े पात्र तय करते हैं. मेरे ही उपन्यास की भाषा को लेकर आलोचना हुई कि इसमें गाली गलौच और कुछ देशी शब्दों का प्रयोग ज्यादा हो गया है. अब कोई बताए कि आप जब एक 21वीं सदी के गांव से आये और शहर में पढ़-लिख रहे उत्तर भारतीय लड़कों की ज़िंदगी पर कोई उपन्यास लिख रहे हों तो ये कैसे संभव है कि आप अबे साले की जगह मान्यवर, सिगरेट को धूम्रदंडिका और लैपटॉप को उच्चगोद कहें. जो शब्द आपके आसपास हैं ही नहीं, वे शब्दकोष से घसीटकर अपने पात्रों के मुंह में घुसेड़ कर हम हिंदी पांडित्य परंपरा के कौन से पुरोहित हो जाएंगे.

साहित्य की भाषा पर माथापच्ची करना हिंदी विमर्श के कुछ उन प्रमुख विषयों में से है, जिनपर चर्चा का सिलसिला अनवरत जारी रहता है. साहित्य की भाषा कैसी हो? इस यक्ष प्रश्न का जवाब कई बड़े साहित्यकारों ने दिया है. इस विषय को लेकर अक्सर हो-हल्ला मचता है कि उपन्यास लेखन या किसी अन्य लेखन के दौरान साहित्यकार अपनी भाषाई मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं. अपने उपन्यास 'ओस की बूंद' की प्रस्तावना में राही मासूम रज़ा ने भी इस विषय का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि बड़े-बूढ़े ये समझाते हैं कि अगर 'आधा गांव' में इतनी गालियां न बकी होतीं तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार निश्चित था. रज़ा साहब ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि मैं कोई तानाशाह नहीं हूं जो अपने पात्रों को आदेश दूं- यह बोलो, वह बोलो. साहित्य की भाषा को लेकर युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल की भी अपनी धारणाएं हैं, जो साहित्यकार राही मासूम रज़ा से काफी कुछ मेल खाती हैं.

देखा जाय तो कई साहित्याधीशों ने अपना मठ बना रखा है और आप अगर उनकी परंपरा के मानक शब्दों से इतर लिखेंगे तो भ्रष्ट माने जाएंगे. ऐसे तो किसी भी भाषा का क्या भला होगा? भाषा बहता पानी है, इसमें जितने देशी-विदेशी मीठे बोल मिलेंगे ये और समृद्ध होगी. आज की कमाऊ भाषा अंग्रेजी ने ही अपने में लैटिन और फ्रेंच के कई शब्द अपनाये, इससे वह कंगाल नहीं बल्कि और धनवान ही हुई. आज कई लेखक हिंदी की रचनाओं में भी अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग भी कर रहे हैं और पात्रों के संदर्भ में ये स्वाभाविक भी लगती है. हां, लेकिन अंग्रेजी शब्द के चक्कर में हिंदी लिपि से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. एक तरफ आप यथार्थ भी लिखने की घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ आस-पास और खुद उपयोग में लाई जाने वाली भाषा से बचते हैं. ये कैसा यथार्थ है? साहित्य का वजन उसके पूरे शिल्प और संवेदना व उसकी स्वाभाविक गति और परिणति से बढ़ता है, प्रत्येक पन्ने पर भारी-भरकम शब्दों को धर देने से नहीं. अगर आप आज भी रामायण और महाभारत का पुनर्लेखन करेंगे तो उसकी भाषा आपके बिना उठा-पटक किए भी परिमार्जित और तत्समी हो जायेगी. लिखते वक्त एक समस्या ये भी आती है कि आप जब अपने अर्जित अनुभव और ज्ञान के हवाले से कुछ लिख रहे होते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए इसे लिख भले हम रहे हैं पर इसे पढ़ना पाठकों को है.

अक्सर आपको तो अपनी लिखी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, पर बात आपके पाठक के समझ आयेगी कि नहीं. इस बात को सृजन करते हुए कभी भी अपने मानसिक पटल से नहीं हटाना चाहिए. इसके बाद ही हमें भारी भरकम शब्द अपनी पुस्तकों या लेखों में चिपकाने चाहिए. हम लेखक अक्सर अपने पाठकों की समझ सकने की क्षमता पर कम और अपनी देयता पर अधिक फोकस होते हैं. ये देने का सुख वाला आत्मसंतोष लेखक और पाठक के बीच बाधक बन सकता है. शब्द देशज हों या विदेशी, तत्सम हों या तद्भव. एक तो पात्रों की स्वभाविक भाषा हो और दूसरा वे अधिकतर उपयोग में आती हों. भले उसे एक-दो खास क्षेत्र का ही आदमी समझ पाये. जब आप कहानी इलाहाबाद या भागलपुर पर लिखेंगे तो ये उम्मीद रखना ही बेमानी है कि कुछ शब्द इसमें फ्रेंच के भी होते तो इसे पेरिस वाले भी समझ लेते. हां, ये बात भी सत्य है कि कुछ लोग यथार्थ के नाम पर अति करते हैं और यथार्थ व प्रगतिशिलता की ओट में खूब अश्लील और गैरज़रूरी भाषा ठूंस-ठूंस कर अपनी कुंठा का प्रदर्शन करते हैं. कुछ लोग इसे प्रसिद्ध होने का चलताऊ हिट मसाला बनाकर खूब उपयोग में लाते हैं. ऐसे लोगों और लेखन का बहिष्कार होना ही चाहिए. रही बात भाषाई शुद्धि और शूचिता के विमर्श की तो ज़रूरी ये है कि हम जितना माथापच्ची साहित्य की भाषा पर करते हैं उतना समाज की भाषा पर कर लें तो शायद वह ज्यादा फलकारी हो. हमें साहित्य नहीं बल्कि समाज पर काम करने की ज़रूरत है. आपका समाज जैसा बोलेगा, साहित्य वैसा लिखेगा. क्योंकि अंततोगत्वा सब जानते हैं कि साहित्य समाज का ही तो दर्पण है. सो आइए साहित्य की नहीं, अपनी भाषा पर बात करें.■

(लेखक युवा साहित्यकार हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
چوتھی دنیا

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

कंपनी ने इस टैबलेट को 8 इंच और 9.7 इंच की दो साइज में उतारा है. इससे पहले सबसे पतले टैबलेट्स का रिकॉर्ड एप्पल एयर3, सोनी एक्सपीरिया और जेड4 के नाम था. ये कंपनियां 6.1 एमएम साइज़ के टैबलेट्स लॉन्च कर चुकी है. यह टैबलेट अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. कंपनी ने इनमें सुपर अमोलेड डिस्प्ले दिया है, जिसका रेजोल्यूशन 2048X1536 मेगा पिक्सल है.

यामाहा की दमदार बाइक आर3

यामाहा 300–350 सीसी की बाइक सेगमेंट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अपनी बहुप्रतीक्षित वाईजेडएप–आर3 को भारत में लॉन्च करने जा रही है. पहले खबरे थीं कि कंपनी आर25 को आर3 की जगह लॉन्च कर सकती है, लेकिन कंपनी ने केटीएम आरसी 390, केटीएम निंजा 300 और अन्य बड़ी बाइक्स से टक्कर लेने के लिए इस बाइक को उतारने का मन बनाया है. वाईजेडएफ–आर3 मूल रूप से आर25 जैसी ही है. आर3 का इंजन आर25 का ही बोर्ड आउट वर्जन है. आर3 इंजन की परफॉर्मेंस आर25 से बेहतर है. आर3 में कंपनी ने 320सीसी का ट्विन–सिलिंडर इंजन लगाया है, जो 29.5 का टॉर्क और 41 बीएचपी की पावर देता है. इस बाइक के डिजाइन के बारे में बात की जाए, तो यह काफी कुछ आर25 जैसा ही है. लेकिन थोड़े–बहुत बदलावों के साथ यह पिछली बाइक के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी नजर आती है. दोनों मॉडल्स में एक जैसा डायमेंशन, बॉडी पैनल और डायमंड टाइप फ्रेम है. आर3 के डिजाइन का कुछ हिस्सा वाईजेडएप–आर से लिया गया है. खास तौर पर ड्युल हेडलैंप, 10– स्पोक अलॉय वील, डिजिटल–एनलॉग कंसोल और साइलेंसर. इस बाइक का वजन 169 किलोग्राम है. ■

आर3 का इंजन आर25 का ही बोर्ड आउट वर्जन है. आर3 इंजन की परफॉर्मेंस आर25 से बेहतर है. आर3 में कंपनी ने 320सीसी का ट्विन–सिलिंडर इंजन लगाया है, जो 29.5 का टॉर्क और 41 बीएचपी की पावर देता है.

वाटरप्रूफ स्पीकर के साथ पूल पार्टी करें

म्यूजिक पसंद लोगों के लिए बााजर में कई तरह के स्पीकर उपलब्ध हैं. इनमें होम थिएटर से लेकर पार्टेबल, ब्लूटुथ वाई–फाई, वाटरप्रूफ कई कैटेगरी शामिल हैं. कई स्पीकर ऐसे भी हैं जो वाटरप्रूफ होने के साथ पानी में भी तैर सकते हैं. इस कैटेगरी में इवेशन (Ivation) वाटरप्रूफ ब्लूटुथ स्विमिंग फ्लोटिंग स्पीकर शामिल है. ब्लूटुथ कनेक्टिविटी के साथ आने वाला ये स्पीकर पानी में तैर सकता है. साथ ही, इसका इस्तेमाल आप बारिश के मौसम में भी कर सकते हैं. सभी डिवाइस से कनेक्टिविटी 10 मीटर रेंज है. इस स्पीकर की सबसे खास बात है कि 33 फीट पानी के अंदर भी बेहतर साउंड क्वालिटी देता है. इसे यूजर्स अपने स्मार्टफोन के साथ फैबलेट, टैबलेट, लैपटॉप, कम्प्यूर या अन्य किसी ब्लूटुथ डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसकी खास बात है कि ये पानी में तैरता है. यानी आप पानी के अंदर इसे डुबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये छूटते ही ऊपर आ जाएगा. हालांकि, इसमें बिल्ट–इन बैटरी नहीं है. ये 6 बैटरी के साथ काम करता है. यूजर्स इसको 10 मीटर के दायरे में इसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है. इस स्पीकर का वजन 2 पाउंड यानी लगभग 907 ग्राम है. इसका डायमेंशन 6.9 x 6.8 x 6.7 इंच है. ये मल्टी कलर ऑप्शन में मौजूद है. इस स्पीकर की कीमत 5,128 रुपये है. ■

लावा का स्मार्टफोन पिक्सेल वी1

लावा इंटरनेशनल ने नया स्मार्टफोन पिक्सेल वी1 लांच किया है. इस फोन की इंटरनल मेमोरी 32 जीबी की है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 32 जीबी अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है. इस स्मार्टफोन में 1.3 क्वॉड–कोर

इस स्मार्टफोन में 1.3 क्वॉड–कोर प्रोसेसर और एक 2जीबी रैम का इस्तेमाल किया गया है. इसका रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है. फोन की बैटरी 2,650 एमएएच की है. इसका आईपीएस डिस्प्ले 5.5 इंच का है.

प्रोसेसर और एक 2जीबी रैम का इस्तेमाल किया गया है. इसका रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है. फोन की बैटरी 2,650 एमएएच की है. इसका आईपीएस डिस्प्ले 5.5 इंच का है. इस फोन में 4जी की सुविधा नहीं है. गूगल के एंड्रॉयड वन ऑपरेटिंग सिस्टम वाले इस स्मार्टफोन की कीमत 11,350 रुपये है. ■

दुनिया का सबसे पतला टैबलेट

सैमसंग ने स्लिम टैबलेट बाजार पर कब्जा जमाने के लिए गैलेक्सी टैब एस2 नाम से नया टैबलेट लॉन्च किया है. सैमसंग गैलेक्सी टैब एस2 टैबलेट की मोटाई महज 5.6 इंच है. इसी के साथ यह दुनिया का सबसे स्लिम टैबलेट है. यह दुनिया का सबसे पतला टैबलेट है. कंपनी ने इस टैबलेट को 8 इंच और 9.7 इंच की दो साइज में उतारा है. इससे पहले सबसे पतले टैबलेट्स का रिकॉर्ड एप्पल एयर3, सोनी एक्सपीरिया और जेड4 के नाम था. ये कंपनियां 6.1 एमएम साइज़ के टैबलेट्स लॉन्च कर चुकी है. यह टैबलेट अगस्त से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. कंपनी ने इनमें सुपर अमोलेड डिस्पले दिया है, जिसका रेजोल्यूशन 2048X1536 मेगा पिक्सल है. ये एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.0 ओएस पर काम करते हैं. इन दोनों टैबलेट्स में 64 बिट ऑक्टोकोर सैमसंग एग्जीनॉस 7420 प्रोसेसर, 3 जीबी रैम, 8 एमपी का रियर कैमरा और 2.1 एमपी का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इन दोनों ही टैबलेटस में 32 जीबी और 64 जीबी मेमोरी वेरियंट्स दिए गए हैं. इसके अलावा दोनों में 128 जीबी तक का मेमोरी कार्ड लगता है. इसमें 4000 एमएएच की बैटरी दी गई है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मारुति सुज़ुकी की डीजल कार एस–क्रास

मारुति सुज़ुकी अपनी नई कार एस–क्रास को लेकर आई है. इस कार की लंबाई 4300एमएम और चौड़ाई 1756एमएम रखी गई है. एस–क्रास की ऊंचाई (रूफ–रेल के साथ) 1590एमएम है. वही कार की व्हीलबेस 2600एमएम, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 180एमएम और टर्निंग रेडियस 5.2एम है. इस कार की सीटिंग कैपेसिटी 5 सीटर है. इस कार का फ्यूल टैंक 48 लीटर है. एस–क्रास दो डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ बाज़ार में उपलब्ध होगी, जिसमें 1.3–लीटर डीडीआईएस और 1.6–लीटर डीडीआईएस इंजन शामिल है. इस कार का पेट्रोल मॉडल नहीं है. भारत में लॉन्च होने वाली एस–क्रास में फ्रंट व्हील ड्राइव होगा. इस कार की कीमत लगभग 8 लाख रुपये है. ■

दिलशान ने पार किया 10,000 रनों का आंकड़ा

श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए. ऐसा करने वाले वह दुनिया के 11वें बल्लेबाज बन गये हैं. पाकिस्तान के खिलाफ हंबनटोटा में वनडे इंटरनेशनल मैच में अपनी 62 रनों की पारी के दौरान वनडे क्रिकेट में 10 हजार रन भी पूरे किए और इसके साथ ही दिलशान ने वनडे मैचों में 10,008 रन और 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं. दिलशान के नाम 22 शतक और 45 अर्धशतक दर्ज हैं. उनका औसत 39.71 है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ 1999 में बुलावायो में अपने वनडे करियर की शुरूआत करने वाले दिलशान श्रीलंका के चौथे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए. दिलशान ने सर्वाधिक 2255 रन भारत के खिलाफ बनाए हैं. वनडे मैचों में सबसे कम पारियों में 10 हजार रन बनाने का रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने अपने 10 हजार रन पूरे करने के लिये केवल 259 पारियां खेली थीं.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 या इससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में भारत के सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 18,426 बनाए हैं, जबकि कुमार दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 14,234 रन बनाया है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने 13,704 बनाए हैं. श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने कुल 13, 430 रन, श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने ने वनडे में 12,650 रन बनाए हैं.

इनके बाद नंबर आता है पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम उल हक का जिन्होंने वनडे में 11,739 रन बनाए हैं, इस लिस्ट में अगला नाम है साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर रहे जैक कैलिस का जिन्होंने वनडे में कुल 11,579 रन किए हैं. पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली 11,363 रनों के साथ इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हैं. इंडियन बैटिंग की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ ने वनडे में 10,889 रन बनाए हैं. उनके बाद सर्वकालिक बल्लेबाजों में महानतम माने जाने वाले वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा का नंबर है, जिन्होंने 10, 405 रन और फिर लंका के आक्रामक बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान हैं. जिन्होंने 10,008 रन बनाए हैं.

दिलशान ने हालांकि श्रीलंका की तरफ से सबसे कम पारियों में इस मुकाम पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाया है. अपना 319वां मैच खेल रहे इस 38 वर्षीय बल्लेबाज ने 293वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की.■

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को मिलेगा 5 करोड़: आनंदीबेन

गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने ऐलान किया है, कि राज्य का कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतता है, तो उसे पांच करोड़ रूपये का इनाम दिया जाएगा. मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ओलंपिक में गुजरात से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को पांच करोड़ रूपये का इनाम देना उनका सपना है.

यह ऐलान अगले साल रियो डी जनेरियो (5 से 21 अगस्त) में होने वाले ओलंपिक खेलों से पहले किया गया है. आनंदी बेन पटेल वडोदरा में सामा इंडोर स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद रेजिडेंशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अकादमी का उद्घाटन करने के बाद बोल रही थीं.

क्रिस फ्रूम ने जीती टूर डी फ्रांस रेस

ब्रिटेन के क्रिस फ्रूम ने 102वीं टूर डी फ्रांस साइक्लिंग रेस को जीत लिया है. इस साइक्लिंग मैराथन में यह क्रिस फ्रूम की दूसरी जीत है.

रेस जीतने के बाद विजेता की पीली जर्सी पहने हुए फ्रूम ने कहा कि वास्तव में यह बहुत कठिन टूर है और मुझे खुशी है, जो मैं यहां पीली जर्सी में खड़ा हूं. रेस के दौरान क्रिस पर झगड़ने, बेइज्जती करने और धोखेबाजी के आरोप भी लगे थे. यहां तक की उनपर मूत्र भी फेंका गया था. टूर डी फ्रांस जैसी साइक्लिंग की सबसे कठिन मैराथन रेस में कोलंबिया के नाइरो कुईन्टाना दूसरे और स्पेन के अलेजांद्रो वालवेर्द तीसरे स्थान पर रहे.■

श्रीसंत आत्महत्या करना चाहते थे

श्रीसंत ने कहा, मैंने बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर से मिलने का समय मांगा है. उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा था कि मैं प्रतिबंध हटाने के लिए आग्रह कर सकता हूं. उन्होंने कहा, बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारियों ने जो संकेत दिए हैं उससे मेरी उम्मीद बंधी है कि वे मेरे आग्रह पर विचार करेंगे.

श्रीसंत जब तिहाड़ जेल में थे, तो आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को अब उम्मीद जगी है कि वह वापसी कर सकते हैं और उनके ऊपर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए वह बीसीसीआई से संपर्क साधेंगे. दिल्ली की एक अदालत ने श्रीसंत को पिछले सप्ताह 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले से बरी कर दिया था. श्रीसंत ने कहा, मैंने बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर से मिलने का समय मांगा है. उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा था कि मैं प्रतिबंध हटाने के लिए आग्रह कर सकता हूं. उन्होंने कहा, बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारियों ने जो संकेत दिए हैं उससे मेरी उम्मीद बंधी है कि वे मेरे आग्रह पर विचार करेंगे. इसलिए मैं आवेदन भेजना चाहता हूं. मैं उनके (सचिव अनुराग ठाकुर) जवाब का इंतजार कर रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि बीसीसीआई के साथ अगली बैठक में बीसीसीआई उम्मीद के मुताबिक फैसला करेगा.श्रीसंत ने उस दौर के दर्द को भी बयां किया, जब उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था और उन पर कथित तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम और उसके साथी छोटा शकील द्वारा चलाए जा रहे क्रिकेट के सट्टेबाजी रैकेट से जुड़े होने के आरोप लगाए गए थे.

श्रीसंत से पूछा गया कि क्या उन्हें बीसीसीआई से अनुकूल जवाब की उम्मीद है जिसकी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीयू) के मुख्य सलाहकार दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त नीरज कुमार हैं, तो श्रीसंत ने कहा कि आखिरकार वह भी इंसान हैं. उनका भी दिल है.

उन्होंने कहा कि यदि कुमार, जिन्होंने दिल्ली पुलिस प्रमुख रहते हुए श्रीसंत के अलावा अजित चंदीला और अंकित चव्हाण की गिरफ्तार के भी आदेश दिए थे, 2013 आईपीएल स्पाट फिक्सिंग मामले के घटनाक्रम को याद करें तो उनके सामने तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी. श्रीसंत ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वे मेरी राह में कोई बाधा खड़ी करेंगे. बीसीसीआई एक संस्था है एक व्यक्ति नहीं.

श्री संत ने कहा कि यदि बीसीसीआई प्रतिबंध नहीं हटाता तो वह अदालत की शरण में नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा, मैं इंतजार करूंगा. मैं किसी को चुनौती नहीं देना चाहता. मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं. श्रीसंत ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया कि उन्होंने सोमवार को जवाहर लाह नेहरू अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में नेट पर अभ्यास किया था. उन्होंने कहा कि वह आजीवन प्रतिबंध हटने के बाद इस मैदान पर अभ्यास करेंगे.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट

लाहड़ी की शीर्ष स्थिति मजबूत

भारतीय गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिड़ी ने यूरोपीयन मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट में शानदार पांचवां स्थान हासिल करते हुए एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट में अपनी शीर्ष स्थिति और मजबूत कर ली. रोपीयन मास्टर्स यूरोप की जमीन पर खेला जाने वाला एक मात्र गोल्फ टूर्नामेंट है, जिसे यूरोपीयन टूर और एशियन टूर दोनों से मान्यता प्राप्त है. लाहिड़ी मलेशिया में दो जबकि भारत में एक खिताब जीत चुके हैं और उनकी कमाई 9,25,484 डॉलर पहुंच चुकी है, जो दूसरे स्थान पर मौजूद आस्ट्रेलिया के एंड्र डॉड्ट से काफी अधिक है. लाहिड़ी पिछले दो सत्रों में ऑर्डर ऑफ मेरिट में क्रमश: तीसरे और दूसरे स्थान पर रहे और लगातार सुधार करते हुए सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने.

लाहिड़ी की नजरें अब एक सत्र में 10 लाख डॉलर की कमाई पार करने वाले एशियन टूर का तीसरा खिलाड़ी बनने पर है. अब तक यह कीर्तिमान जीव मिल्खा सिंह और थाईलैंड के किराडेक अफिबार्नराट स्थापित कर सके हैं.

लाहिड़ी ने कहा कि वर्ष के आखिर तक मैं एशियन टूर में चार-पांच टूर्नामेंटों में हिस्सा लेने वाला हूं. उम्मीद है मैं उनमें अपने बेहतर प्रदर्शन को कायम रख पाउंगा और अंतत: इस कीर्तिमान तक पहुंचना अच्छा

रहेगा. 2013 में मैं तीसरे स्थान पर रहा और दूसरा स्थान हासिल कर सका. इसलिए इस वर्ष ऑर्डर ऑफ मेरिट में शीर्ष पर रहना बेहतर होगा.■

बोल्ट ने फिर जीता फर्राटा का खिताब

यूसैन बोल्ट ने वर्षा प्रभावित लंदन डायमंड लीग में 100 मीटर फर्राटा दौड़ का खिताब अपने नाम किया. बोल्ट ने इस जीत के साथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों को आगाह कर दिया है. ओलंपिक चैम्पियन और वर्ल्ड कीर्तिमानधारी बोल्ट ने छह सप्ताह बाद ट्रैक पर वापसी करते हुए 9.87 सेकंड में पहला स्थान हासिल किया. बोल्ट बाएं पैर में चोट से जूझ रहे हैं. अमेरिका के माइकल रॉजर्स ने 9.90 सेकंड के साथ दूसरा तथा जमैका के केमार बैली-कोल ने 9.92 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया.

बोल्ट ने लंदन ओलिंपिक स्टेडियम में इससे पहले हीट में भी यही समय निकाला था. इस वर्ष उन्होंने इससे पहले ब्राजील में 10.12 सेकंड का समय निकाला था. अमेरिका के जस्टिन गैटलिन के नाम इस सत्र का सबसे तेज समय (9.74 सेकंड) दर्ज है और बीजिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उनके और बोल्ट के मुकाबले का सबको इंतजार है. बोल्ट ने कहा कि कुल मिलाकर यह अच्छी रेस रही, मैं तेज दौड़ना चाहता था, लेकिन मेरी शुरुआत अच्छी नहीं रही और इसी वजह से मैं बेहतरीन समय नहीं निकाल पाया. मुझे बीजिंग के पहले अच्छी तैयारी करनी होगी.■

सबकी परवाह करने वाले थे कलाम: अमिताभ

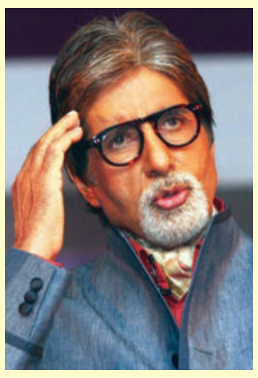

अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि वह बच्चों जैसे व्यवहार वाले व्यावहारिक, सबसे प्यार और सबकी परवाह करने वाले सीधे-सादे व्यक्ति थे. मेरी उनके साथ संपर्क की एकमात्र उपलब्धि वह एक टेलीफोनिक बातचीत है...

महानायक अमिताभ बच्चन पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के निधन से दुखी हैं. उन्होंने बताया कि कैसे ए.पी.जे अब्दुल कलाम के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने का अवसर मिला था. अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि वह बच्चों जैसे व्यवहार वाले व्यावहारिक, सबसे प्यार और सबकी परवाह करने वाले सीधे-सादे व्यक्ति थे. मेरी उनके साथ संपर्क की एकमात्र उपलब्धि वह एक टेलीफोनिक बातचीत है, जो उन्हें भारत का अगला राष्ट्रपति घोषित किए जाने से पहले हुई थी. भारत शोक संतप्त है.

अमिताभ ने लिखा कि एक प्रतिष्ठित हस्ती का आकस्मिक अंत. विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपस्थिति, मिसाइल तकनीक और अंतरिक्ष शोध से संबंधित कई अन्य उपलब्धियों के पीछे उन्हीं का दिमाग था. उन्होंने इन सुविधाओं के क्षेत्र में भारत को विश्व के पटल पर स्थापित किया. अमिताभ ने प्रार्थना की कि कलाम के परिवार को इस दुख को सहने की हिम्मत मिले.■

सुल्तान में सलमान खान के रोल का खुलासा

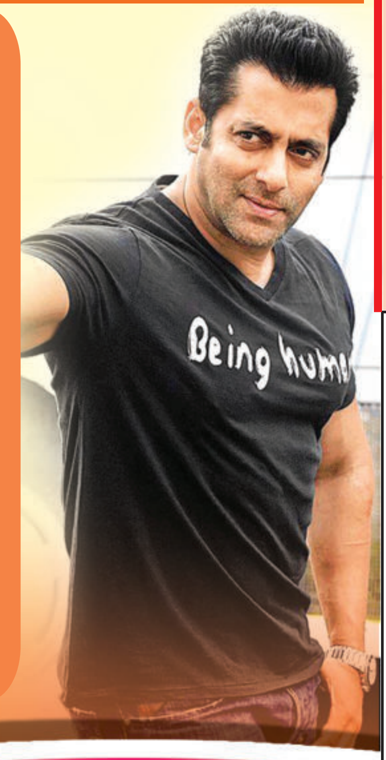

अली अब्बास जफ़र के निर्देशन में बनने वाली फिल्म सुल्तान का निर्माण यश राज फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है. जिसमें सलमान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. सलमान इस फिल्म में एक बॉक्सर का किरदार निभाएंगे. इस बॉक्सर की उम्र 40 वर्ष के आसपास होगी. इस फिल्म के लिए सलमान लगभग 15 किलो वजन भी बढ़ाएंगे. आमतौर पर सलमान अपनी भूमिका के लिए विशेष तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन सुल्तान की शूटिंग के पहले उन्हें काफी मेहनत करनी होगी. 14 अगस्त को रिलीज होने वाली ब्रदर्स में अक्षय कुमार भी बॉक्सर के रोल में हैं, जबकि आमिर खान दंगल में पहलवान बनेगें.

बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म कर सलमान ने संकेत दिए हैं कि वे भी अच्छे कंटेंट वाली फिल्म करना चाहते हैं, जिसे दर्शकों और आलोचकों का समान प्यार मिले. भारत में ही नहीं बल्कि सीमा पार भी सलमान की फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई. यही वजह है कि उन्होंने सुल्तान का हिस्सा बनना मंजूर किया है.■

हॉलीवुड ख़बर

किस बात से सिहर उठती थीं सलमा हयाक

हॉलीवुड अभिनेत्री सलमा हयाक का कहना है कि उन्हें बढ़ती उम्र का डर सताता था और 50 की होने केख्याल से ही वह सिहर उठती थीं, सलमा हयाक इस साल सितंबर में 49 साल की हो जायेंगी. सलमा हयाक ने माना कि उन्हें उम्रदराज होने से डर लगता था. सलमा ने कहा जब मैं यह कल्पना करती थी कि ज्यादा उम्र में मैं कैसी दिखूंगी और मेरी जिंदगी कैसी होगी, तो मैं काफी डर जाती थी. मैंने खुद की उम्रदराज महिला के रूप में कल्पना की, लेकिन मुझे लगता है कि अब भी मैं ठीक दिखती हूं और अपने आप से खुश हूं. सलमा ने कहा कि अब वह 50 साल की होने को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि इस उम्र में भी महिलाओं में प्रजनन क्षमता होती है. सलमा 41 साल की उम्र में पहले बच्चे की मां बनी थीं.■

> मैं यह कल्पना करती थी कि ज्यादा उम्र में मैं कैसी दिखूंगी और मेरी जिंदगी कैसी होगी, तो मैं काफी डर जाती थी. मैंने खुद की उम्रदराज महिला के रूप में कल्पना की, लेकिन मुझे लगता है कि अब भी मैं ठीक दिखती हूं और अपने आप से खुश हूं.

हो गया दिमाग का दही

संजय-राजपाल की जोड़ी दर्शकों को गुदगुदाएगी

फिल्म जगत में संजय मिश्रा एक शानदार और बहुमुखी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं. इनका अभिनय अपने आप में इतना कुछ बोलता है कि दर्शक किसी भी फिल्म में संजय की भूमिका को नज़रअंदाज कर ही नहीं पाते. हाल में रिलीज़ हुई फिल्म मसान में संजय की भूमिका और अदायगी की तारीफ़ किसने नहीं की. निर्देशक, सहायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले संजय को उनके हास्य किरदार से असली पहचान मिली. फस गए रे ओबामा, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3, दम लगा के हईशा और अभी हाल ही में आई फिल्म मिस टनकपुर, जैसी हिट कॉमेडी फिल्में देने के बाद, एक बार फिर संजय मिश्रा लोगों को गुदगुदाने आ रहे हैं, अपनी नई फिल्म हो गया दिमाग का दही में. डेली मीडिया लिमिटेड (डीएएल) द्वारा निर्मित और फौजिया अर्शी निर्देशित इस फिल्म में संजय मिश्रा एक वकील की भूमिका में नज़र आएंगे. फिल्म के ट्रेलर में वो खुद को डाइवोर्स स्पेशलिस्ट बताते नज़र आ रहे हैं. बनारस में जन्मे संजय मिश्रा को बचपन से ही कला के प्रति आर्कषण था. वह हमेशा अपने पिता के साथ बिसमिल्ला खॉं, किशन महाराज जैसे महान कलाकारों के कार्यक्रमों में जाया करते और सबसे आगे की कतार में बैठते. फिल्म हो गया दिमाग का दही के लिए दिए गए एक इंटरव्यू में संजय मिश्रा ने बताया की बिस्मिल्लाह खॉं के एक कार्यक्रम में उन्हें यह एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसकी वजह से कम से कम 20 लोग उसे देखें.

टीवी सीरियल और ऑफिस-ऑफिस, सत्या, जॉली एल.एल.बी, किक जैसी फिल्मों में शानदार काम करने के बाद अब वो हास्य फिल्म हो गया दिमाग का दही में अपने हुनर का जलवा दिखाने आ रहे हैं. अब बस इंतजार है फिल्म दिमाग का दही में इस डाइवोर्स स्पेशलिस्ट के वकालत को देखने का. फिल्म में संजय के साथ दिखेंगे कॉमेडी के दूसरे महान कलाकार राजपाल यादव. राजपाल यादव ने बॉलीवुड में अपनी हास्य भूमिकाओं से अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है. छोटे से शहर शाहजहांपुर से मायानगरी मुम्बई तक का राजपाल यादव का सफ़र उनकी प्रतिभा, अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा और लगन की कहानी है. राजपाल यादव ने अभिनय की शुरूआत दूरदर्शन पर प्रकाश झा के सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल से की थी. टेलीविज़न धारावाहिक में मुख्य नायक का किरदार निभाने के बाद वो बॉलीवुड में किस्मत आजमाने पहुंच गए. राजपाल के उम्दा अभिनय की वजह से वो कुछ ही समय में बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकारों की सूची में शामिल हो गए. करियर की शुरुआत में ही की गई फिल्म जंगल के लिए उन्हें नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला. हंगामा, चुप-चुप के, मुझसे शादी करोगी और गरम मसाला जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया. राजपाल यादव और कॉमेडी एक ही सिक्के के दो पहलु हैं. उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में बहुत जल्द शामिल होने जा रही है फिल्म हो गया दिमाग का दही. इस फिल्म में राजपाल यादव एक बार फिर धमाकेदार हास्य भूमिका में दर्शकों को सामने नजर आएगें. फिल्म हो गया दिमाग का दही(HDKD) में राजपाल यादव एक हास्य नौकर की भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके किरदार का नाम मसाला है, जो चेहरे पर मुस्कान ला देता है.

हो गया दिमाग का दही फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें राजपाल यादव और संजय मिश्रा के साथ कॉमेडी के सुपर स्टार कादर खान, ओम पूरी और रज्जाक खान जैसे हास्य कलाकार भी दर्शकों को जी भर के हसाएंगे. यह फिल्म 25 सितंबर को रिलीज होगी, लेकिन इस फिल्म की चर्चा और आने का इंतज़ार अभी से हर तरफ हो रहा है. यू-ट्यूब पर रिलीज़ हुआ इस फिल्म का ट्रेलर भी इस फिल्म के लिए दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ा रहा है. राजपाल यादव और संजय मिश्रा ने रुपहले पर्दे पर अपनी हास्य भूमिकाओं और सहज अभिनय से प्रशंसकों के दिल में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है. फिल्म हो गया दिमाग का दही की कहानी और निर्देशन से इन बेहतरीन कलाकारों की अदाकारी और निखर के सामने आयेगी. इस फिल्म की कामयाबी का पता यूट्यूब पर रिलीज हुए इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर पता चलता है. इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

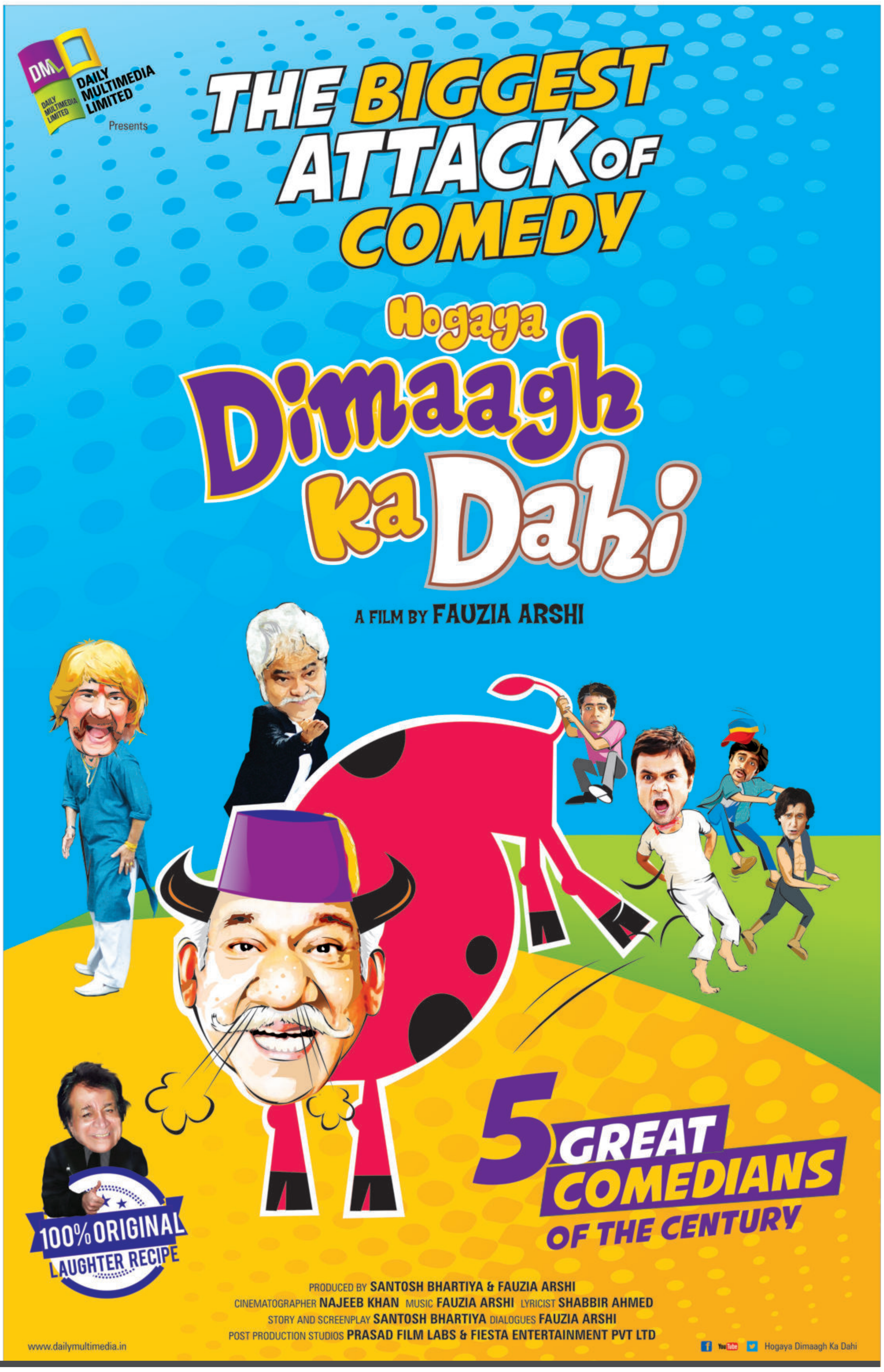

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

10 अगस्त-16 अगस्त 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

यादव सिंह ने पूरी व्यवस्था को अपना दास बना लिया हैः इलाहाबाद हाईकोर्ट

खुद बचने के लिए यादव का बचना जरूरी

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों और गायत्री प्रजापति जैसे मंत्रियों के भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को औकात में लाने के सारे उपक्रम किए जाते हैं. मुलायम सिंह यादव उन्हें फोन करके धमकी देते हैं. फिर बलात्कार का मुकदमा ठोका जाता है. फिर सम्पत्ति की जांच होने लगती है. फिर लोकायुक्त के यहां शिकायत दर्ज हो जाती है और वहां भी जांच शुरू हो जाती है. विजिलेंस शाखा भी जांच शुरू कर देती है और अमिताभ ठाकुर पर सत्ता का पंजा कसने लगता है. लेकिन भीषण भ्रष्टाचार के आरोपी खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की करतूतों पर सरकार आंचल डाले रहती है. भ्रष्टाचार के यादव सिंह जैसे पर्यायवाचियों को संरक्षण देने का चरम दृश्य दिखाने में भी सपाई सत्ता को शर्म नहीं आती, बस सपा के राष्ट्रीय महासचिव को महामहिम कहने में लाज आती है.

नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह जैसे भ्रष्टों को भद्दा संरक्षण देने पर हाईकोर्ट सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां दे चुकी है. लेकिन सरकार को इन टिप्पणियों की नहीं बल्कि यादव सिंह को बचाने की चिंता है. यादव सिंह के भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अखिलेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने का फैसला किया. सीबीआई जांच होने से केवल यादव सिंह ही नहीं, लखनऊ से दिल्ली रूट के कई कद्दावर नेता भी चपेटे में आ जाएंगे. इसी डर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यादव सिंह का मसला फौरन ही सीबीसीआईडी को सौंप दिया था. तब सीबीसीआईडी महकमे के मुखिया जगमोहन यादव थे. उन्होंने आनन-फानन यादव सिंह के भ्रष्टाचार की जांच भी कर ली और फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी. इतनी तीव्र गति से फाइनल रिपोर्ट लगाने के कारण ही प्रदेश सरकार ने जगमोहन यादव को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बना कर उन्हें पुरस्कृत कर दिया. लेकिन वह फाइनल रिपोर्ट हाईकोर्ट को कतई रास नहीं आई, और अदालत ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश जारी कर दिया.

भ्रष्टाचार के नेता गायत्री प्रजापति और प्रणेता यादव सिंह के धंधों के खिलाफ हाथ धोकर पड़ीं समाजसेवी डॉ. नूतन ठाकुर ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रदेश सरकार की सुगबुगाहट भांप कर फौरन ही सुप्रीम कोर्ट में कैवियेट दाखिल कर दिया. नूतन ठाकुर की कैवियेट से उत्तर प्रदेश सरकार की तिकड़म में बड़ा कानूनी रोड़ा अटक गया. कैवियेट दाखिल करने के बाद नूतन ठाकुर ने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश सरकार अरबों के घोटाले के आरोपी यादव सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है. इससे साफ जाहिर होता है कि यादव सिंह के कारनामों में राज्य सरकार के शीर्ष नेताओं के भी लिप्त होने की पूरी आशंका है, इसीलिए वे सीबीआई की जांच से डर रहे हैं. कैवियेट दाखिल करने से अब इस मामले में कोई भी फैसला नूतन ठाकुर का पक्ष सुने बगैर नहीं लिया जाएगा. उल्लेखनीय है कि बीते 16 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला की पीठ ने नूतन ठाकुर की याचिका पर यादव सिंह भ्रष्टाचार प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने यादव सिंह से जुड़े लोगों को भी जांच के दायरे में लाने को कहा. काले धन को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) ने भी यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी. एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर यादव सिंह के खिलाफ समुचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था. राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन करने के नाम पर सीबीआई जांच का विरोध किया था. जबकि अदालत ने कहा कि एकल सदस्यीय अमरनाथ वर्मा आयोग पर उन्हें भरोसा नहीं है.

आपको याद ही होगा कि पिछले साल 27 और 28 नवम्बर को नोएडा विकास प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्य अभियंता यादव सिंह के घर, उनकी पत्नी कुसुमलता की कंपनी के साझेदारों और एक अन्य कंपनी के यहां आयकर और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मार कर दस करोड़ से अधिक की नकदी, सोने और हीरे के दो किलो आभूषण और बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे. कुसुमलता के घर पर छापे के दौरान 12 लाख रुपये भी मिले थे. कुसुमलता मीनू क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं. मीनू क्रिएशन्स के ही एक अन्य निदेशक अनिल पेशावरी के यहां छापे में 44 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे. छापों के दौरान 14 लॉकर बरामद किए गए थे. आयकर विभाग की 20 टीमों ने दोनों कंपनियों के दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के ठिकानों और कंपनियों के निदेशकों के घरों पर छापे मारे थे. प्रापर्टी डीलिंग के काम में उक्त कंपनियों ने कोलकाता से फर्जी शेयर होल्डिंग बनाकर 30 से 40 कंपनियों के जरिए नोएडा विकास प्राधिकरण से अपने नाम भूखंड आवंटित करा लिए और बाद में इन कंपनियों के शेयर बेच दिए. शेयर खरीदने वालों को इन कंपनियों द्वारा खरीदे गए भूखंड मिल गए. इस तरह कर की भीषण चोरी की गई. आयकर विभाग का अनुमान है कि यादव सिंह के पास हजार करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति है. ऐसे महापुरुष को बचाने में लगी सरकार पर तल्ख टिप्पणी देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है कि यादव ने पूरी व्यवस्था को अपना दास बना लिया है. आखिर ऐसा क्या है कि यादव सिंह प्रदेश सरकार के लिए होली काऊ (पवित्र गाय) बना हुआ है.

नूतन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार एक ओर उनके पति आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की घोषित संपत्ति पर सतर्कता जांच करा रही है, लेकिन दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सीबीआई जांच का विरोध कर रही है. इससे उत्तर प्रदेश सरकार की विद्वेषपूर्ण और दोहरी नीति का खुलासा होता है.

सरकार कर रही है नंगा नाच

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि यादव सिंह को बचाने के लिए प्रदेश सरकार नंगा नाच कर रही है. मामले की सीबीआई जांच के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने के राज्य सरकार के निर्णय से यह साबित हो गया है कि सरकार यादव सिंह के काले कारनामों में बराबर की हिस्सेदार है. उत्तर प्रदेश सरकार अपनी काले कारनामों और गलत नीतियों के कारण चौतरफा घिर चुकी है.

अमिताभ ने सरकार को कठघरे में खींचा

मुलायम की धमकी प्रकरण से मशहूर और निलंबित हुए आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से कठघरे में खींचा है. निलंबन की अवधि में उन्हें आधा वेतन दिए जाने पर भी उन्होंने विधिक आपत्ति जताई है और कहा है कि बिना काम के पैसा लेना और देना दोनों गैर कानूनी और लोकहित के खिलाफ है. लिहाजा, उनका निलंबन समाप्त कर उन्हें फौरन बहाल किया जाए.

गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिख कर अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि 13 जुलाई का आरोप पत्र मिलने के बाद उन्होंने 16 जुलाई को ही अपना जवाब भेज दिया था. जवाब में उन्होंने सभी आरोपों को प्रमाण के साथ आधारहीन बताया था, साथ ही 20 जुलाई के पत्र द्वारा निर्णयकर्ता

(शेष पृष्ठ 18 पर)

सोशलिस्ट तब के समाजवादी अब के

के. विक्रम राव

लोहिया कहते थे कि खूंटी गाड़ो ताकि फिसलन कहीं तो थमे. वर्ना रसातल में जा पहुंचेंगे. अर्थात सिद्धान्तों से डिगने तथा समझौता करने का अधोबिन्दु कहां है? इसीलिए लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा यादव सिंह पर दिए गए निर्देश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार को राजधर्म की कसौटी पर कसें. मायावती के कुशासन को हिला देने वाले लोहिया के ये लोग अब खुद ही हिल गए हैं. बसपा से डिग गए हैं. बसपा से यादव सिंह सटे रहे और यादव सिंह से सपाई गलबहियां कर बैठे. मगर भिन्न था वह मंजर लोहिया के समकालीन लोगों का छह दशकों पहले. मुम्बई के उन समाजवादियों को भी परखें लखनऊ के समाजवादियों से सन्निध करके. क्रान्तिकारी दामोदर स्वरूप सेठ जो लोहिया से वरिष्ठ थे, पच्चीस साल बड़े थे, कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में थे. पर वह भी जालसाजी और धोखाधड़ी के मुकदमे में आरोपी थे. सर्वोच्च न्यायालय ने सजा भी सुनाई थी. उस वक्त भी यादव सिंह सरीखा एक धूर्त था. जिसने छल से इस अदम्य समाजवादी को फंसाया था. इसे जानकर ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दामोदर स्वरूप के पक्ष में मुम्बई जिला अदालत में गवाही दी थी. आचार्य नरेन्द्र देव ने उनके निरपराध होने का सबूत दिया था. बम्बई के राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश ने दामोदर स्वरूप के समर्थन में बयान दिया. चन्द्रभानु गुप्त ने कानूनी सहायता दी. अतः पुराने समाजवदियों की नैतिकता की तुलना आज के समाजवादियों के आचरण से हो. पर इन अत्याधुनिक समतावादियों के करतबों का उल्लेख पहले हो ताकि उनकी छवि और अधिक चमकीली हो जाये और एक ठग अपनी कारिन्दगी द्वारा तीन-तीन मुख्यमंत्रियों को धन के बल से पोट ले, सत्ता का वैश्याकरण कर दे और अकूत धन सम्पत्ति हथिया ले. सियासी अजूबा यह है. यादव सिंह का भूत मायावती पर सवार था, उसके वाजिब कारण थे. दलित के नाते उन्हें दलित से खिंचाव था, लगाव था. दौलत की लिप्सा भी थी. पर मजलूम मजदूरों तथा पसमन्दा काश्तकारों के रहनुमा समाजवादी लोग इस फरेबी के चाल में कैसे आ फंसे? इसका जवाब चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुक्त, विकसित प्रदेश के लिए साइकिल को वोट दिया था. हाथी को तजा था. पड़ताल हो कि एक तीसरे दर्जे का सरकारी कारिन्दा नोएडा में जूनियर इंजीनियर से पन्द्रह वर्षों में ही मुख्य मेंटेनेंस इंजीनियर बन गया और अरबों रुपयों से खेलने लगा. उसकी मोटरकार की डिक्की में दस करोड़ रुपये पाए गए थे. उसके विरुद्ध जांच हुई पर हर मुख्यमंत्री ने उसे रफा-दफा करा दिया. गत सप्ताह लखनऊ के उच्च न्यायालय में सरकारी वकील पचहत्तर वर्षीय महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए यादव सिंह के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग को खारिज करने का तर्क दिया मगर उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दे ही दिया. इससे तमाम सरकारी पापियों का भांडा फूटेगा. मगर पेचीदा प्रश्न यही है कि सीबीआई जांच का सरकार विरोध क्यों कर रही थी. कैसा विद्रूप है कि साधारण से अपराध में गिरफ्तारी तथा जेल हो जाती है, पर राजकोष से जिसने करोड़ों लूटा है, गबन किया है, वह अब तक छुट्टा घूम रहा है. प्रदेश के राजनेता आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? इन सियासती, अपराधी महापुरुषों का भी महागठबंधन दिखता है. मोदी सरकार के वित्त मंत्री ने उस आयकर आयुक्त का तबादला कर मानव संसाधन मंत्रालय में डाल दिया जिसने यादव सिंह के दिल्ली गाजियाबाद और नोएडा मकानों पर छापा मारकर अरबों रुपये की काली कमाई पकड़ी थी. आखिर भाजपा सरकार किसको बचा रही है? सर्वोच्च न्यायालय में यादव सिंह की सहायता के पूर्व कांग्रेसी मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद भी पेश हो चुके हैं. मायावती ने यादव सिंह को प्रश्रय दिया और उसे प्रोत्साहन दिया था. समाजवादी मुख्यमंत्रियों ने खादपानी डाला. छोटा सा जीव आज दैत्याकार हो गया है. एक त्रासद तथ्य पर गौर कर लें. उत्तर प्रदेश के गुप्तचर पुलिस विभाग ने यादव सिंह को निर्दोष पाया और मुकदमा अदालत से वापस ले लिया था. महज इत्तेफाक था कि चौबीस घंटों में लखनऊ के आयकर विभाग ने छापा मारा और यादव सिंह के बेहिसाब कालेधन को पकड़ा, कब्जे में लिया. प्रदेश सरकार को ऐसी नाजायज हरकत का जवाब सीबीआई तथा अदालत को देना पड़ेगा. बड़े राज खुलेंगे. दिग्गजों के सिर लुढकेंगे. मुख्य न्यायाधीश धनंजय चन्द्रचूड ने कहा भी कि जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का हक किसी को भी नहीं है. यह यादव सिंह का तिलिस्म है या उत्कोच की लिप्सा? यहीं फिर लोहिया की बातें याद कर लें कि खूंटी गाड़े. वर्ना क्या पता लाल टोपी

(शेष पृष्ठ 18 पर)

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंसे मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवक

लालफीताशाही में फंसा है नियमितीकरण

पाटेश्वरी प्रसाद

ग्राम रोजगार सेवकों का नियमितीकरण करके राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर ग्राम रोजगार सेवक आए दिन आंदोलनरत रहते हैं. वे सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित होने वाले समस्त शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं और जिनका कार्य ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के समरूप है, तो उन्हें नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह मामला धीरे-धीरे उग्र होने की तरफ बढ़ रहा है.

सन 2006 में जब मनरेगा योजना की शुरुआत हुई तो इस योजना को भारत में तीन चरणों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था. योजना का उद्देश्य यह था कि ग्राम पंचायतों में स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण करके ग्रामीणजनों की आजीविका में वृद्धि की जाए. गांवों के जंगल, जल एवं पर्यावरण की रक्षा की जाए. सामाजिक समरसता और समानता को सुनिश्चित किया जाए. ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जा रहे लोगों के पलायन पर अंकुश लगे. इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध करना सुनिश्चित किया गया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके. इस योजना को उत्तर प्रदेश में तीन चरणों में बांटा गया था, जिसमें पहले चरण में 22 जनपदों, दूसरे चरण में 17 जनपदों और तीसरे चरण में नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को शामिल कर लिया गया. इस योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश में 65 हज़ार संविदा कर्मियों को विभिन्न पदों पर तैनात किया गया था. जिसमें ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एवं को-ऑर्डिनेटर शामिल हैं. इनमें सबसे अधिक संख्या ग्राम रोजगार सेवकों की है.

उत्तर प्रदेश में 52 हज़ार ग्राम पंचायतों में 45 हज़ार ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत हैं. सपा सरकार ने 2006 में इन ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति पंचायत मित्र के पदनाम पर की थी. जिसे पंचायतीराज विभाग के अधीन किया गया था. जिसके तत्कालीन शासनादेश में यह निहित था कि ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक सहायक का कार्य सम्पादित करेंगे. जिनका मानदेय प्रतिमाह दो हज़ार रुपये होगा. बसपा सरकार के आते ही इन पंचायत मित्रों का पदनाम बदलते हुए ग्राम रोजगार सेवक कर दिया गया और उन्हें पंचायतीराज विभाग से हटाकर ग्राम्य विकास विभाग को सौंप दिया गया.

वर्ष 2009-10 के शासनादेश में ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय में सशर्त बढ़ोत्तरी करते हुए विभाग ने कहा कि यदि अनुमोदित श्रम बजट 80 फीसदी से अधिक कार्य करते हैं, तो मानदेय तीन हज़ार दिया जाएगा और यदि श्रम बजट के अंदर कार्य करते हैं, तो मानदेय प्रतिमाह 2500 ही दिया जाएगा. सपा सरकार ने 18 अप्रैल 2012 के शासनादेश में पुनः मानदेय में बढ़ोत्तरी करते हुए (सशर्त को हटाकर) तीन हज़ार प्रतिमाह कर दिया. साथ ही प्रतिवर्ष दस प्रतिशत इन्क्रिमेंट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की. साल दर साल बढ़ोतरी होते हुए मौजूदा समय में ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय के तौर पर प्रतिमाह 3630 रुपये प्रशासनिक मद से भुगतान किया जाता है, लेकिन प्रशासनिक मद का दुरुपयोग होने से इस कर्मचारी संवर्ग को प्रत्येक माह इनके मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है. इसी अव्यवस्था के चलते मौजूदा सपा सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय के भुगतान के लिए 60 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया. उसके उपरांत 3 जुलाई 2015 को पुनः 138 करोड़ का बजट समस्त मनरेगा कर्मियों के भुगतान के लिए जारी किया. इसके बाद भी मनरेगा कर्मियों के लिए यह दूर की कौड़ी साबित हो रही है.

सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी मंचों और मीडिया के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों का नियमितीकरण कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की कई घोषणाएं कीं, लेकिन वे घोषणाएं केवल छलावा ही साबित हुईं. ऐसे में ग्राम रोजगार सेवकों ने प्रदेश में सपा सरकार के बनने के तुरंत बाद जनपद बाराबंकी में एक प्रांतीय सम्मलेन आयोजित किया, जिसमें मौजूद ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरविन्द कुमार सिंह गोप ने ग्राम रोजगार सेवकों को यह विश्वास दिलाया था कि सपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है. अब तो सपा सरकार के बनने के आज तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन ग्राम रोजगार सेवकों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है. ऐसी दशा में ग्राम रोजगार सेवक नियमितीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हमेशा ही संघर्षरत रहे हैं. उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाही का कहना है कि सत्ता में बैठे प्रशासनिक अधिकारी उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा हैं, जो सपा सरकार की छवि तो धूमिल कर ही रहे हैं साथ ही नियमितीकरण के मामले को दबाने की भी नापाक कोशिश कर रहे हैं. संगठन के प्रदेश सचिव आकाश त्रिपाठी का मानना है कि सरकार के नौकरशाहों ने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आंखों में काली पट्टी बांध रखी है, जिस कारण उन्हें रोजगार सेवकों की जायज़ मांगें न दिखाई दे रही हैं और न सुनाई दे रही हैं. शासन में मौजूद अधिकारी ग्राम रोजगार सेवकों को निकालने की साजिश रच रहे हैं. जैसी कोशिश पूर्व में बसपा सरकार के प्रशासनिक अधिकारी कर चुके हैं.

सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2010 में बसपा सरकार में ग्राम्य विकास के प्रमुख सचिव रहे मुकुल सिंघल ने भी इस संवर्ग को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कशिश की थी, लेकिन संवर्ग ने उच्च न्यायालय एवं आंदोलनों के माध्यम से उनके इस प्रयास को नाकाम कर दिया. इस मलाईदार विभाग को पाने के लिए वैसे तो कई वरिष्ठ अधिकारी लगे रहे लेकिन यह विभाग मिला मुकुल सिंघल के भाई अरुण सिंघल को. पुनः जुलाई 2015 को प्रमुख सचिव मुकुल सिंघल ने प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों की बैठक बुलाकर ग्राम रोजगार सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इससे यह जाहिर है शासन में बैठे अधिकारी यह नहीं चाहते कि ग्राम रोजगार सेवकों का नियमितीकरण हो और उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले.

उत्तर प्रदेश में 52 हज़ार ग्राम पंचायतों में 45 हज़ार ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत हैं. सपा सरकार ने 2006 में इन ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति पंचायत मित्र के पदनाम पर की थी. जिसे पंचायतीराज विभाग के अधीन किया गया था, जिसके तत्कालीन शासनादेश में यह निहित था कि ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक सहायक का कार्य सम्पादित करेंगे.

आन्दोलनों की लंबी फेहरिस्त

ऐसे तो ग्राम रोजगार सेवकों के बारे में कम लोग ही जानते थे और सम्बंधित विभाग भी इनकी मांगों को गंभीरता से संज्ञान नहीं लेता था, लेकिन 02 दिसंबर 2010 को ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष समिति जिसके अगुआ शिव मनोरथ शुक्ल, संतोष शुक्ल, आकाश त्रिपाठी, देवेन्द्र प्रताप शाही, कमलेश गुप्ता सरीखे कर्मचारी नेता रहे, इनके नेतृत्व में राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पर हज़ारों की संख्या में ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया. तत्कालीन बसपा सरकार की दमनकारी नीति के चलते ग्राम रोजगार सेवकों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले एवं वाटर कैनन से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया. कई ग्राम रोजगार सेवकों को गंभीर चोटें आईं. इस घटना में रामपुर के ग्राम रोजगार सेवक सहदेव पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए नदी में कूदे तो उनकी मौत हो गई. तब विपक्ष में रहे सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निंदा करते हुए सरकार को बर्खास्त करने की राज्यपाल से मांग की थी. लेकिन अभी छह जुलाई को हुए आंदोलन में नियमितीकरण की मांग कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों पर उसी तरह पुलिस कार्रवाई करके उसे दबाने का प्रयास किया गया. इसके बाद ग्राम रोजगार सेवकों की प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास मंत्री अरविन्द कुमार सिंह गोप से हुई वार्ता में मंत्री ने नियमितीकरण के मामले में एक माह का समय मांगा. अब ग्राम रोजगार सेवकों का यह ऐलान है कि यदि 07 अगस्त तक नियमितीकरण को लेकर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो संगठन आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे. जिसमें चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है. आंदोलन की शुरुआत 07 अगस्त को प्रदेश के समस्त विकास खंडों, 13 अगस्त को समस्त जनपद मुख्यालयों और 20 अगस्त को प्रांतीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. स्पष्ट है कि संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए आमादा है.

ऐसे खड़ा हुआ आंदोलन

17 मई 2011-नई चयन प्रक्रिया को रोकने के लिए आंदोलन.
23 सितम्बर 2012-मानदेय में बढ़ोत्तरी एवं नियमितीकरण के लिए आंदोलन.
26 दिसंबर 2013-आंदोलन के उपरांत कृषि उत्पादन आयुक्त से वार्ता, विभाग से रिपोर्ट तलब.
19 से 25 नवम्बर 2014-आंदोलनरत ग्राम रोजगार सेवक.
25 नवम्बर 2014-मुख्यमंत्री से वार्ता, नियमितीकरण पर जताई सैद्धांतिक सहमति.
04 जून 2015-मुख्यमंत्री सचिव से वार्ता.
06 जुलाई 2015-आंदोलन के दौरान ग्राम्य विकास मंत्री अरविन्द कुमार सिंह गोप से वार्ता, नियमितीकरण पर जताई सहमति, मांगा एक माह का समय. ■

feedback@chauthiduniya.com

यादव सिंह ने पूरी व्यवस्था को अपना दास बना लिया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

खुद बचने के लिए यादव का बचना जरूरी

पृष्ठ 17 का शेष

लेकिन मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया.

अमिताभ ने शासन को लिखे पत्र में कहा है कि उनसे बिना कोई सरकारी काम लिए 81,350 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है जो उनके कुल वेतन रुपये 1,45,477 के आधे से भी अधिक है. अमिताभ ने विधिक पेंच खड़ा करते हुए कहा है कि 01 अप्रैल 2013 से अब तक उन्हें कार्य मूल्यांकन में दस में आठ से नौ अंक मिलते रहे हैं, जो यह बताते हैं कि उनका सरकारी काम बहुत अच्छा रहा है, ऐसे में बिना काम लिए इतना पैसा देना और कोई काम नहीं लेना लोकहित के विरुद्ध है. अमिताभ ठाकुर ने कहा कि एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रदीप शुक्ला और अवैध खनन के आरोपी इलाहाबाद कमिश्नर बीके सिंह और फतेहपुर के जिलाधिकारी राकेश कुमार को जब राज्य सरकार ने पिछले दिनों बहाल कर दिया तो उन्हें बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? यह उनके अधिकार का सीधा-सीधा हनन है.

कानून के विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार अमिताभ ठाकुर को अपने घेरे में लेने की कोशिश में है, लेकिन अमिताभ ने भी अपने बचाव में माकूल प्रमाण और कानूनी तर्क इकट्ठा कर लिए हैं, जिससे सरकार अप्रिय स्थितियों में फंस सकती है. टेलीफोन पर सपा प्रमुख मुलायम द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद लखनऊ पुलिस का यह नहीं मानना कि वह धमकी थी, ने तंत्र पर सत्ता-कुप्रभाव को उजागर किया है. लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी देने की शिकायत को बिल्कुल ही नकार दिया है. हजरतगंज के इंस्पेक्टर विजयमल सिंह यादव ने 17 जुलाई 2015 को पत्र के जरिये यह बताया है कि मुलायम सिंह यादव द्वारा धमकी देने की शिकायत की जांच कराई गई, लेकिन जांच में प्रार्थनापत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं होती है. अतः प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है. हजरतगंज थाने के सिपाही ने अमिताभ ठाकुर के घर जाकर उन्हें यह चिट्ठी रिसीव कराई. यह चिट्ठी भेज कर सरकार ने वैसी ही गलती की जैसी गलती मुलायम ने धमकी देकर की थी. अमिताभ ने हजरतगंज पुलिस की जांच पर असहमति जताते हुए कहा भी कि इसमें आरोपों की पुष्टि नहीं होने का कोई कारण नहीं बताया गया है और सतही तौर पर निष्कर्ष निकाल लिया गया है. यह स्पष्टतया दबाव में की गई कार्रवाई है, इसे वे अदालत में पेश करेंगे. ■

अमिताभ ने शासन को लिखे पत्र में कहा है कि उनसे बिना कोई सरकारी काम लिए 81,350 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है जो उनके कुल वेतन रुपये 1,45,477 के आधे से भी अधिक है. अमिताभ ने विधिक पेंच खड़ा करते हुए कहा है कि 01 अप्रैल 2013 से अब तक उन्हें कार्य मूल्यांकन में दस में आठ से नौ अंक मिलते रहे हैं, जो यह बताते हैं कि उनका सरकारी काम बहुत अच्छा रहा है, ऐसे में बिना काम लिए इतना पैसा देना और कोई काम नहीं लेना लोकहित के विरुद्ध है.

सोशलिस्ट तब के, समाजवादी अब के

कितनी और खिसकती रहे. अब याद कर लें पुराने दौर की लाल टोपी को, जब गांधी टोपी के कुछ वर्षों बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने सफेद की जगह रक्तिम रंग पसंद किया था. उसी युग के थे संघर्षशील समाजवादी दामोदर स्वरूप सेठ जो यूपी सोशलिस्ट पार्टी के 1936 में संस्थापक अध्यक्ष थे. जब वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो आचार्य नरेन्द्र देव उपाध्यक्ष थे. वे बीस वर्ष की भरी तरूणाई के थे जब काकोरी षडयंत्र में गिरफ्तार हुए थे. फिर वे पांच बार जेल गए. भारत छोड़ो आन्दोलन (1942) में दो साल कैद रहे. तो अचरज होना स्वाभाविक है कि ऐसा राष्ट्रभक्त समाजसेवी, क्रान्तिकारी व्यक्ति आखिर धोखाधड़ी, जालसाजी तथा गबन के अपराध में कैसे किन हालातों में कैद हुए और जेल की सजा पाए. यह महज राजनीतिक संयोग था और दगाबाज साथियों पर अतिविश्वास करने का नतीजा था. दामोदर जी सरल प्रकृति के थे. भारत के स्वतंत्र होने के दो वर्ष बाद की घटना है. नेताजी सुभाष के साथी रहे और उनकी पार्टी फारवर्ड ब्लाक के उपाध्यक्ष रहे लाला शंकरलाल दामोदर जी के मित्र थे. शंकरलाल जो वाणिज्यीय प्रबन्ध बीमा कम्पनी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक कुटिल व्यूह रचकर जूपिटर बीमा कम्पनी के शेयर हथिया लिये. नियंत्रण अपने हाथ में रखा पर वित्तीय लेनदेन दामोदर जी के नाम पर करते रहे. काले धन की आवक हुई और शंकरलाल ने अपना वित्तीय कारोबार विस्तृत कर लिया. जूपिटर बीमा कम्पनी में शीघ्र ही शेयरों का घपला पकड़ा गया. सरकारी जांच पर करीब पचास लाख (आज उसका हजार गुणा ज्यादा) रुपये का गबन और हेराफेरी उभरकर आई. बारह अभियुक्त बने जिनमें शंकरलाल पहले नम्बर पर थे और दामोदर स्वरूप जी नौंवे नम्बर पर थे. किन्तु बैंक का सारा लेनदेन उन्हीं के नाम पर होता था. आचार्य नरेन्द्र देव ने दामोदर स्वरूप जी को सावधान भी किया था कि उन्हें आर्थिक बारीकियों का ज्ञान नहीं है, व्यापार से यह समाजवादी क्रान्तिकारी अनभिज्ञ हैं. अतः वह जूपिटर कम्पनी छोड़कर लखनऊ लौट आए. पर दामोदरजी तब तक इन विश्वासघाती मित्रों के कारण आकंठ डूब गए थे. मुम्बई जिला अदालत में मुकदमा चला. उस वक्त कारागार से तपे-तपाये निकले इस स्वाधीनता सेनानी और सामाजवादी नेता की वित्तीय अपराध में संलिप्तता कोई सोच भी नहीं सकता था. स्वयं जवाहर लाल नेहरू ने अदालत में बयान दिया कि दामोदर जी ऐसा गबन का अपराध कर ही नहीं सकते. नामी वकील और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने दामोदर जी की अदालत में पैरवी स्वयं की. जिला जज ने दामोदर जी को दोषमुक्त पाकर रिहा कर दिया. तब मुम्बई सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी. मुकदमा लम्बा चला. सहअभियुक्तों के बनावटी बयानों के कारण दामोदर जी को सात साल का सश्रम दण्ड मिला. लाला शंकरलाल और उनके साथियों ने दामोदर जी की बलि दे दी. सलीब पर चढ़ा दिया. दामोदर जी ने मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी. इस अपील की प्रधान न्यायाधीश कोका सुब्बा राव ने सुनवाई की, जिन्हें विपक्षी पार्टियों ने 1967 में इन्दिरा गांधी के प्रत्याशी डा. जाकिर हुसैन के विरुद्ध राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था. तब जनसंघ, सोशलिस्ट, स्वतंत्र पार्टी आदि के नेताओं ने कांग्रेस की पराजय की योजना बनाई पर विफल रहे. कम्युनिस्टों ने कांग्रेस का साथ दिया था. फिलहाल प्रधान न्यायाधीश सुब्बा राव ने पांच वर्षों तक सुनवाई कर 18 मार्च 1963 के दिन दामोदर स्वरूप सेठ की सजा को बरकरार रखा, लेकिन दो वर्षों के भीतर (1965 में) उनका निधन हो गया. उन्हें मुम्बई कारागार में सश्रम कैद से महाराष्ट्र की राज्यपाल रही श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित ने बचाया. उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री चन्द्रभानु गुप्त से आग्रह किया तो दामोदरजी को लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में सुगणावस्था में भर्ती किया गया. इसी सिलसिले में एक त्रासद अनुभव का भी उल्लेख कर दूं. कितने युवा समाजवादी हैं जिन्होंने युसुफ मेहरअली, पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास, रामवृक्ष बेनीपुरी, डा. उषा मेहता, गोपाल गौडा, एन्टोनी पिल्लई, आदि का नाम भी सुना हो. उत्तर प्रदेश के समाजवादी सिरमौरों को दामोदर स्वरूप सेठ के बारे में केवल आर्थिक अपराध के संदर्भ में जानकारी होगी. लोहिया से भी वरिष्ठ इस समाजवादी के बारे में युवाओं को बताना होगा. बरेली में जन्मे, इलाहाबाद तथा लखनऊ में शिक्षित दामोदर स्वरूप सेठ महज बीस वर्ष की उम्र में बनारस षडयंत्र केस में पांच वर्ष जेल काट चुके थे. बनारस षडयंत्र केस के प्रमुख आरोपी शचीन्द्रनाथ सान्याल को काला पानी आजीवन कारावास हुआ था. वे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक थे, जिसमें भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद थे. दामोदर स्वरूप जी के साथ दूसरे आरोपी थे रास बिहारी बोस, जिन्होंने जापान में आजाद हिन्द फौज गठित किया था. जिसका नेताजी सुभाष बोस ने बाद में नेतृत्व किया था. संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के नाते 1946 में दामोदर स्वरूप सेठ ने सदन में कहा था कि विश्व का भारी भरकम यह संविधान पूंजीपतियों के अधिकारों का दस्तावेज है. आम जन के लिए रद्दी कागज है. प्रथम संसद के वे एकमात्र सोशलिस्ट सदस्य थे क्योंकि समाजवादियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था. पर इस निर्णय की सूचना देर से मिलने के कारण दामोदर स्वरूप जी अपना नामांकन वापस नहीं ले पाये. उन्होंने संविधान में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि उनकी राय में इससे प्रशासन में अक्षम, निकम्मे और मूर्ख लोग चयनित हो जाएंगे. बेबाकी उनकी पहचान थी. उस दौर के समाजवादियों की संघर्ष गाथा यदि आज के समाजवादी पढ़ें, समझें और आत्मसात करें तो फिर राजकोष के लुटेरों की कोई भी पैरवी नहीं कर सकता, जैसा लखनऊ उच्च न्यायालय में समाजवादी सरकार के वकीलों ने ठग यादव सिंह के लिए किया था. कहीं तो खूंटी गड़े, ताकि कदाचार की सीमा तय हो. वर्ना कांग्रेस क्या खराब थी?

feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री और सरकारी महकमा नहीं दे रहा टैक्स, अरबों बकाया

सीएम न दे टैक्स तो क्या कर लेगा निगम!

वैष्णवी वंदना

प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा टैक्स जमा न करने का मसला जबसे उजागर हुआ है, यह सवाल उठने लगा है कि फिर आम लोगों पर जबरन वसूली का हथियार क्यों आजमाया जाता है. मुख्यमंत्री के टैक्स प्रकरण से लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में हो रही टैक्स चोरी के मामले सामने आने लगे हैं. किसानों का बकाया दिलाने से लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहाल करने तक की प्राथमिकताओं में फेल हो चुकी सरकार टैक्स वसूली में भी पूरी तरह लचर साबित हुई है. इससे उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति के बारे में समझा जा सकता है.

प्रदेश में आम आदमी पुलिस से, जबरन टैक्स वसूली से, फर्जी बिलों पर आपराधिक कार्रवाई, कुर्की जब्ती से और किसी भी समय पानी-बिजली का कनेक्शन काट दिए जाने की सरकारी हरकतों से परेशान है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री टैक्स नहीं देते तो उन पर कार्रवाई करने की भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन को हिम्मत कहां है. यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास और दफ्तर पर नगर निगम के करीब एक करोड़ रुपये गृह-कर के बकाया हैं. आरटीआई के जरिए उर्वशी शर्मा को मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दफ्तर पर नगर निगम के 63 लाख 31 हजार 266 रुपये बकाया हैं. इस साल के बकाये की राशि 12 लाख 64 हजार 307 रुपये उसमें और जोड़ दी जाए, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर का बकाया 75 लाख 95 हजार 573 रुपये हो जाता है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास पर भी हाउस टैक्स के तीन लाख 53 हजार 662 रुपये बाकी हैं. यानी दफ्तर और घर मिला कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर 79 लाख 49 हजार 235 रुपये केवल हाउस टैक्स के बकाया हैं. सूचना के अधिकार पर सरकारी सक्रियता की गति यह है कि आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने 28 नवंबर 2014 को आरटीआई के जरिये जो सूचना मांगी थी, उसका जवाब उन्हें एक साल बाद इस वर्ष जुलाई महीने में प्राप्त हुआ.

उत्तर प्रदेश सरकार इसी गति से चल रही है. जवाहर भवन जैसे बहुमंजिला सचिवालय पर सात करोड़ रुपये और उसके पड़ोसी सचिवालय इंदिरा भवन पर पांच करोड़ रुपये बकाया है. सरकारी भवनों की देखरेख का जिम्मा संभालने वाले राज्य सम्पत्ति विभाग ने 2010 से कोई टैक्स ही नहीं जमा किया है. राज्य सम्पत्ति विभाग के अंतर्गत आने वाले सरकारी भवनों (केवल जोन-1 के) पर करीब 35 करोड़ रुपये बकाया है. पहले निगम ने टैक्स बकाये पर ब्याज लागू कर दिया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया. इसके बावजूद सम्पत्ति विभाग ने 35 करोड़ रुपये नहीं दिए. इन सरकारी विभागों पर नगर निगम की नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता. जब मुख्यमंत्री ही टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, तो इन सरकारी अधिकारियों का कोई क्या बिगाड़ लेगा. सरकारी महकमों से नगर निगम को हाउस टैक्स मिल नहीं रहा और नगर निगम कंगाल होने की स्थिति में है. नगर निगम की आय का मुख्य जरिया हाउस टैक्स है, लिहाजा पूरा का पूरा दबाव आम नागरिकों पर पड़ता है और उसकी वसूली के लिए प्रताड़ना और मानवाधिकार उल्लंघन के सारे हथकंडे अपनाये जा रहे हैं. गरीबों की गर्दन मरोड़ी जा रही है. आम लोगों की सम्पत्तियां कुर्क करने के लिए नोटिसें जारी हो रही हैं. छोटे और मंझोले दुकानदारों और व्यापारियों के संस्थान सील कराने की कार्रवाई हो रही है. लेकिन सरकारी विभागों पर नगर निगम की कुछ चलती ही नहीं. छोटे बकाएदारों के खिलाफ निगम उत्पीड़न के स्तर तक जाकर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बड़े सामर्थ्यवान बकाएदारों, नेताओं और सरकारी महकमों पर कोई कानून नहीं चलता. बकायेदारों में जवाहर भवन और इंदिरा भवन ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का मुख्य सचिवालय, लखनऊ के एसएसपी का दफ्तर, हजरतगंज कोतवाली, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, महात्मा गांधी मार्ग स्थित रेलवे का दफ्तर, जनपथ सचिवालय, बापू भवन सचिवालय, विधान भवन (संवैधानिक पीठ) समेत कई सरकारी महकमे शामिल हैं, जिन पर करोड़ों रुपये हाउस टैक्स के बकाया हैं. अकेले जनपथ स्थित सचिवालय भवन पर दो करोड़ 57 लाख 11 हजार 444 रुपये का गृह-कर बकाया है.

मुख्य डाकघर (जीपीओ) पर करीब छह करोड़ रुपये बकाया है. मेडिकल कॉलेज पर एक करोड़ 70 लाख रुपये बकाया है. पुलिस विभाग पर 40 लाख रुपये, स्वास्थ्य विभाग पर 40 लाख रुपये, जिमखाना क्लब पर दो करोड़ रुपये, गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल पर 38 लाख रुपये और जगत सिनेमा पर 35 लाख रुपये बकाया है. इसके साथ-साथ ज्यूडिशियल ट्रेनिंग सेंटर पर करीब एक करोड़ रुपये, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) पर पांच करोड़ रुपये, होम्योपैथिक कॉलेज पर एक करोड़ रुपये, मानवाधिकार विभाग पर 14 लाख रुपये, सुषमा नर्सिंग होम पर 30 लाख रुपये और कुबेर लाल पर 20 लाख रुपये बकाया है. सहारा बजाज पर 10 लाख रुपये की देनदारी है और गोमतीनगर के पत्रकारपुरम स्थित तरंग होटल पर 18 लाख रुपये बकाया है. लोहिया विधि संस्थान और लोकबंधु अस्पताल पर दो करोड़ रुपये बकाया है. स्कूटर इंडिया पर करीब 17 लाख रुपये बकाया है. नगर निगम के हाउस टैक्स की परिधि में करीब 5,03,996 मकान आते हैं. इनमें से जोन नंबर-एक में 44,596, जोन नंबर-दो में 46,272, जोन नंबर-तीन में 1,15,098, जोन नंबर-चार में 82,010, जोन नंबर-पांच में 93,709 और जोन नंबर-छह में 1,21,838 मकान हैं. इन्हीं में सरकारी भवन भी शामिल हैं. राजस्व विभाग के एक आला अधिकारी ने कहा कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है. सामर्थ्यवानों और सरकारी महकमों से कहीं भी टैक्स वसूली नहीं हो पा रही है. सरकारी महकमे अब लोकतंत्र पर भारी पड़ते जा रहे हैं और खाईं की भरपाई के लिए आम नागरिकों को लूटा जा रहा है और उन पर रोजाना नए-नए टैक्स लादे जा रहे हैं. उन्होंने शाहजहांपुर जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल इस एक जिले में ही सरकारी विभागों पर टैक्स के करोड़ों रुपये बाकी हैं. सरकारी भवनों के साथ-साथ रसूखदार लोगों के घरों से हाउस और वाटर टैक्स नहीं मिल रहा है. जिले के डीआईओएस कार्यालय पर 14 लाख 81 हजार 078 रुपये बकाया हैं. वहां के वन विभाग पर 11 लाख 21 हजार 948 रुपये बकाया हैं. जिला पंचायत बोर्ड पर 9 लाख 81 हजार 148 रुपये, जिला समाज कल्याण छात्रावास पर 33 लाख 97 हजार 20 रुपये, राजकीय इंटर कालेज पर 2 लाख 52 हजार 744 रुपये, मिशन स्कूल पर 96 हजार 768 रुपये बकाया हैं. रसूखदार जसवंत कौर पर 2 लाख 66 हजार 400 रुपये और अनीस अहमद पर 2 लाख 65 हजार 923 रुपये बकाया है. ऐसे बकायेदारों की सूची काफी लंबी है. ऐसी ही वीभत्स स्थिति पूरे प्रदेश की है और सरकार नगर निगमों और नगर पालिकाओं को अधिक ताकत देने के बजाय उनका पर कतरने पर ही लगी हुई है. ताकि खेल निर्बाध जारी रहे.

एलआईसी हजम कर गया अरबों रुपये

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आयकर विभाग की ओर से जारी टैक्स बकायेदारों की सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सारे सरकारी उपक्रमों और कंपनियों को पछाड़ दिया है. एलआईसी के साथ-साथ बकायेदारों की सूची में केंद्र और राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण या स्वामित्व वाली कंपनियों की संख्या सबसे ज्यादा है. अकेले एलआईसी पर 70 अरब रुपये से ज्यादा का टैक्स बकाया है. विभाग की ओर से केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के बाद जारी सूची में अलग-अलग श्रेणियों के शीर्ष दस की सूची जारी की गई है.

आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को दी गई जानकारी के मुताबिक टैक्स बकायेदारों में नोएडा कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वोडाफोन, आइडिया, नोकिया, भारत पेट्रोलियम, एचडीएफसी बैंक, इंडियन ऑयल, होंडा मोटर, गुजरात स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, सन फार्मा सिक्किम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, बंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, जमशेद जी टाटा ट्रस्ट जैसी कई संस्थाएं, कंपनियां, ट्रस्ट वगैरह प्रमुख रूप से शामिल हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड में 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग प्रमाणपत्र से वंचित

रेनू शर्मा

प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग भले ही कितने ही दावे करे, लेकिन प्रदेश की सही हकीकत यह है कि प्रदेश में अब तक 60 फीसद से ज्यादा विकलांग विकलांगता प्रमाण पत्रों से वंचित हैं. यानी 40 फीसद विकलांगों को भी विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है. इसकी असली वजह है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टरों का न होना जो कि विकलांगों को प्रमाण पत्र दे सकें. प्रमाण पत्र पाने वालों में से भी अधिकांश शहरी इलाकों के हैं गांवों की तो खैर बात ही क्या की जाए. प्रदेश में कुल एक लाख 85 हजार विकलांगों में से केवल 73148 लोगों को ही विकलांगता प्रमाण पत्र दिए गए हैं. दरअसल, प्रदेश में खासकर दुर्गम व पर्वतीय व ग्रामीण इलाकों में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं इनमें से ज्यादातर में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं. मिसाल के तौर पर क्लीनिकल सायकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक व नाक कान गला (ईएनटी) विशेषज्ञ, हड्डी विशेषज्ञ आदि. ऐसे में बहुत से विकलांग लोग हैं. मिसाल के तौर पर मूक बधिरता, मानसिक विकलांगता व अन्य किस्म की विकलांगता प्रमाणित नहीं हो पाती, क्योंकि विकलांगता को केंद्रीय समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय मान्यता देता है, सुविधाओं के अभाव में लोग अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं दे पाते नतीजतन विकलांगता प्रमाण पत्र न होने से विकलांगों के मिलने वाले आरक्षण व पेंशन से भी वंचित हो जाते हैं. इसी तरह प्रदेश में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं भी धरी की धरी रह जाती हैं. वैसे भी प्रदेश में विकलांगता प्रमाण पत्र देने का रिकार्ड बहुत बुरा रहा है. 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में कुल विकलांगों में से केवल 39.48 फीसद को ही विकलांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराए जा सके हैं. प्रदेश में कुल मिलाकर एक लाख 85 हजार 272 विकलांग हैं, जिनमें से 73148 को ही विकलांगता प्रमाण पत्र दिए गए हैं. विकलांगता प्रमाण पत्र ही वह दस्तावेज है जिसकी मदद से कोई व्यक्ति साबित कर सकता है कि वह विकलांग है और सरकारी सुविधाएं पाने का हकदार है. केंद्र सरकार ने विकलांगता प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया सरल कर दी है, उत्तराखंड में इसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है. बता दें कि 2011 में विशेषज्ञों की बजाय एमबीबीएस डॉक्टरों को विकलांगता प्रमाण पत्र देने का अधिकार दे दिया दिया था, प्रदेश में एमबीबीएस डॉक्टर इस काम में रुचि नहीं लेते, क्योंकि वे मानते हैं कि वे किसी व्यक्ति की मानसिक विकलांगता या अन्य प्रकार की विकलांगता प्रमाणित करने में सक्षम नहीं हैं. अब प्रदेश सरकार ने केंद्र से अपील की है कि वह विषेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम का दौरा कराए और शिविर लगाकर मौके पर लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए. ■

गंगा सुरक्षा के लिए गोमुख से लेकर गंगासागर तक रोड मैप तैयार

-चौथी दुनिया ब्यूरो

गंगा सुरक्षा के लिए गोमुख से गंगासागर तक 2700 किमी के बीच आठ इकोलोजिकल जोन बनाए जाएंगे. पांच राज्यों से मशवरा के बाद यह तय हो गया है. इन राज्यों के वैज्ञानिकों के बीच पांच दौर तक बैठक चली बैठक के बाद वन अनुसंधान केंद्र ने रोड मैप तैयार कर लिया है. उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल के बीच गंगा के दोनों किनारों पर 50 मीटर तक अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियां लगाई जाएंगीं. उत्तराखंड में गंगा किनारे सिर्फ जड़ी-बूटियों के पौधे लगाए जाएंगे. केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगा सुरक्षा के लिए गोमुख से गंगासागर तक रोड मैप तैयार करने के लिए पांच राज्यों को निर्देश दिए थे. इस पर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों की बैठक मई में देहरादून स्थित वन अनुसंधान केंद्र (एफआरआई) में हुई थी. एफआरआई को रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी. राज्यों के वैज्ञानिकों की आखिरी बैठक 3 जुलाई को हुई. इसमें रोड मैप को अंतिम रूप दे दिया गया. उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल के बीच अलग-अलग इको सिस्टम के मुताबिक आठ इकोलोजिकल जोन बनाए जाएंगे. रोड मैप तैयार करने वाली कोर कमेटी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इकोलोजिकल जोन इको सिस्टम के लिहाज से बनाए गए हैं. आद्रता, ऊष्णता, मिट्टी के प्रकार, जैव विविधता आदि को आधार बनाया गया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के यूपी से सटे इलाकों का इको सिस्टम मिलता है. इन दोनों को मिलाकर इकोलोजिकल जोन बना है. इसी तरह बिहार-झारखंड के मिलते इको सिस्टम वाले क्षेत्रों को एक जोन में रखा गया है. इकोलोजिकल जोन के लिहाज से ही यहां वनस्पतियां लगाई जाएंगी. गोमुख से गंगा सागर तक नदी के किनारे बसी आबादी की स्थिति पता करने की जिम्मेदारी जियोग्राफिकल सर्वे आफ इंडिया और रिमोट सेंसिंग को दी गई है. इस संबंध में दोनों संस्थानों को पत्र भेजा जा चुका है. जहा गंगा किनारे 50 मीटर के दायरे में आबादी है इसे हटाने के लिए संबंधित राज्य सरकार को लिखा जाएगा. ■

सपा, कांग्रेस और विहिप के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल

राजकुमार शर्मा

भाजपा 2017 के चुनावों के मद्देनजर भले ही कांग्रेस को आपदा राहत व आबकारी घोटाले के जरिए घेरने में जुटी हो, लेकिन भाजपा को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भाजपा में ही नहीं बल्कि सपा बसपा और भाजपा के सहयोगी संगठनों में भी सेंध लगानी शुरू कर दी है. इसकी मिसाल रविवार को दिखी जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की मौजूदगी में उधम सिंहनगर से सपा, बसपा एवं विश्व हिन्दू परिषद के सैकडों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं का फूल माला पहनाकर एवं बुके देकर स्वागत किया. बता दें कि इसी 21 तारीख को सैकड़ों भाजपाइयों ने कांग्रेस का दामन थामा था. बहरहाल, विधानसभा 2002 के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे तथा विगत विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जरनैल सिंह काली, नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष मोहम्मद सफी तथा विश्व हिन्दू परिषद के उधमसिंहनगर जिला प्रभारी दीपक गोस्वामी ने अपने लगभग 60 सहयोगियों सहित कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों के सहयोग से

क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जो सभी धर्मों, सम्प्रदायों एवं जातियों का सम्मान करती है. कांग्रेस पार्टी ने आजादी से लेकर आज तक राजनीति के साथ-साथ समाज सुधारक का भी काम किया है तथा समाज को एक नई दिशा दी है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया. मोदी सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में मंहगाई, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया है. देश की जनता भाजपा के असली चेहरे को पहचान चुकी है तथा आने वाले समय में इसे सबक सिखाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी साथियों से अपेक्षा है कि वे सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की भावना तथा कांग्रेस की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप उत्तराखंड में पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करेंगे. इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, प्रदेश कार्यक्रम प्रभारी राजेन्द्र शाह, सचिव विनोद चौहान, सुरेंद्र सिंह रांगड़, तारक बाछड़, उदयन कपूर, प्रयाग भट्ट, विनोद शर्मा, प्रीत ग्रोवर, सतीश गुंजाल, ललित पंत, विजय सुखीजा, प्रेम कांडपाल, महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा आदि अनेक नेतागण उपस्थित थे. आपदा व आबकारी मामले में कांग्रेस को घेरने में जुटी भाजपा को कांग्रेस ने विश्व हिन्दू परिषद, सपा, बसपा के सैकडों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराकर जवाब दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

पार्टियों में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंत्रणा जारी

किसे पकड़ें, किसे छोड़ें की राजनीति

सी. लाल/सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2017 अब तक के चुनावों से अलग रहेगा. भाजपा, बसपा व सत्ताधारी सपा अभी से मिशन-2017 की तैयारियों में जुट गए हैं. बसपा अपने परम्परागत दलित वोट बैंक के साथ अल्पसंख्यक, अतिपिछड़ा व सवर्ण समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी है, तो भाजपा लोकसभा चुनाव-2014 की तरह प्रदर्शन दोहराने के समीकरण निर्माण में जुटी है. सपा को जहां तक विश्वास है कि उसका परम्परागत यादव वोट बैंक के साथ अल्पसंख्यक उसका साथ नहीं छोड़ेगा. विधानसभा चुनाव-2012 में अतिपिछड़ी जातियां आरक्षण के मुद्दे पर सपा के साथ चली गई थीं, लेकिन अब इनका सपा से मोह भंग हो रहा है. विमुक्त जातियों का आरक्षण खत्म करने से मल्लाह, केवट, कहार, लोध, मेवाती, बंजारा, भर, औधियां, घोसी आदि जातियां पहले से ही नाराज थीं, उस पर अब गोरखपुर, संत कबीनगर में निषाद आरक्षण आन्दोलन के पटाक्षेप से निषाद-कश्यपों का भी सपा से मोह भंग होता दिख रहा है.

विधानसभा चुनाव-2017 में बसपा व सपा का मिथक लोकसभा चुनाव-2014 की भांति टूटने की पूरी सम्भावना है. लोकसभा चुनाव में सपा का परम्परागत यादव मतदाता व बसपा का दलित मतदाता बड़ी संख्या में भाजपा के साथ चला गया था. सपा सरकार के क्रियाकलापों से अतिपिछड़ों में काफी नाराजगी उपजी है. जिसके कारण यह वर्ग सपा से दूर जा रहा है. उत्तर प्रदेश में इस समय एआईएमआईएम, पीस पार्टी सहित कुछ अन्य मुस्लिम पार्टियां अपना पैर पसारने में मजबूती से जुटी हैं. इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा. सपा बसपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी होगी. सपा को विश्वास है कि वह पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में फिर से वापसी करेगी, लेकिन यह सत्तादंभ में पैदा हुई गलतफहमी के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि सपा शासन की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सपा नेताओं की जनता से दूरी व कुछ जिलों के जाति विशेष के उम्मीदवारों को नौकरियों में भरे जाने से अन्य वर्गों में भीषण नाराजगी है. समझदार यादव वर्ग भी नाराज ही चल रहा है.

उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण में 17 अति पिछड़ी व 11 विमुक्त जनजातियों का चुनावी दृष्टि से काफी महत्व है. 17 अति पिछड़ी जातियों की उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अन्य पिछड़े वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या में लगभग एक तिहाई यानी 15.30 प्रतिशत व विमुक्त जातियों की संख्या 17.60 प्रतिशत से अधिक है. यदि विधानसभा चुनाव-2002, 2007 और 2012 पर नजर दौड़ाई जाए, तो सत्ता का हस्तांतरण 3-4 प्रतिशत मतों के ही अन्तर से होता रहा है. विधानसभा चुनाव-2007 में बसपा को 29.65 व सपा को 25.75 प्रतिशत मत मिला था. वहीं विधानसभा चुनाव-2012 में सपा को 29.13, बसपा को 25.91 व भाजपा को लगभग 15 प्रतिशत मत मिला. लोकसभा चुनाव-2014 में भाजपा को 42.3 प्रतिशत, बसपा को 19.95 व सपा को 22.6 प्रतिशत मत मिला था. विधान सभा चुनाव-2017 में सामाजिक-जातिगत समीकरण में काफी उलटफेर की सम्भावना है. अभी तक जो तस्वीर उभर कर आई है, उसमें भाजपा व बसपा ही नम्बर-1 की पार्टी के रूप में देखी जा रही है. कानून व्यवस्था व अतिपिछड़ों (गैर यादव पिछड़ों) की उपेक्षा से माहौल सपा के खिलाफ है. ऐसे में भाजपा व बसपा इस माहौल को कैसे अपने पक्ष में कर पाती हैं, वह अभी भविष्य के गर्भ में है.

भाजपा को अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में जब भी उसकी सरकार बनी उसमें अति पिछड़ों, अति दलितों की मुख्य भूमिका रही. भाजपा के एक महामंत्री ने कहा कि सपा के यादवीकरण व खराब कानून व्यवस्था का लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा. दूसरा, भाजपा का जातिगत सामाजिक समीकरण अन्य दलों की अपेक्षा काफी मजबूत है. दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग चिन्तक चौधरी लौटन राम निषाद का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा से पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग का ही नहीं, अन्य वर्गों का भी मोह भंग हुआ है. अतिपिछड़ा वर्ग भाजपा के छद्म सामाजिक न्याय व सामाजिक समता, समरसता के चुनावी नाटक को समझ गया है, अब वह इस बहकावे में नहीं आएगा.

उत्तर प्रदेश के सामाजिक संतुलन का औसत देखें तो सामान्य वर्ग-20.94, अन्य पिछड़ा वर्ग-54.05, अनुसूचित जाति-24.95 व अनुसूचित जनजाति वर्ग-0.06 प्रतिशत है. पूरी आबादी में अल्पसंख्यक-14.6 प्रतिशत, यादव 10.46, मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग-10.22 प्रतिशत तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-33.34 प्रतिशत है. जिसमें अतिपिछड़ों की चुनाव में खास भूमिका होती है. अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी में निषाद/ मछुआरा-12.91, मौर्य/ कुशवाहा/ शाक्य/ काछी-8.56 प्रतिशत, कुर्मी/पटेल-7.46, लोध-किसान-6.06 प्रतिशत, पाल/बघेल-4.43, तेली/साहू-4.03, कुम्हार/ प्रजापति-3.42, राजभर-2.44, नोनिया/चौहान-2.33, विश्वकर्मा/ बढ़ई-2.44, लोहार-1.81, जाट-3.7, गूजर-1.71, नाई/ सविता-1.01 और भुर्जी/ कांदू-1.43 प्रतिशत हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित सात यादव कैबिनेट मंत्री हैं. वहीं गैर यादव पिछड़े वर्ग से राजेन्द्र चौधरी (जाट), राममूर्ति वर्मा (कुर्मी) को महत्वहीन विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. अत्यन्त पिछड़ों में विवादित गायत्री प्रसाद प्रजापति 17 अति पिछड़ी जातियों के अकेले ऐसा नेता हैं, जिन्हें मलाईदार विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. इससे अन्य अति पिछड़े काफी नाराज हैं. मांझी/गोड़िया समाज के शंखलाल मांझी, लोधी/किसान समाज के मानपाल सिंह वर्मा व राममूर्ति सिंह वर्मा, पाल/गड़ेरिया समाज के विजय बहादुर पाल व मौर्य/काछी/शाक्य/कुशवाहा समाज के विनय कुमार शाक्य को राज्यमंत्री बनाकर इन वर्गों का राजनीतिक अपमान ही किया गया है. ऐसे मंत्रिमंडलीय असंतुलन से अति पिछड़ा वर्ग में सपा के प्रति काफी असंतोष है.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2017 के मद्देनजर कांग्रेस व भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें हैं. कांग्रेस की नजर भी पिछड़ा वर्ग पर है. मिस्त्री व खत्री की कैमेस्ट्री फेल हो गई है. ऐसे में किसी पिछड़े/अतिपिछड़े को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा है. भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी के प्रति भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. मोदी-शाह की जोड़ी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति भी खास है. कयास लगाया जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह (कुर्मी), धर्मपाल सिंह (लोधी), प्रकाश पाल (बघेल/गड़ेरिया/धनगर), केशव प्रसाद मौर्य में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंप कर भाजपा पिछड़ा वर्ग कार्ड खेल सकती है. जो भी हो उत्तर प्रदेश में 2017 के विधान सभा चुनाव में अति पिछड़े वर्ग की भी अहम भूमिका रहेगी.

भाजपा-कांग्रेस बदलेगी अध्यक्ष, सपा भी सक्रिय

उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने पिछड़ा या दलित वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी है. दिल्ली-प्रयोग से बच रही भाजपा ने संघ की मदद से संगठन को मजबूत करने का काम तेज कर दिया है. उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी का अगस्त में ही कार्यकाल पूरा हो रहा है. लिहाजा, पार्टी आलाकमान ने नये अध्यक्ष की कवायद शुरू कर दी है. भाजपा के रणनीतिकार इस बार प्रदेश में संगठन की जिम्मेदारी पिछड़े या अनुसूचित जाति वर्ग के किसी ऐसे नेता को सौंपने पर विचार कर रही है, जिसके नेतृत्व में पार्टी में इस समूह के लोगों को बड़ी संख्या में जोड़ा जा सके और जो बड़े समूह से आता हो.

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दिनों पिछड़े और दलित समुदाय का आह्वान करते हुए कहा भी था कि उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर भाजपा काबिज हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनकी तकलीफ समझ सकते हैं. उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी इन्हीं वर्गों से जुड़े किसी नेता को सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है. आलाकमान का मूड और इच्छा भांपते हुए प्रदेश के कई नेता भाजपा के नये प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल भी हो गए हैं.

पार्टी की अंदरूनी रणनीतियों के जानकारों का कहना है कि ब्राह्मण और राजपूत को अध्यक्ष बनाने के बजाय अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से आने वाले ऐसे नेता जो संगठन में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, उनकी दावेदारी पर विचार किया जा रहा है. लेकिन एक विचार यह भी बन रहा है कि दलित समुदाय के ऐसे नेता को भी मौका दिया जा सकता है, जिसके साथ उनके समुदाय की बृहत्तर जनसंख्या हो. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इसका संकेत दे चुके हैं.

उधर, प्रदेश में मृतप्राय कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी में जान डालने की कोशिशों में लगी है. कांग्रेस के दो शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए जिंदा रहना उनकी प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है. कांग्रेस भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहती है. कांग्रेस का इरादा दूरगामी प्रयोग करने के मूड में है. प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री के बजाय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर विचार हो रहा है. पार्टी के अंदर लम्बे समय से श्रीप्रकाश जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग हो रही है. जायसवाल कांग्रेस मुखिया सोनिया गांधी के नजदीकी माने जाते हैं. इसी वजह से यूपीए-1 में उन्हें गृह राज्यमंत्री और यूपीए-2 में कोयला मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी.

समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बार तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा उन्होंने कन्नौज से विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया है. कन्नौज संसदीय क्षेत्र से अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव सांसद हैं. पति-पत्नी कन्नौज पर पूरी तरह दखल बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. डिम्पल ने कहा भी कि कन्नौज मुख्यमंत्री के दिल में बसता है. यह भूमि मुख्यमंत्री के लिए कर्मभूमि रही है और रहेगी. सीएम कन्नौज से ही 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. अखिलेश यादव मार्च 2012 तक कन्नौज से ही सांसद रहे हैं. उन्होंने यह सीट मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली कर दी थी. उसके बाद हुए उपचुनाव में डिम्पल वहां से जीतीं. 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां की तीनों सीटें कन्नौज सदर, तिरवा और छिबरामऊ जीत ली थीं. पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अखिलेश की कन्नौज-सक्रियता साफ-साफ दिख रही है. मुख्यमंत्री की पहल पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने कन्नौज में परफ्यूम पार्क लगाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं. इत्र के लिए दुनियाभर में मशहूर कन्नौज में 400 एकड़ जमीन पर परफ्यूम पार्क की स्थापना की जाएगी. ■

अखिलेश पर अपहरण का आरोप एनएचआरसी ने मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव को नोटिस जारी करके पूछा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर लगे अपहरण के आरोपों व आवेदक भरत गांधी के लखनऊ आवास पर हमला कराने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? आयोग के कार्यालय ने इस आशय का ई-मेल 23 जुलाई को भरत गांधी को भेजा है. भरत गांधी के केस (संख्या- 40582/24/48/2013 दिनांक-21/11/2013) पर आयोग ने अपना आदेश पारित किया है. मुख्यमंत्री पर ये आरोप दिल्ली में रह रहे मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले भरत गांधी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कन्नौज संसदीय उपचुनाव के दरम्यान एडवोकेट प्रभात पांडेय का अपहरण कर लेने का आरोप लगाया था. राजनीतिक समीक्षक भरत गांधी ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर बताया था कि अमेठी निवासी एडवोकेट प्रभात पांडेय का अपहरण करने के अलावा भरत गांधी के लखनऊ आवास पर हमला कराया था. इसलिये इस अपराध की जांच प्रदेश पुलिस के बजाय सीबीआई से कराई जाए. हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. भरत गांधी कहते हैं कि यूपी पुलिस के डीजीपी की जांच से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है. भरत गांधी ने आरोप लगाया कि आयोग के 2 मार्च के आदेश के अनुपालन में जो पुलिस जांच चल रही थी, उसको प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य गवाह अमेठी के एडवोकेट प्रभात पांडेय का 27 अप्रैल को दूसरी बार अपहरण करा लिया. पाण्डेय का पहली बार अपहरण तब कराया गया था, जब वे वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री की पत्नी डिम्पल यादव के खिलाफ पर्चा दाखिल करने 6 जून 2012 को कन्नौज गए थे. गत 27 अप्रैल को हुए दूसरी बार के अपहरण के दौरान उन्हें बुरी तरह मारा-पीटा भी गया. उन्हें डरा-धमका कर पुलिस में रपट दर्ज नहीं करने दिया गया और न मेडिकल जांच ही होने दी. भरत गांधी का कहना है कि पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की ही तरह ही प्रभात पांडेय के खिलाफ भी गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करके मुंह बंद करने की साजिश हो रही है. गैंग रेप के झूठे मुकदमे के खिलाफ अमेठी बार एसोसिएशन ने हड़ताल भी की. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
बिहार-झारखंड
10 अगस्त-16 अगस्त 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

चुनावी दांव पर विकास का एजेंडा

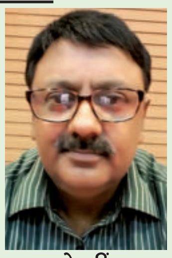

सरोज सिंह

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार का दसवां रिपोर्ट कार्ड जारी कर अपनी अब तक की उपलब्धियों का ब्योरा बिहार की जनता के सामने पेश किया है. इन उपलब्धियों के आधार पर अब वह नए जनादेश के लिए बिहार के मतदाताओं के बीच जाएंगे. बिहार में पंद्रह वर्षों का लालू-राबड़ी राज 2005 में समाप्त हो गया और उसी साल नवम्बर में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बिहारी नायक के तौर पर उन्होंने सूबे की सत्ता की कमान संभाली थी. बिहार ने गत दस वर्षों में विकास और सुशासन के संदर्भ में काफी कुछ हासिल किया है, यह आम धारणा है. विकास दर और प्रतिव्यक्ति आय के मामले में इस राज्य ने इस एक दशक में लंबी छलांग लगाई है.आधारभूत संरचनाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ. सड़कों के निर्माण का काम बिहार के आमजन को आकर्षित करता रहा, तो बिजली के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि न होने के बावजूद इसकी उपलब्धता बढ़ाने में नीतीश सरकार सफल रही है. स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे मानव विकास के मानकों पर सूबे में इस अवधि में भी काफी कार्य हुए. शिशु मृत्यु-दर में इसकी हालत देश के कई विकसित राज्यों से बेहतर हो गई है. नारी शिक्षा के साथ-साथ महिला और दलित-वंचित सामाजिक समूहों के सशक्तिकरण की दिशा में तो नीतीश सरकार ने प्रतिमान जैसा काम किया है. यह रिपोर्ट कार्ड, जैसा कि आम तौर पर होता है, नीतीश कुमार की दस साल के तीन चरणों की सरकार की ऐसी अनेक उपलब्धियों का दस्तावेज है. लेकिन यह भी सही है कि रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बहाने मुख्यमंत्री ने लोक-लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी. चुनावी साल होने के कारण यह होना ही था. हालांकि तोहफ़ों की घोषणाएं आमतौर पर सरकारी सेवाओं और सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से जुड़े विभिन्न समूहों तक ही सीमित रहीं. हालांकि तोहफ़े से पत्रकार भी नवाज़े गए. जिन तोहफ़ों की घोषणा की गई हैं, उन सभी की महीनों से चर्चा रही है. इनमें से पत्रकार पेंशन स्कीम के बारे में तो चालू वित्त वर्ष के बजट में भी उल्लेख किया गया था.

नीतीश कुमार की इन घोषणाओं में दो का असर राज्यव्यापी और दीर्घकालिक है. ये दोनों हैं, संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए वेतनमान और चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बढ़ोतरी का फैसला. अब राज्य सरकार के चिकत्सक 67 साल की उम्र तक सेवा में रहेंगे. पहले उनके लिए 65 वर्ष तक की सीमा थी. राज्य की अधिकांश सेवाओं में सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है. चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष है. अब इसमें और दो साल की बढ़ोतरी कर दी गई. हालांकि चिकित्सकों की मांग सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 70 वर्ष करने की थी, पर सरकार ने मात्र दो साल की बढ़ोतरी दी है. इससे राज्य की विभिन सेवाओं में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग तेज हो जाएगी. यह वास्तविकता है कि जिस पेशेवर समुदाय का दबाव जितना अधिक होता है, उसकी मागें उतनी जल्दी मानी जाती हैं. इस लिहाज से बिहार में चिकित्सकों का कोई जोड़ नहीं है और डाक्टरों की सदैव चलती रही है, सरकार चाहे जिस राजनीतिक दल की हो. बिहार सरकार अभियंता व अन्य तकनीकी सेवाओं के अधिकारियों के संगठनों से यह मांग की जाती रही है. अब उन्हें एकजुट होने और सरकार पर दबाव डालने का नया अवसर मिलेगा. इस फैसले का दूसरा प्रभाव भी है और वह ज्यादा घातक है. राज्य के मेडिकल कॉलेजों से निकल रही प्रतिभाओं के लिए इस सूबे में सेवा की गुंजाइश निरंतर कम होती जा रही है. अवसर का संकट ज्यादा गहरा हो जाएगा, वह चिकित्सा सेवा के अधिकारियों का मामला हो या मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों का. ये हालात दूसरी समस्याएं पैदा करते हैं जो अराजकता की ओर ले जाएंगे. इसी तरह, संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर नियोजित शिक्षकों के वेतनमान का मामला है. राज्य सरकार ने हालांकि इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी, पर उसे अमली जामा अब पहनाया गया है. राज्य के सवा चार लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, उन्हें जुलाई का वेतन नए नियम के अनुसार मिलेगा. इन शिक्षकों को अब साढ़े नौ हजार रुपये प्रतिमाह से लेकर उन्नीस हजार तीन सौ रुपये प्रतिमाह तक मिलेंगे. यह संघे शक्ति कलयुगे की नीति का ही परिणाम है. बिहार में संविदा पर नियोजित शिक्षकों की संख्या काफी अधिक हो गई है, नियमित तौर पर नियुक्त शिक्षकों कि तुलना में इन शिक्षकों ने शुरुआत में अपनी लड़ाई खुद लड़ी.

नीतीश कुमार की इन घोषणाओं में दो का असर राज्यव्यापी और दीर्घकालिक है. ये दोनों हैं, संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए वेतनमान और चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र में बढ़ोतरी का फैसला. अब राज्य सरकार के चिकत्सक 67 साल की उम्र तक सेवा में रहेंगे. पहले उनके लिए 65 वर्ष तक की आयुसीमा थी. अधिकांश सेवाओं में सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है. चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष है. इसमें दो साल की बढोतरी कर दी गई.

बाद में राज्य के स्थापित शिक्षक संगठनों और नेताओं ने इनका साथ देना ही श्रेयस्कर समझा. बिहार में पेशेवर समूहों में शिक्षकों के समूह को बहुत ही असरदार माना जाता रहा है. कहते हैं, अपनी पेशाई एकजुटता ने शिक्षकों को यह हक दिलाया है. यह संविदा पर नियोजित अन्य सेवाओं के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए प्रेरक तत्व बन सकता है. कुछ विभागों के संविदाकर्मी वेतनमान और ग्रेड पे के लिए पिछले महीनों से आंदोलन भी कर रहे है. इन आंदोलनों को अब नई ताकत मिलेगी. नीतीश सरकार ने अपने दसवें साल में टोला सेवकों, कृषि सलाहकारों और शिक्षा स्वयंसेवकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है. इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका, ममता, आशा सहित अनेक काम में लगे लोगों के लिए नीतीश कुमार ने कई सुविधाओं की घोषणा की है. इन सुविधाओं में इन सभी कार्यों में लगे लोग अब 60 साल की उम्र तक काम करेंगे. काम के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में इनके परिजनों को चार लाख रुपये का क्षतिपूर्ति अनुदान मिलेगा.

यह रिपोर्ट कार्ड वस्तुत: नीतीश-राज के शुक्लपक्ष का ही दस्तावेज है. फिर भी, सरकार के कामकाज के कई कृष्णपक्ष की झलक इससे स्वत: मिल जाती है. नारी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और अति पिछड़े व महादलित सामाजिक समूहों के लिए नीतीश सरकार के काम ऐसे हैं जहा लोगों को शुक्लपक्ष ही दिख रहा है. बाकी क्षेत्रों में ऐसा कहना कठिन है. मसलन, बिहार औद्योगिक विकास के मामले में अब भी कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर सका है. इसका सीधा असर पड़ा है सूबे में रोजगार के अवसर पर और यहां से कुशल अथवा अकुशल मजदूरों के पलायन पर. रिपोर्ट कार्ड में यह तो कहा गया है कि राज्य में 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है, पर यह कहीं नहीं कहा गया है कि ये कैसी इकाइयां हैं और यह चालू होने के किस चरण में है? चूंकि इस रिपोर्ट कार्ड में गत दस साल की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, इसीलिए कुछ चीनी मिलों के चालू होने की बात फिर दुहरायी गई है. दरभंगा के अशोक पेपर मिल को पुनर्वास पैकेज देने की बात तो कही गई है, पर यह अब तक बंद ही क्यों है, इसका खुलासा नहीं किया गया है. यह तो बताया गया है कि सरकार ने दस साल में सरकारी क्षेत्र में कितनी नौकरियां दी, पर यह नहीं बताया गया है कि इन औद्योगिक इकाइयों में कितने नए रोजगार के अवसर पैदा हुए है?

-शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

एक नज़र
चुनावी हलचल

भारत विश्व गुरु बनाने की राह पर

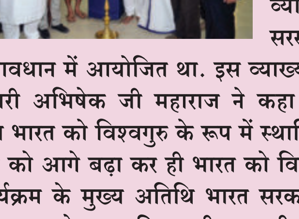

दिल्ली के कॉन्स्टूशन क्लब आफ इंडिया के सभागार में स्वामी करपात्री जी महाराज के स्मृति में भारत आज और कल विषय पर राष्ट्रीय व्याख्यान स्वामी सहजानन्द सरस्वती सामाजिक न्याय मंच के तत्वावधान में आयोजित था. इस व्याख्यान का उद्घाटन करते हुए ब्रहमचारी अभिषेक जी महाराज ने कहा की स्वामी करपात्री जी महाराज भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना चाहते थे. इनके विचारों को आगे बढ़ा कर ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने कहा की स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म पुरुष थे, इनकी पुस्तक राम राज और मार्क्सवाद हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता को पढ़ना चाहिए. कार्यक्रम में भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि मोदी देश के सर्वांगीण विकास हेतु जिस तरह से कार्य कर रहे है इससे भारत का कल बेहतर होगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंच के अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने भारत सरकार से स्वामी करपात्री जी महाराज के नाम पर वेद अनुसंधान केंद्र की स्थापना की मांग की. कार्यक्रम में निम्स विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डा. बी.एस तोमर, फिल्म अभिनेता राजपाल यादव, केजे जोसमोन, गिरजन नायर, उमेश राय, डॉ. एस. पी. राय, सुनीता दुग्गल, सुनील शर्मा ने भी समारोह को सम्बोधित किया.

– भारती

जदयू का हर घर दस्तक कार्यक्रम बेअसर : निरंजन

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू का हर घर दस्तक, घर–घर दस्तक कार्यक्रम पर रालोसपा के युवा नेता निरंजन कुशवाहा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि विकास का ढिंढ़ोरा पीटने वाली जदयू सरकार अब जनता का दरवाजा पीट रही है. जनता से पूछ रही है कि राज्य में विकास हुआ या नहीं. कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका जनता से सम्पर्क टूट चूका था, जो अब सम्पर्क यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क बनाने में जुटे है, लेकिन बिहार की आवाम ने इसे भी नकार दिया है. आगे निरंजन ने कहा की नीतीश कुमार टम टम और लाठी के युग से बिहार को आगे बढ़ाना चाहते है. जिसका जवाब बिहार की जनता आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में देगी.

– रजनीकांत पांण्डेय

गोपालगंज सीट पर कांग्रेस की दावेदारी

गोपालगंज विधानसभा सीट पर महागठबंधन के नेताओं की दावेदारी अब जोर पकड़ने लगी हैं. राजद–जदयू और कांग्रेस के नेताओं ने टिकट पाने के जुगाड़ में जूट गये हैं. कुशवाहा समाज पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में सुकुलवां मेला ग्राइंड में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाने की मांग की. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो–दो अभिकर्ता व 11 सदस्यीय पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया गया हैं. जो अगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन अपना काम करेंगे कांग्रेस नेता प्रेमनाथ राय शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष विनोद दूबे, नोजुबुल हक, मणिभुषण सिंह, प्रमोद कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव, जुल्फिकार अली भुटटो, महाताब आलम, परमानंद कुशवाहा, राजकुमार यादव, ब्रजेश सिंह, पंकज पांण्डेय, मनीष कुमार, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष इमामुल हक, खालिद हैदर, धनराज सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इतखार हैदर आदि नेताओं ने कहा कि केन्द्र में बैठी भाजपा की सरकार बिहार के साथ सौतेलापन कर रही हैं.■

– अखिलेश मिश्र

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

हृदय रोग कारण और उपचार
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. मो. आबीद हुसैन CARDIOLOGIST-NAVADA
आजकल लोग अपनी जीवन शैली को सही नहीं रख पाने की वजह से कई बीमारियों को अपना बना लेते हैं। जीवन शैली के कारण होने वाले प्रमुख रोगों में हृदय रोग भी है। नवादा के कुशल चिकित्सक डॉ. मो. आबिद हुसैन ने कुछ इस प्रकार लोगों को सुरक्षित रहने के उपाय बताये:–कारण–बी.पी. का बढ़ना, डायबिटिज होना, धुम्रपान करना, फैमिली हिस्ट्री का होना, ज्यादा मोटा होना, सही लाईफ स्टाइल में बदलाव आना। थाईराइड होना, कोलस्ट्रोल का बढ़ जाना। लक्षण –चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, जबड़ा से नाली तक दर्द होना, चलने पर साँस फुलना, बेहोशी हो जाना, घबराहट होना या वोमेटिंग होना, इसके लक्षण दिखाई देते हैं। उपचार: खानपान में केवल सादा भोजन ही लें, मिठे फल न खायें, फल में सन्तरा और नासपाती का प्रयोग करें। 30 से 45 मीनट तक तेजी से चलें, नियमित व्यायाम करें, बी.पी. डायबिटिज, और अपनी जीवन शैली के साथ– साथ कोलस्टरोल को भी नियंत्रित रखें। - रजनीकान्त पाण्डेय
URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp. Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma

रून्नीसैदपुर विधानसभा

भाजपा में टिकट के दावेदारों की भरमार

वाल्मीकि कुमार

ब्रहमप्रकाश शाही, मिंदर साह, वीरेंद्र प्रसाद सिंह, रामबाबू सहनी, शशिनाथ सिंह, विकास शर्मा, युगल किशोर गुप्ता, मनोज कुमार

सीतामढ़ी जिले का रून्नीसैदपुर विधानसभा सीट पर वर्तमान में जदयू का कब्जा है. इस सीट से जदयू की गुडडी देवी प्रतिनिधित्व कर रही है. सूबे बिहार की राजनीति में अदला–बदली का आलम है कि पिछले चुनाव में आमने–सामने टक्कर देने वाली राजद अबकी बार जदयू के साथ है, तो सामने कल का राजनीतिक साथी रही भाजपा आज विरोधी टीम की कप्तानी कर रही है. नये राजनीतिक समीकरण के तहत एक और जदयू के साथ राजद व कांग्रेस जैसी पार्टियां है तो दूसरी और भाजपा के साथ लोजपा व रालोसपा चुनावी खेल खेलने को तैयार है. पिछले साल सम्पन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के तहत रालोसपा के राम कुमार शर्मा की जीत से जहां भाजपा खेमा में नमो आंधी का आसार पुन: दिखायी दे रहा है, वही जदयू के सूबे में विकास की सफल पाली पर पूरा भरोसा है. जदयू खेमा का मानना है कि भाजपा चुनावी पार्टी बन कर रह गयी है, विधानसभा चुनाव में नीतीश–लालू के विश्वास को रून्नीसैदपुर में भेदना भाजपा के लिए आसान नहीं है. जहां तक स्थानीय विधायक के कार्यकाल का सवाल है तो इसे किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में कम नहीं आका जा सकता है. वैसे फिलहाल चल रही राजनीतिक चर्चाओं को अगर किनारा कर दिया जाये तो सबसे अहम चुनौती भाजपा के लिए प्रत्याशी का चयन साबित हो सकता है. इसके दो प्रमुख कारण सामने आ रहे है. पहला यह कि भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाने की मांग का मन बना रहे है और दूसरा कि टिकट के दावेदारों की संख्या में कमी का नाम नहीं ले रहा है.

क्षेत्र में चल रही चुनावी चर्चाओं पर यकीन करे तो अब तक इस सीट से केवल भाजपा के एक दर्जन से अधिक नाम सामने आ रहे है. इनमे रून्नीसैदपुर विधानसभा महासंपर्क प्रमुख सह परिवर्तन यात्रा के सभा प्रभारी रहे शशिनाथ सिंह के नाम का चर्चा जोरो से है. इनके अलावा प्रो. वीरेंद्र प्रसाद सिंह, जिला भाजपा उपाध्यक्ष विकास शर्मा, युवा भाजपा नेता सह पूर्व मंत्री नवल किशोर शाही का पुत्र ब्रहमप्रकाश शाही, कैप्टन पुष्कर झा, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे गिरीजानंदन यादव, राजीव कुमार यादव, मुखिया रामबाबू सहनी, मिंदर साह, राम बहादुर साह, युगल किशोर गुप्ता, रामायण कुमार अशोक कुमार सिंह व पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार समेत अन्य शामिल है. बताया जाता है कि रून्नीसैदपुर का 33 एवं नानपुर का 5 पंचायत को मिलाकर इस क्षेत्र का गठन किया गया है. जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या लगभग सवा 2 लाख है. गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में भूमिहार मतदाताओं की संख्या करीब 36 हजार, यादव 31 हजार, वैश्य 25 हजार, मुस्लिम 21 हजार, पिछड़े वर्ग की संख्या 26 हजार है. जबकि दलित व महादलित की संख्या भी निर्णायक बतायी जाती है. जहां तक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का सवाल है तो अब तक इस सीट से प्रतिनिधित्व का कमान कांग्रेस, जनता पार्टी, राजद व जदयू संभाल चुकी है. एक मौका भाजपा के हाथ आते–आते रह गया था, तब से अब तक भाजपा कार्यकर्ता अपनी बारी के इंतजार कर रहें है. जदयू–भाजपा गठबंधन टूटने के बाद पहली बार भाजपा को एक सुनहरा अवसर सामने नजर आ रहा है. वैसे चुनाव में अभी वक्त है. गठबंधन राजनीति के तहत सीट किस दल के पाले में जायेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है. परंतु भाजपा गठबंधन के तहत रालोसपा व लोजपा के कार्यकर्ता भी टिकट को लेकर प्रयासरत है. चर्चा चल रही है कि हर हाल में भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय प्रत्याशी की मांग पर डटे है. क्षेत्र में जो चर्चा चल रही है, अगर इस पर यकीन किया जाये तो शशिनाथ सिंह व ब्रहमप्रकाश शाही के संबंध में पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी अंजान नही है. शेष संभावित प्रत्याशी अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे है.

एक मौका भाजपा के हाथ आते–आते रह गया था, तब से अब तक भाजपा कार्यकर्ता अपनी बारी के इंतजार कर रहें है. जदयू–भाजपा गठबंधन टूटने के बाद पहली बार भाजपा को एक सुनहरा अवसर सामने नजर आ रहा है. वैसे चुनाव में अभी वक्त है. गठबंधन राजनीति के तहत सीट किस दल के पाले में जायेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है. परंतु भाजपा गठबंधन के तहत रालोसपा व लोजपा के कार्यकर्ता भी टिकट को लेकर प्रयासरत है.

मगर गठबंधन के तहत सीट के बंटवारा का सभी को इंतजार है. इस सीट से भाजपा के अलावा गठबंधन दल के लोजपा व रालोसपा से भी कई चेहरे दावेदारों की सूचि में शामिल है. अगर सीट गठबंधन के तहत लोजपा अथवा रालोसपा के पाला में जाती है तो भाजपा कार्यकर्ता के लिए यह कष्टदायक साबित हो सकता है. अब इस सीट पर कब्जे को लेकर भाजपा गठबंधन चुनाव मैदान में अपना जौहर दिखाने का किसको मौका देती है इस पर लोगों की नजर टिकी है. वैसे जदयू समर्थक सीट पर अपनी दावेदारी कायम रखने को लेकर एकजुट नजर आ रहे है.■

feedback@chauthiduniya.com

चुनावी दांव पर विकास का एजेंडा

पृष्ठ 17 का शेष

बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा हासिल है. पर यह सेक्टर कितने लोगों को रोजगार दे रहा है या सूबे के पर्यटक–स्थलों का किस हद तक दोहन इन वर्षों में किया गया, यह जानकारी देने में यह दस्तावेज विफल है. बिहार सरकार का यह दसवां रिपोर्ट कार्ड कृषि विकास की जरूरतों को शिद्दत से रेखांकित करता है और इसके लिए कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन व कृषि कैबिनेट के गठन को बतौर उपलब्धि पेश करता. पर, यह नहीं बताता कि कृषि पैदावार में लगभग जड़ता की स्थिति क्यों है और कृषि विकास की योजनाओं की क्या हालत है? बिहार के आर्थिक विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को काफी महत्वपूर्ण माना गया है. पर रिपोर्ट नहीं बताती कि इस क्षेत्र में सरकार के स्तर पर क्या पहल रही, कुछ हुआ भी है या नहीं. इसमें यह बताया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोप में इन दस वर्षों में कोई पांच सौ कर्मियों को बर्खास्त किया गया है. पर, यह जानकारी नहीं दी गई है कि पिछले लंबे अर्से से यह काम शिथिल क्यों है, इस संदर्भ में दायर मुकदमों को निपटाने की गति तेज क्यों नहीं है और बड़े नौकरशाहों पर क्यों कार्रवाई चयनित और सीमित ही क्यों रही है. ऐसे अनेक सवालात यह रिपोर्ट कार्ड पैदा करता है. हालांकि सरकार का राजनीतिक नेतृत्व कम समय का तर्क दे सकता है. पर, दस साल का निरन्तर दो कार्यकाल किसी सत्ता की राजनीतिक इच्छा–शक्ति के आकलन के लिए कम समय नहीं होता है.

बिहार में यह चुनाव काल है और अपने इस रिपोर्ट कार्ड के साथ नीतीश कुमार चुनावी अखाड़े में जा रहे है. नीतीश कुमार के विरोधी भी इसे अस्वीकार करने की हालत में नहीं हैं कि उन्होंने विकास को बिहार की राजनीति के केन्द्र में ला दिया है और सूबे में इसकी भूख जगाई है. गत कई दशकों से इस पिछड़े राज्य की राजनीति के एजेंडा से विकास गायब जैसा था. यह भूखंड भारतीय जनतंत्र के अंधेरे इलाके में जीवन निरन्तर संकट में घिरता जा रहा था. यहां से मजदूरों का पलायन तो हो ही रहा था, व्यावसायी समूहों का भी पलायन तेज हो चुका था. सत्ता का इकबाल अपने न्यूनतम स्तर पर था और आम हालात निरन्तर डरावने होते जा रहे थे. ऐसे में सत्ता नीतीश कुमार के हाथ– तबके एनडीए के हाथ– आई जिसमें जनता दल(यू) और भारतीय जनता पार्टी थी. उन वर्षों में अर्थात नवम्बर 05 से जून 13 तक– नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ कई फ्रंट पर काम किए. इन प्रशासनिक और राजनीतिक प्रयास व पहल ने राज्य में विकास और सुशासन का आभा–मंडल तैयार किया. लेकिन वास्तविकता तो यह भी है कि नीतीश राज का दूसरा दौर (वर्ष नवम्बर 10 के बाद) ऐसा नहीं रहा. हालांकि सरकार के नायकों के फीलगुड से फुल जाने के कारण हालात बदलने लगे थे और तत्कालीन एनडीए सरकार कई आरोपों से भी घिर गई थी. लेकिन संकट जून 13 में ज्यादा गहरा हो गया जब नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में एनडीए बंट गया, नीतीश कुमार उससे अलग हो गए. नीतीश कुमार के अब तक के राजनीतिक सहयोगी भाजपा राज्य का सबसे शक्तिशाली विपक्षी दल बन गया. लालू प्रसाद और उनका राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस सरकार के साथ हो गई. इसके बाद की कहानी बिहार के लिए सुखद नहीं रही न सत्ता के इकबाल के संदर्भ मे न विकास के. राजनीतिक वर्चस्व के संघर्ष में क्षति बिहार की ही हुई–हर नजरिये से. इसके साथ ही सच तो यह भी है कि नीतीश राज की उपलब्धियों में भाजपा की भी हिस्सेदारी है, पर दुर्भाग्य कि इसकी चर्चा नहीं होती.■

feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

भाजपा के दावेदार हैं डॉ. मिथिलेश

सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा सीट से भाजपा नेता डॉ मिथिलेश कुमार दावेदारी को लेकर प्रयासरत है. बताया जाता है कि जदयू के विकास को क्षेत्र के लोगों ने देख लिया है. अबकी बार बाजपट्टी के आम लोग भाजपा के पक्ष में एकजुट है. आसन्न चुनाव में भाजपा की और से अगर मौका मिला तो डॉ मिथिलेश जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यो से लोगों को अवगत कराते हुए एक मौका देने का आग्रह करेंगे. पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में आयोजित पीएम की परिवर्तन रैली की सफलता पर कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है.

–गोविंद कुमार

चुनाव में भाग्य आजमायेंगे सेवा निवृत्त शिक्षक

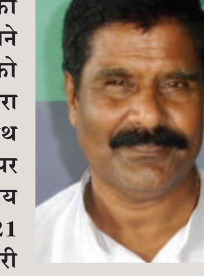

सीतामढ़ी जिले में अबकी बार चुनावी समर में न केवल राजनीतिक दल के नेता आने को आतुर है, बल्कि अब शिक्षा का अलख जगाने वाले शिक्षक भी राजनीति में भागीदारी को लेकर आगे आने लगे है. रीगा प्रखंड के रमनगरा गांव निवासी सेवा निवृत्त शिक्षक बैद्यनाथ प्रसाद रमन ने अबकी बार राजद की टिकट पर सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाने का मन बनाया है. तकरीबन 21 प्रतिशत मतदाता संख्या वाले कुशवाहा बिरादरी के रमन की चर्चा जोरो पर है. बताया जाता है कि उनकी दावेदारी के साथ ही लोगों ने उनकी योग्यता व समाज एवं राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच को चर्चा का विषय बना लिया है. कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान में राजनीतिक माहौल अलग होता जा रहा है. ऐसे में शिक्षा जगत से जुड़ा रहने वाले व्यक्ति का राजनीति में बेहतर योगदान साबित हो सकता है.

– विकास

खर्च करोड़ों, आमदनी फूटी कौडी नहीं

जब नंदन मार्केट पूर्ण रूप से तैयार हो गया तो उंचे रसुख वाले संभ्रांत परिवार से आने वाले राजनेता, विधायक तथा बड़े–बड़े पूंजीपतियों नें प्रशासनिक अधिकारियों की सांठ–गांठ से सरकारी मार्केट की दुकानों को अपने नाम पर या फिर अपने रिश्तेदारों के नाम पर आवंटित करा लिया और किराए पर दे दिया. जहां अब विभिन्न प्रकार के अवैध तथा अनैतिक कार्यो के का अड्डा बन गया है. शिक्षित बेरोजगारों के लिए बने इस बाजार में एक भी दुकान शिक्षित बेरोजगारों को नहीं मिली. जिससे उनमें मायूसी छा गई जिससे बेरोजगार– बेरोजगार ही रह गए. नन्दन मार्केट के निर्माण में सरकार का करोडों खर्च हुआ, यदि भूमि का मूल्यांकन सहित बाजार का मूल्यांकन किया जाए तो आंकडा अरबों रूपये तक जा सकता है. बावजूद प्रशासनिक उदासीनता, जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण सरकार के खाते राजस्व के रूप में फूटी–कौड़ी भी प्राप्त नहीं हो रहा है. तत्काल स्थिति यह है कि जो मार्केट कम्पलेक्स से शहर के सौंदर्यकरण में इजाफा होना था, वहां आज शहर के लोग कूड़ा–कचरा फेंक जाते है.■

– राकेश कुमार

सीवान

सोशल मीडिया पर छाये नेताजी, चलने लगे बयानों के तीर
पांच साल बाद नेताजी को अब याद आई जनता की

शंभू प्रसाद अभय

हरेन्द्र दूबे, अभिषेक कुमार सिंह, अवधेश सिंह कुशवाहा, एहतेसामुल हक सिद्दीकी

बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के पहले ही नेताजी जनता के बीच जाने एवं उनके दिलो दिमाग में छा जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए है. इसके लिए कोई रथ पर सवार होकर तो कोई जनता के दरवाजे पर पहुंच कर अपनी बात रख रहा है. पिछले पांच वर्षो में नेताजी को जनता की याद व क्षेत्र के विकास की याद नहीं आयी. अचानक जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तब नेताजी जनता के बीच जाने लगे. जहां जनता उन्हें अपने गुस्से का शिकार बना रही है. माननियों में आये इस बदलाव से जनता हैरानी में है कि नेताजी सभी जगह दिखने लगे है. कल तक नेताजी से मिलने के लिए जनता जब उनके आवास पर आती थी तो पता चलता था कि नेताजी पटना है. जनता भाग दौड़ करती थक जाती थी, लेकिन नेताजी से मुलाकात नहीं होती थी. अब तो नेताजी लगातार जनता के बीच दिखने लगे है. विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मौका हासिल करने के लिए वह जनता के सुख–दुख में भी भाग लेने लगे है तथा रुपये भी खर्च कर रहे है. जिले में कुछ ऐसे भी विधायक है जो पांच वर्षो में जनता की समस्या सुनने हेतु कभी क्षेत्र में गए ही नहीं. लोगों का कहना है कि विधायक पांच–सात बार क्षेत्र में आए होगें, वो भी शादी समारोह में भाग लेने के लिए या उद्घाटन हेतु. विधायको की इस लापरवाही से लोग काफी नाराज है. लोगों की माने तो जिले में कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जो जीतने के बाद जनता के बीच में लगातार गया हो. विधायको के अलावा संभावित उम्मीदवार भी लगातार क्षेत्र भ्रमण में लगे है. सीवान विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता हरेन्द्र दुबे,बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से राजद अकलियत कमेटी के प्रदेश महासचिव मो. एहतेसामुल हक सिद्दीकी, व कांग्रेस नेता रिजवान अहमद, दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से राल–ोसपा के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह कुशवाहा आदि भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है तथा लगातार जनसंपर्क कर रहे है. इन नेताओं का कहना है कि पार्टी अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा तथा जनता के आर्शीवाद से जीत होगी.

वहीं जनता के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए नेताजी विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाने लगे है. भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रथ जिले के आठो विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चूका है. सीवान के भाजपा विधायक ब्यासदेव प्रसाद, भाजपा के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु कुमार सिंह, विधायक रामायण मांझी, विधायक डॉ देवरंजन सिंह, विधायक विक्रम कुंवर के अलावा सांसद ओमप्रकाश यादव, विधान पार्षद टुन्नाजी पांडेय आदि भी इस रथ को क्षेत्रों में घुमा रहे है. वहीं जदयू के विधायक श्यामबहादुर सिंह, विधायक कविता सिंह, जिलाध्यक्ष मुर्तजा अली कैसर, के अलावा जदयू के तमाम नेता एवं कार्यकर्ता भी घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे है. अपनी बातों को जनता के बीच ले जाने के इस तरीके के बावजूद नेताजी सोशल मीडिया को प्रचार–प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम बना चुके है. महागठबंधन में हाहाकार, कहां गयी लालू–नीतीश बयार, जब बनेगी भाजपा सरकार तब आयेगी बिहार में बयार, आगे बढ़ता रहा बिहार, फिर एक बार नितीश कुमार. यह इन दिनों सोशल मीड़िया पर चल रहे राजनीतिक वार का नमूना मात्र है.

सीवान में इस समय में सोशल मीडिया, खास कर फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे किस्म–किस्म कि प्रचार चलाना शुरू हो गए है. जो यह बताने के लिए काफी है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता पर कब्जा करने का खेल शुरू हो गया है. प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लोकल स्तर पर नेता इसके जरिये अपनी ब्रांडिंग बखूबी कर रहे है. दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक की इस रार का सोशल मीडिया वार अभी से शुरू हो चुका है. नेट प्लेटफार्म पर अपनी धुन अपना राग का प्रलाप नेताओं द्वारा किया जाने लगा है. कही अबकी बार भाजपा सरकार तो कही नीतीश कुमार के पोस्ट दिखने लगे है. फेसबुक और वाट्सएप इसके वाहक बने हुए है.

सीवान में इस समय में सोशल मीडिया, खास कर फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे किस्म–किस्म कि प्रचार चलाना शुरू हो गए है. जो यह बताने के लिए काफी है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता पर कब्जा करने का खेल शुरू हो गया है. प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लोकल स्तर पर नेता इसके जरिये अपनी ब्रांडिंग बखूबी कर रहे है. दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक की इस रार का सोशल मीडिया वार अभी से शुरू हो चुका है. नेट प्लेटफार्म पर अपनी धुन अपना राग का प्रलाप नेताओं द्वारा किया जाने लगा है. कही अबकी बार भाजपा सरकार तो कही नीतीश कुमार के पोस्ट दिखने लगे है. फेसबुक और वाट्सएप इसके वाहक बने हुए है. ऐसे ही भाजपा के एक प्रचार पर नजर डाले विकास की राह पकड़ेगा बिहार अबकी बार बीजेपी सरकार. सबके सपने हो साकार, खिले कमल, महके बिहार. भाजपा समर्थक जब इतना बढ़चढ कर बोल रहे है तो नितीश समर्थक भी कहां पीछे रहने वाले है. उन पर नजर डालिए यह हमारा नारा है बिहार हमको प्यारा है. युवाओं की धड़कन है नीतीश महिलाओं का सम्मान है. नीतीश शिक्षा का आधार है. नीतीश प्रगति की उम्मीद है. नीतीश बढ़ते बिहार की शान है. नीतीश बदले विचार बदलेगा बिहार. अब जब वह लोग मैदान में है तो बड़हरिया विधानसभा से कांग्रेस नेता रिजवान अहमद, सीवान विधानसभा क्षेत्र से हरेन्द्र दूबे, के अलावा कई विधायक भी फेसबुक व वाट्सएप का भरपूर राजनीतिक उपयोग हो रहा है. मामला यहीं तक सीमित नहीं है ऑडियो मैसेंज भी फॉरवार्ड हो रहे है. जिसमें अपने–अपने तरीके से अपने–अपने नेता की तारीफ की जा रही है. सोशल मीडिया पर सबको सच्चा जनसेवक बताया जा रहा है. कई वैसे नेता भी है जिन्हें फेसबुक व वाट्सएप चलाने नहीं आता है तो वे एक–एक वेतन पर आदमी रखकर फेसबुक वाट्सएप चलवा रहे है. लेकिन यह तो पब्लिक है सब जानती है. पब्लिक का कमेंट्स भी जबरदस्त तरीके से आ रहे है, जिसको पढ़ते ही नेताजी नाक भौं सिकुड़ रहे है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र
चुनावी हलचल

बेलदौड़ के लिए संघर्ष रहेगा जारी : विद्यार्थी

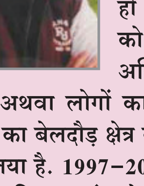

यह हना मुनासिव नहीं होंगा कि बेलदौड़ विधानसभा क्षेत्र में सशक्त जननेता विहीन है.यूं तो इस क्षेत्र का भले ही प्रतिनिधित्व का अवसर स्व .घनश्याम सिंह, सत्यनारायण सिंह व पन्ना लाल सिंह पटेल को मिला हो लेकिन जन सरोकार से जुड़े ज्वलंत समस्याओं को लेकर संघर्ष रहने वाले तेज तर्रार युवा तुर्क नेता अखिलेश कुमार विद्यार्थी के आमजनों से मिलने–जुलने अथवा लोगों का हर प्रकार से मदद करने की प्रवृति व समरस अंदाज का बेलदौड़ क्षेत्र की जनता कायल ही नहीं, बाल्कि उन्हें सर आंखों बैठा लिया है. 1997–2000 तक आखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय मुम्बई सम्भाग शिक्षक संघ के सचिव व 2007–2011 तक आईजीएनओयू, डीपीई में काउन्सलर के पद रहे जिससे नियोजित शिक्षकों में इनका अच्छा प्रभाव रहा है. कुछ लोगों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बेलदौड़ विधानसभा क्षेत्र से नये चेहरे के रूप में अखिलेश को राजद कांग्रेस व जदयू, एनसीपी महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाता है तो एक मुश्त समीकरण का मत मिल सकता है. यहां कोई कौरव– पांडव का बिखराव नहीं कर पायेंगे. यहां कौरव–पांडव मिलकर यादव समुदाय का मत विभाजन कर सकते हैं. ऐसे में बेलदौड़ की सीट पर नये चेहरे उतारना महागठबंधन दल के लिए लाजमी होगा.

– गीता कुमार

उद्घाटन व शिलान्यास विकास का प्रतीक : गुड्डी

सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं का कार्यान्वयन चरम पर है. पिछले दिनों स्थानीय जदयू विधायक गुडडी देवी ने आइएपी योजना के तहत मोरसंड मध्य विद्यालय बालक से रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर पीसीसी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इससे पूर्व विधायक ने क्षेत्र के गुरूदह गौसनगर पंचायत में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत तकरीबन साढ़े 7 लाख की लागत से निर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया. और लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में रून्नीसैदपुर क्षेत्र में समस्या की तलाश विरोधियों के लिए एक चुनौती बन जायेगी. विधायक ने हर घर दस्तक कार्यक्रम में भागीदारी के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता ही पार्टी की ताकत है. मोरसंड में आयोजित कार्यक्रम में पैक्स अध्यक्ष कुमार संजीव, विनोद कुमार सिंह, सोहन सिंह, अनिल कुमार सिंह, श्याम किशोर सिंह, चंचल कुमार, माधव कुमार व कंचन कुमार एवं गौसनगर में पूर्व मुखिया मो. फिरोज आलम, राम इकबाल साह, मो. रेजा, मो. हमायु रजा, संजय कुमार, सुरेंद्र राम, उपेंद्र राम व मो. सागीर समेत अन्य लोग शामिल थे.

– विभा सिन्हा

शोक व्यक्त

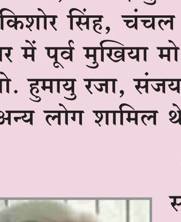

सीतामढ़ी जिला में पत्रकारिता के मजबूत स्तंभ रहे वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र प्रसाद सिंह के असामयिक निधन पर समाज के सभी तबके में शोक व्याप्त है. पिछले दिनों अमरनाथ यात्रा से लौटने के क्रम में अचानक हृदय गति रूकने के कारण इनकी मौत हो गयी. सत्येंद्र प्रसाद सिंह के निधन पर जिले के अलग–अलग स्थानों पर शोक सभाओं का क्रम जारी रहा. सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सिंह के निधन को जिले के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की है. शोक व्यक्त करने वालों में पूर्व सांसद नवल किशोर राय, सांसद राम कुमार शर्मा, पूर्व मंत्री दे–वेशचंद्र ठाकुर, पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद, नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू, जदयू विधायक गुडडी देवी, पूर्व विधायक राम नरेश प्रसाद यादव, डॉ रेणु चटर्जी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला, शिवहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मो. असद, राजद जिलाध्यक्ष मो.शफीक खां, भाजपा नेता डॉ मिथिलेश कुमार, जदयू नेता भरत प्रसाद, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार व विभा रानी, अध्यक्ष अमिताभ कुमार, प्रो. जीतेंद्र कुमार झा, प्रो. श्याम किशोर सिंह, सुबोध कुमार, रामा शंकर शास्त्री, कृष्ण मुरारी सिंह, अवध बिहारी उपाध्याय, शिव कुमार, देव कुमार, समेत अन्य सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आलावा जिले के पत्रकार शामिल है.■

– ब्रजेश कुमार

चुनावी हलचल

मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन

10 सूत्री मांगों के समर्थन में वाम मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सीतामढ़ी जिला में जुलूस निकाल कर बाजार बंद कराया. शहर में मोर्चा के जिला संयोजक जय प्रकाश राय, सीपीआई जिला सचिव राज किशोर ठाकुर, सीपीआई एम के जिला सचिव मदन राय, भाकपा माले के जिला संयोजक सुरेश बैठा ने संयुक्त रूप से नेतृत्व किया. कार्यक्रम में रामानेक ठाकुर, रामबाबू सिंह, बैद्यनाथ हाथी, केदार शर्मा, मौजेलाल शर्मा, रामेश्वर मंडल, उमा शंकर सिंह, खेदू महतो, लालचंद साह, मो. ग्यासुददीन, नवीन कुमार सिंह, लक्ष्मी ठाकुर, प्रकाश पूर्वे,अमित कुमार, अधिवक्ता राम पदार्थ चौधरी, राज किशोर राय, शिव कुमार व हसमत अली समेत अन्य थे. रून्नीसैदपुर में मोर्चा के अंचल संयोजक देवेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में बाल किशोर राय, रामाशीष सिंह, गणेश भंडारी, गोनौर पासवान, शंकर पासवान, दारोगा राय, रेणु देवी, रूपचंद पंडित, विनय कुमार, मौजे पासवान, महेंद्र पासवान समेत अन्य थे. पुपरी में भाकपा नेता नवल किशोर राइत के नेतृत्व में रिजवान खां, लक्ष्मी दास, मन्नू प्रसाद, सुरेंद्र पासवान, भरत सिंह व नरेश पासवान समेत अन्य ने प्रदर्शन किया. सोनबरसा में अंचल मंत्री गणेश साह के नेतृत्व में केसरी चौधरी, राजेंद्र सिंह, धर्मपाल कापड, नागेंद्र प्रसाद, राजेश कुमार, मिततल पासवान, संजय कुमार यादव, निर्मला देवी व जमीला खातून समेत अन्य लोग भी मौजूद थे.

– आदित्यानंद

भाजपा नेता पर कार्रवाई

पूर्वी चम्पारण के भाजपा नेता प्रमोद गिरि को पार्टी से निकाल दिया गया है. प्रमोद गिरि कोटवा प्रखण्ड भाजपा के 15 वर्षो से प्रखण्ड अध्यक्ष थे. गिरि ने इस बावत बताया कि पार्टी से निकाले जाने की सूचना उन्हें समाचार पत्र के माध्यम से मिली है. इस संबंध में पार्टी कार्यालय से किसी प्रकार का पत्र या सूचना नहीं दी गई है. उन्होंने बताया कि अखबार में जिलाध्यक्ष का बयान प्रकाशित हुआ था कि प्रमोद गिरि को पार्टी से निष्कासित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई है, जबकि मुझे कोई पत्र नहीं मिला है. उन्होंने पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया. गिरि ने पूर्व में भी पार्टी पर पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दूसरे दलों से आयातित नेताओं को तरजीह देने का आरोप लगाते हुए विरोध किया था. उन्होंनें कहा कि जिला भाजपा पार्टी के नीतियों पर काम नहीं कर रही है. इसके कारण बहुत से कार्यकर्ता क्षुब्ध हैं. ज्ञात हो कि प्रमोद गिरि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवारी का दावा भी कर रहे थे. बकौल गिरि वे चुनाव लड़ेगें क्षेत्र की जनता का यही फैसला है. कई दलों द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया है लेकिन अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है. बिहार के विकास के परिपेक्ष में वह नीतीश कुमार के कार्यो की प्रशंसा करते हैं. न्याय के साथ सामाजिक समरसता और विकास की नीति पर ही नीतीश कुमार बिहार को विकास के प्रगति पथ पर दौड़ाने में सफल रहे हैं. इनकी जदयू के वरिष्ठ नेताओं से वार्ता हो रही है. जल्द फैसला लिया जायेगा.

– राकेश कुमार

अभूतपूर्व राजद बंद ने दिया नया संदेश

पूर्वी चम्पारण में राजद का बिहार बंद पूर्णत: सफल रहा. राजद का यह बिहार बंद अन्य बंद से पूरी तरह अलग था. साथ ही बन्द की सफलता ने यह भ्रम भी समाप्त कर दिया कि राजद का संगठनात्मक ढ़ाचा कमजोर हो गया है. जहां बंदी के पूर्व संध्या पर राजद कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाल कर बंदी की सफलता के लिए सहयोग की मांग की, वहीं सभी व्यवसायिक संगठनों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा. यह पहली बार हुआ. पूर्व में राजद की सभी बंदी डेंडे के बल पर होता था. पहली बार इस बंदी में डंडा नहीं दिखा. वहीं स्कूलों की गाड़ियों, एम्बुलेंस के परिचालन को बाधित नहीं किया गया. पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से बंद को सफल बनाया गया. डॉ शमीम भी भारी संख्या में सहयोगियों के साथ जुटे रहे. महागठबंधन के घटक दलों का भी सराहनीय सहयोग रहा. जदयू जिलाध्यक्ष प्रो. दिनेश चन्द्र प्रसाद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार शुक्ल भी मोर्चा संभाले रहे. कुल मिलाकर इस बंदी ने जहां राजद के मजबूत संगठन का एहसास करा दिया वही राजद के डंडा कल्चर में बदलाव की भी पुष्टि कर दी. बंदी में पूर्व विधायक सहदेव पासवान, पूर्व विधान पार्षद कलावती देवी, अनिरूद्ध सहनी,बजरंगी नारायण ठाकुर. राजेन्द्र राम, एनामुल हक,डॉ राजीव प्रकाश,नसीमा खातून,संजय निराला, गोपालजी जायसवाल, मोख्तार आलम, लालबाबम यादव, मुन्नी लाल यादव, अनिल यादव, विचारी यादव, जंगबहादुर यादव, चांद विद्रोही सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने मुख्य भूमिका निभाई.■

– राकेश कुमार

प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंकगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न

सुबोध कुमार, Director S.T.C., Motihari, वृहत अंकगणित के लेखक

41. एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, शेष का 1/2 भाग पीला और शेष 3.5 से.मी. नीला है। तो पेंसिल की कुल लम्बाई क्या है?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

42. राम अपने कुल धन का 1/4 भाग भोजन पर शेष 1/2 भाग कपड़ा पर खर्च करता है। यदि उसके पास शेष 300 रू. बच जाता है तो प्रारंभ में कितना धन था?
A) 500 B) 700 C) 800 D) 1000

43. एक पुस्तकालय में 60 प्रतिशत पुस्तक अंग्रेजी में, शेष का 60 प्रतिशत हिन्दी में, शेष का 1/3 भाग उर्दू में है। यदि शेष 8000 पुस्तक अन्य भाषा में है, तो हिन्दी में कितनी पुस्तकें है?
A) 60,000 B) 75,000 C) 80,000 D) 90,000

44. मोतिहारी शहर में कुल टी.वी. को $14\frac{2}{7}\%$ सोनी कंपनी का टीवी, शेष का 3/5 भाग सैमसंग का शेष 1/3 भाग एलजी और शेष का 50% अन्य कंपनी का टीवी बिका। यदि सैमसंग का कुल 540 टीवी बिका, तो अन्य कंपनी के कितने टी.वी. बिके?
A) 120 B) 125 C) 130 D) 140

45. एक व्यक्ति का मासिक आय 60,000 रू. है। वह अपने आय का 20% खाने पर शेष का 1/10 भाग किराया पर, शेष का 50% अन्य खर्च है, तो उसका वार्षिक बचत क्या है?
A) 2000 B) 2100 C) 2160 D) 2500

46. एक छात्र अपने पिता से मिले रूपये का 1/3 भाग गणित के पढ़ाई पर शेष 2/3 भाग भौतिकी पर और शेष का 1/3 भाग रसायन के पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि रसायन पर कुल 9000 रू. खर्च करता है तो उसके पास शेष कितना रूपया बचा है?
A) 16000 B) 18000 C) 2000 D) 22000

47. एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला तथा उसके भागीदार को शेष का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भागों में अन्तर 36रू. है तो कुल राशि क्या थी?
A) 256 B) 260 C) 280 D) 250

48. किसी विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग सामाजिक कैंप में भाग लिया। यदि कैंप में कुल 1000 विद्यार्थीयों ने भाग लिया जिसमें 300 छात्राएं थे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है?
A) 235 B) 230 C) 240 D) 250

49. किसी विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/8 भाग सामाजिक कैंप में भाग लिया, तो विद्यालय में कुल कितने भाग विद्यार्थी सामाजिक कैंप में भाग लिया?
A) 13/40 B) 13/80 C) 2/13 D) इनमें से कोई नहीं

50. किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 भाग छात्राएं और शेष छात्र हैं। यदि छात्राओं की संख्या का 2/9 और छात्रों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है?
A) 23/30 B) 23/36 C) 18/49 D) 17/25

SMS द्वारा उत्तर 8002817092 पर भेजें

सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले प्रथम दस विजेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा।

शेष अगले अंक में